



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

खण्ड 41

शिमला, शनिवार, 24 अप्रैल, 1993/4 वैशाख, 1915

संख्या 17

विषय सूची

भाग 1	वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	578—622 तथा 632
भाग 2	वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और फिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	622—626
भाग 3	अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रबल समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, काईनैशियल कमिशनर तथा कमिशनर द्वारा अधिसूचित दावें इत्यादि	626—628
भाग 4	स्थानीय स्वायत शासन, म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया क्षेत्र द्वारा दावायती राज विभाग	—
भाग 5	विधिवितक अधिसूचनाएं और विज्ञापन	628—630
भाग 6	भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन	630—632
भाग 7	भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) को वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं	—
—	अनुपूरक	—

24 अप्रैल, 1993/4 वैशाख, 1915 को समाप्त होने वाले सत्ताह में निम्ननिवित विज्ञप्तियाँ 'भारतीय राजपत्र, हिमाचल प्रदेश' में प्रकाशित हुईः—

विज्ञप्ति की संख्या	विभाग का नाम	विषय
संख्या 3-4/92-ई० एल० एन०-II, दिनांक 12 अप्रैल, 1993.	निर्वाचन विभाग	भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 56/93 (3), दिनांक 23 मार्च, 1993 का अप्रेजी रूपान्तर सहित प्रकाशन।
संख्या 3-25/91-ई० एल० एन०, दिनांक 16 अप्रैल, 1993.	निर्वाचन विभाग	भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 82/हि०प्र-०- वि०८०/१ व २/९० का इसके अप्रेजी रूपान्तर सहित प्रकाशन।
संख्या एल०एस०जी०-ए०(३) १७/९२, दिनांक 16 मार्च, 1993.	स्थानीय स्वशासन विभाग	नगरपालिका समिति, हरीसपुर में इष्टहार और विज्ञापन चिपकाने को विनियमित करना, उपविधि, 1993 का प्रकाशन इसके अप्रेजी रूपान्तर सहित।
No. LLR-E (9)-1/88-Vol.-II (loose), dated 2nd April, 1993.	Law Department	Appointment of Shri N. K. Sharma, Advocate as Advocate-on-record for H. P. Government Litigation work with Supreme Court w.e.f. 24-4-1993.

57
—
se
in
—**भाग 1—वैधानिक नियमों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि****हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट****NOTIFICATIONS***Shimla-1, the 31st March, 1993*

No. HHC/Admin. 6 (23)/74-VIII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, is pleased to declare the District and Sessions Judge, Shimla as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of District and Sessions Judge (Forests), Shimla and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class-III and IV establishment attached to the aforesaid court under head "2014-Administration of Justice" during the leave period of Mrs. Kiran Agarwal, District and Sessions Judge (Forests). Shimla with effect from 19.4.1993 to 5.5.1993 with permission to prefix Sunday falling on 18.4.1993 and to suffix gazetted holiday falling on 6.5.1993, or until she returns from leave.

Shimla-1, the 31st March, 1993

No. HHC/Admin. 6 (23)/74-VIII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, is pleased to declare the Sub-Judge-cum-JMIC (II) Paonta Sahib as Drawing and Disbursing Officer in respect of the court of Sub Judge-cum-Sub Divisional Judicial Magistrate (II), Paonta Sahib and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class-III and IV establishment attached to the aforesaid court under head "2014-Administration of Justice" during the leave period of Shri D.S. Khenal, Sub Judge-cum-S.D.J.M. (I), or until he returns from leave.

Shimla-1, the 31st March, 1993

No HHC/Admin. 6 (23)/74-VIII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under rule 1.26 of Himachal Pradesh Financial Rules, 1971, Volume-I, is pleased to declare Shri George, Additional Chief Judicial Magistrate-cum-Sub Judge 1st Class, Dharamshala as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Sub Judge-cum-Judicial Magistrate (II), Dharamshala and also the Controlling Officer for the purpose of T. A. etc. in respect of the Class-III and IV establishment attached to the aforesaid Court under head "2014-Administration of Justice" till the new incumbent is transferred and posted there.

By Order,
Sd/-
Additional Registrar (Admn.)

हिमाचल प्रदेश सरकार**प्राधिक विभाग (नि-1)****अधिसूचनाएं***शिमला-2, 4 दिसम्बर, 1991*

संख्या का० (नि-1)-बी० (15)-3/79.—इस विभाग की सम मंथ्या अधिसूचना दिनांक 1-1-91, त्रिम द्वारा हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के सर्वर्णके पदों का निर्धारण किया गया है, का क्रम जारी रखते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सहर्ष आदेश करते हैं कि उप मण्डलाधिकारी (नागरिक) के 39 पदों में से जिन में, 3 पद मण्डलाधिकारी (नागरिक) के भी सम्मिलित हैं का पदनाम 1-1-91 में परियोजना अधिकारी एवं उप मण्डलाधिकारी (ना०) भरपूर/काजा/पर्सी होंगा।

संख्या पर (ए०-१)-ई० (३)-९/९१.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की अधिसूचना संख्या पर (ए०-१)-बी० (६-०-१)-९१ दिनांक 30-८-९१ में आंशिक संशोधन करते हुए श्री जी० के० श्रीवास्तवा, एच०ए०ए०, का भा-अर्जन अधिकारी (लोक निर्माण-I) शिमला के पद पर स्थानान्तरण तैनाती के आदेशों को सहर्ष रद्द करने के आदेश देते हैं। श्री जी० के० श्रीवास्तवा, एच०ए०ए० एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, धर्मशाला के पद पर ही तैनात रहेंगे।

शिमला-171002, 10 दिसम्बर, 1991

संख्या का० (नि-1)-बी० (२)-२/८८.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर श्री ईश्वर दास, अवर सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार को (जिन्हें उप-सचिव नामांदिष्ट किया गया है) 1-12-1991 से नियमित आधार पर उप-सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार के पद पर ₹ 3700-5000 के बेतनमान ₹ 400/- प्रतिमाह विशेष बेतन सहित पदोन्नत करने के सहर्ष आदेश करते हैं।

श्री ईश्वर दास 1-12-1991 से 2 वर्ष की परियोगिता पर रहेंगे।

राज्यपाल, यह भी सहर्ष आदेश करते हैं कि श्री ईश्वर दास उपरोक्त पदोन्नति पर उप-सचिव (मुख्य मन्त्री तथा जनजातीय विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार के पद पर ही कार्यरत रहेंगे।

शिमला-171002, 17 दिसम्बर, 1991

संख्या 1-15/73-कार्मिक-I.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सहर्ष श्री सी० पी० पाण्ड, भा० प्र० से० (हि० प्र०-८०) को विदेशी प्रशिक्षण से लौटने पर सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा अधिकारी के पद पर तैनात करने के लोकहित में तत्काल से आदेश देते हैं।

शिमला-2, 18 दिसम्बर, 1991

संख्या पर (ए०-१)-ए० (४)-१/९१.—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के अनुसार, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, श्री बी० पी० मल्होत्रा, स्थाई वरिष्ठ बास्तुकार, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को मुख्य बास्तुकार, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के पद पर बेतनमान ₹ 5900-6700 में नियमित ₹ 1 से पदोन्नति करने के सहर्ष तत्काल से आदेश करते हैं।

2. श्री बी० पी० मल्होत्रा 2 वर्ष तक परिवीक्षा काल पर रहेंगे।

शिमला-2, 18 दिसम्बर, 1991

संख्या पर (ए०-१)-ई० (३)-९/९१.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लोक हित में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के नियन्त्रित करने के अधिकारियों के स्थानान्तरण तथा तैनाती आदेश सहर्ष तत्काल से करने हैं—

1. श्री जी० के० श्रीवास्तवा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, धर्मशाला को स्थानान्तरित करके मण्डलाधिकारी, धर्मशाला के सहायक आयुक्त के पद पर तैनात किया जाता है।

2. श्री टी० एन० गर्मी, मण्डलाधिकारी धर्मशाला के सहायक आयुक्त को स्थानान्तरित करके क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, धर्मशाला तैनात किया जाता है।

शिमला-2, 21 दिसम्बर, 1991

संख्या पर (नि-1)-बी० (२)-२/९०.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पर (ए०-१) बी० (२) ५/८५, दिनांक 10-९-८६ का क्रम जारी रखते हुए तथा उसमें

दी गई गर्ने को यथास्थित रखते हुए श्री करनार तिह मिहाम को दिनांक 20-5-85 से 22-1-86 तक पूर्णतया कार्यनिक तौर पर ग्रवर सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, रु 0 1400-1850 जमा रु 200/- प्रतिमास विशेष बेतन (दिनांक 1-1-1986 में रु 0 3000-4500 जमा रु 0 400/- प्रतिमास विशेष बेतन) के बेतनमात्र के पद पर पदान्वत करने के सहर्ष आदेश करते हैं।

श्री अम्बा चरण को भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री शान्ति कुमार के साथ आगामी आदेशों तक तेजात करने के महर्ष आदेश करते हैं।

आदेश ग्राम,
मधु सदन मुख्यमंज्ञी,
मुख्य सचिव।

श्री कश्त्रार तिह मिहाम दिनांक 23-1-86 में 30-6-86 तक पहुँचे ही ग्रवर सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार पदान्वत रहे हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/
मुख्य सचिव।

शिमला-2, 23 दिसम्बर, 1991

संख्या का 0 (नि-1)-ए 0 (2)-1/86.—राजपत्र, हिमाचल प्रदेश फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कु 0 विवेदित नेपी, भा 0 प्र० से 0 (पर्वतीयाओं), निरमोर जिला को कार्यकारी दण्डाधिकारी नियुक्त करने तथा कार्यकारी दण्डाधिकारी की शक्तियों को तत्काल में प्रयोग करने के महर्ष आदेश देते हैं। यह शक्तियों के अन्दर प्रयोग में लाइ जाएगी जो कि गृह विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अनुदेशों मेंब्या होम-बी(बी) 12-5/84, दिनांक 4-12-1984 तथा 28-12-1984 के अनुस्य होंगी।

हस्ताक्षरित/-
विशेष सचिव।

शिमला-171002, 28 दिसम्बर, 1992

संख्या 3-34/66-डीपी-नियुक्ति.—भारत के राष्ट्रपति, महर्ष श्री अमर नाथ विद्यार्थी, भा 0 प्र० से 0 वितायुक्त एवं सचिव (आवकारी द्वा०) कराधान, जननातीय, खाता एवं आपूर्ति तथा सहकारिता) हिमाचल प्रदेश सरकार के 11-1-1993 से 19-1-1993 के प्राक्तिक व वैकल्पिक अवकाश के दोरान वर्ष 1990-93 की रियायती याता अवकाश सुविधा अपने परिवार के आश्रित सदस्यों गहिर शिमला से बंगलौर तथा वारसी की अनुमति प्रदान करते हैं।

भारत के राष्ट्रपति यह भी सहर्ष आदेश करते हैं कि श्री अमर नाथ विद्यार्थी, भा 0 प्र० से 0 वितायुक्त एवं सचिव गवर्नरी तथा कराधान, जन जातीय, खाता एवं आपूर्ति तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की उपरोक्त अवकाश अवधि उक्त कार्यकारी एस 0 एस 0 सिद्ध, भा 0 प्र० से 0 वितायुक्त एवं सचिव (लोक निर्माण); हिमाचल प्रदेश सरकार अतिरिक्त रूप से देंगे।

शिमला-171002, 28 दिसम्बर, 1992

संख्या 2-25/64-डी पो-नियुक्ति.—भारत के राष्ट्रपति, श्री अमर सह. भा 0 प्र० से 0, वितायुक्त एवं सचिव (विकास), हिमाचल प्रदेश रकार के पक्ष ने इस विभाग के अधिसूचना समसंघक दिनांक 17-1-1992 द्वारा स्वीकृत किये गये 13 दिनों के लियांतरित विकाश दिनांक 11-1-1993 से 23-1-1993 को सहर्ष रह करने से स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री अत्तर सिंह, भा 0 प्र० से 0 के पक्ष में खण्ड वर्ष 1990-93 के प्रदान की गई रियायती याता अवकाश सुविधा को भी रह सकती जाती है।

हस्ताक्षरित/-
मुख्य सचिव।

(सचिवालय प्रशासन सेवाओं-1)

शिमला-171002, 28 दिसम्बर, 1992

संख्या कार्यक्रम (स 0 प्र०-1) बी (6)-3/89.—भारत के राष्ट्रपति, हिमाचल प्रदेश सचिवालय के विशेष निजि सचिव

(नि-1)
शिमला-171002, 29 दिसम्बर, 1992

संख्या 10-3/73-डी पी-नियुक्ति.—भारत के राष्ट्रपति, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कु 0 विवेदित नेपी, भा 0 प्र० से 0 (पर्वतीयाओं), निरमोर जिला को कार्यकारी दण्डाधिकारी नियुक्त करने तथा कार्यकारी दण्डाधिकारी की शक्तियों को तत्काल में प्रयोग करने के महर्ष आदेश देते हैं। यह शक्तियों के अन्दर प्रयोग में लाइ जाएगी जो कि गृह विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अनुदेशों मेंब्या होम-बी(बी) 12-5/84, दिनांक 4-12-1984 तथा 28-12-1984 के अनुस्य होंगी।

शिमला-171002, 29 दिसम्बर, 1992

संख्या 10-2/72-डीपी-नियुक्ति-2.—भारत के राष्ट्रपति फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अब्दुल खान, भा 0 प्र० से 0, तहसीलदार जसवां, जिला कांगड़ा को कार्यकारी दण्डाधिकारी नियुक्त करने तथा कार्यकारी दण्डाधिकारी की शक्तियों को तत्काल से प्रयोग करने के सहर्ष आदेश देते हैं। यह शक्तियों जमकां तहसील की स्थानीय सीमाओं के अन्दर प्रयोग में लाइ जाएगी जो कि गृह विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अनुदेशों मेंब्या होम-बी(बी) 12-5/84, दिनांक 4-14-1984 तथा 28-12-1984 के अनुस्य होंगी।

शिमला-171002, 30 दिसम्बर, 1992

संख्या 10-2/72-डी पी-नियुक्ति.—भारत के राष्ट्रपति, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कृष्ण देव जापी, महावक आयकूत, मण्डला-कुकुर, कांगड़ा, धमंशाला को कार्यकारी दण्डाधिकारी नियुक्त करने तथा कार्यकारी दण्डाधिकारी की शक्तियों को तत्काल से प्रयोग करने के सहर्ष आदेश देते हैं। यह शक्तियों धर्मगाना की स्थानीय सीमाओं के अन्दर प्रयोग में लाइ जाएगी जो कि गृह विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अनुदेशों मेंब्या होम-बी(बी) 12-5/84, दिनांक 4-12-1984 तथा 28-12-1984 के अनुस्य होंगी।

शिमला-171002, 30 दिसम्बर, 1992

संख्या का (नि-1)-ए 0 (2)-2/90.—भारत के राष्ट्रपति, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री बी 0 एल 0 राणा, नायक तहसीलदार (ग्रामीण), जिला शिमला को कार्यकारी दण्डाधिकारी नियुक्त करने तथा कार्यकारी दण्डाधिकारी की शक्तियों को तत्काल से प्रयोग करने के सहर्ष आदेश देते हैं। यह शक्तियों धर्मगाना की स्थानीय सीमाओं के अन्दर प्रयोग में लाइ जाएगी जो कि गृह विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अनुदेशों मेंब्या होम-बी(बी) 12-5/84, दिनांक 4-12-1984 तथा 28-12-1984 के अनुस्य होंगी।

शिमला-171002, 30 दिसम्बर, 1992

संख्या का (नि-1)-ए 0 (2)-2/90.—भारत के राष्ट्रपति, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कौशिं शर्मा, नायक तहसीलदार, भृत्यवस्था बूत ठेला, जिला शिमला को कार्यकारी दण्डाधिकारी नियुक्त करने तथा कार्यकारी दण्डाधिकारी की शक्तियों को तत्काल से प्रयोग करने के सहर्ष आदेश देते हैं। यह शक्तियों बृत ठेला की स्थानीय सीमाओं के अन्दर प्रयोग में लाइ जाएगी जो कि गृह विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अनुदेशों मेंब्या होम-बी(बी) 12-5/84, दिनांक 4-12-1984 तथा 28-12-1984 के अनुस्य होंगी।

57

हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अनुदेशों संख्या होम-बी (बी) 12-5/84 के अनुरूप होगी।

58

शिमला-171002, 30 दिसंबर, 1992

संख्या का (नि-1)-ए(2)-2/90.—भारत के राष्ट्रपति, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री चंद्र राम चौहान, नाथव तहसीलदार, जूना, जिला शिमला को कार्यकारी दण्डाधिकारी नियुक्त करने के तथा कार्यकारी दण्डाधिकारी की शक्तियों को तत्काल से प्रयोग करने के सहर्ष आदेश देते हैं। यह शक्तियां जूना की स्थानीय सीमाओं के अन्दर प्रयोग में लाई जाएंगी जो कि गृह विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अनुदेशों संख्या होम-बी (बी) 12-5/84, दिनांक 4-12-1984 व 27-12-1984 के अनुरूप होंगी।

शिमला-171002, 1 जनवरी, 1993

संख्या 3-29/71-डीप्र०-०नियुक्ति—भारत के राष्ट्रपति, श्री बी० के ० बन्धल, भा०प्र० से०, नियुक्त, भू-प्रभिलेख, हिमाचल प्रदेश के पक्ष में ८ दिनों का अनित अवकाश दिनांक 1-1-1993 से ४-१-1993 तक राजपत्रिन अवकाश दिनांक 31-12-1992 व 9, 10-१-1993 को जोड़ने की अनुमति सहित महर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भारत के राष्ट्रपति यह भी महर्ष आदेश करते हैं कि श्री बी० के ० बन्धल, भा०प्र० से० की उपरोक्त अवकाश अवधि के दौरान उनका कार्य श्री हीरा आल नाशाव, भा०प्र० से०, पंजीयक, सहकारी सभाएं, हिमाचल प्रदेश अपने कार्य के अतिरिक्त देखें।

श्री बी० के ० बन्धल, भा०प्र० से० के पक्ष में खण्ड वर्ष 1990-93 की रियावती यात्रा अवकाश सुविधा उनके परिवार के आवित सदस्यों सहित विमन प्रकार से अवैति करने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

क्रम	नाम/मम्बन्ध	यात्रा आरम्भ संख्या जहां तक	संख्या जहां तक अपने करवा है
1.	महर्ष	31-12-1992	शिमला से भुवनेश्वर तथा बापसी।
2.	पंजी	15-12-1992	शिमला से गोआ तथा बापसी।
3.	कु० पूजा (बेटी)	23-12-1992	लखनऊ से गोआ तथा बापसी दिल्ली।
4.	निशान्न बन्धल (बंदा)	21-12-1992	दिल्ली से गोआ तथा बापसी दिल्ली।

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव।

शिमला-171002, 1 जनवरी, 1993

संख्या 1-39/72-कामिक-खण्ड-2.—भारत के राष्ट्रपति, श्री के० नाल, भा०प्र० से० (हि०प्र०-१९७३), बिंगे कार्य अधिकारी (पुनिम रूल), हिमाचल प्रदेश मरकार को स्थानान्तरित करके तत्काल में मण्डलायुक्त, मण्डी मण्डल, मण्डी तेनात करने के सहर्ष आदेश देते हैं। वे कुमारी विमला मण्डल, भा०प्र० से०, प्रबन्ध निवेशक, हि०प्र० यज्य लघु उद्योग तथा नियमन निगम को इस पद के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करेंगे।

शिमला-171002, 1 जनवरी, 1993

संख्या 1-39/72-कामिक-खण्ड-2.—भारत के राष्ट्रपति, श्री के० नाल, भा०प्र० से० (हि०प्र०-१९७३), बिंगे कार्य अधिकारी (पुनिम रूल), हिमाचल प्रदेश मरकार को सारांशीय प्रशासनिक भेजा

के सुपरिटेंडेंट वेतनमान रुपये 5900—8700 में दिनांक 8-7-1993 से पदोन्नत करने के सहर्ष आदेश देते हैं।

भारत के राष्ट्रपति, श्री के० नाल, भा०प्र० से० (हि०प्र०-१९७३) को दिनांक 23-11-1989 अर्थात् उस तिथि से जिस तिथि उनके कनिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को सुपरिटेंडेंट वेतनमान दिया गया है, नोशनल पदोन्नति देने के भी महर्ष आदेश देते हैं।

शिमला-171002, 5 जनवरी, 1993

संख्या 5-1/71-कामिक-1.—भारत के राष्ट्रपति सहर्ष श्रीमती आज स्वरूप भा०प्र० से०, (हि०प्र० : 73) आयुक्त एवं सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार जो कि 25-८-1993 तक अध्ययन अवकाश पर हैं की सेवाएं केन्द्र सरकार के अधीन वर्तार संयुक्त सचिव, भारत सरकार के यथा सामाजिक एवं खेलकूद विभाग के वर्ष पर उनके कार्य भारत संसालन की नियम से प्राप्तिनियुक्ति के आधार पर द्योने वाले आदेश करते हैं।

आदश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
मुख्य सचिव।

शिमला-171002, 6 जनवरी, 1993

संख्या 3-42/74-डीपी-नियुक्ति—इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 30-11-1992 का अधिक्रमण करते हुए भारत के राष्ट्रपति, श्री रवि ढीगरा, भा०प्र० से०, मण्डलायुक्त शिमला बण्डल, शिमला के पक्ष में 20 दिनों का अनित अवकाश दिनांक 11-१-1993 से 30-१-1993 तक तथा राजपत्रिन अवकाश दिनांक 9, 10-१-1993 व 31-१-1993 को जोड़ने की अनुमति सहित सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भारत के राष्ट्रपति यह भी सहर्ष आदेश करते हैं कि श्री रवि ढीगरा, भा०प्र० से० की उपरोक्त अवकाश अवधि के दौरान उनका कार्य श्री एस० के० सूद, भा०प्र० से०, आयुक्त एवं सचिव (विचारी एवं जन स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कार्य के अतिरिक्त करें।

श्री रवि ढीगरा, भा०प्र० से० के पक्ष में खण्ड वर्ष 1990-93 के दौरान शिमला से आगरा तक तथा बापसी अपने परिवार के आवित सदस्यों सहित उपरोक्त अवकाश के दौरान रियावती यात्रा अवकाश सुविधा अवैति करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षरित/-
मुख्य सचिव।

शिमला-171002, 6 जनवरी, 1993

संख्या का (नि-1)-ए(2)-1/86.—भारत के राष्ट्रपति, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री बलदेव राम ठाकुर, तहसीलदार, धमरवी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को कार्यकारी दण्डाधिकारी नियुक्त करने तथा कार्यकारी दण्डाधिकारी की शक्तियों को तत्काल से प्रयोग करने के सहर्ष आदेश देते हैं। यह शक्तियां बिलासपुर तहसील की स्थानीय सीमाओं के अन्दर प्रयोग में लाई जाएंगी जो कि गृह विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अनुदेशों संख्या होम-बी(बी) 12-5/84, दिनांक 4-12-1984 तथा 28-12-1984 के अनुरूप होंगी।

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव।

शिमला-171002, 6 जनवरी, 1993

संख्या 3-9/74-डीपी-नियुक्ति—इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 26-११-1992 में आधिक संशोधन करते हुए भारत के राष्ट्रपति सहर्ष आदेश करते हैं कि श्री योगेश खन्ना,

भा० प्र० मे०, आयुक्त एवं मचिव (प्रशासनिक सुधार तथा प्रणिक्षण), तथा अतिरिक्त कार्यमार्ग आयुक्त एवं मचिव (कैफियत तथा मचिवालय प्रशासनिक नियंत्रण, हिमाचल प्रदेश सरकार व प्रबन्ध नियंत्रण, हिमाचल प्रदेश ग्रोवींग क्षेत्र का अधिकार तिमाही नियम, हिमाचल प्रदेश के अधिकार अवधारणा दिनांक 11-1-1993 से 23-1-1993 के दौरान उनका कार्य और प्र० मि० मित्रा, भा० प्र० मे०, विशेष सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार अतिरिक्त रूप से दख्खणे।

3. भारत के राष्ट्रपति, श्री रवि दीमरा, भा० प्र० मे० मण्डलाद्दक्षिण शिमला मण्डल के अधिकार अवधारणा के दौरान वित्त कार्य अतिरिक्त रूप से श्री ए० स० के० सूद, भा० प्र० मे०, आयुक्त एवं मचिव (सिवार्ड एवं जन स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश सरकार को मौष्ण गवा है के कार्य को 27-1-1993 से 30-1-1993 तक श्री ए० प्र० मे० परमार, भा० प्र० मे०, प्रबन्ध नियंत्रण, हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम की अनुमति के भी सहर्ष आदेश देने हैं।

हस्ताक्षरित/- मुख्य मचिव।

(मचिवालय प्रशासन सेवाएँ-1)

शिमला-171002, 6 जनवरी, 1993

संख्या का (म० प्र०-१) बी(२)-२/९२--भारत के राष्ट्रपति, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित अधीकार प्रेड-II को अनुभाग अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) वेतनमान रुपये 2200-50-2400-60-2700-75-3000-100-4000 जमा रुपये 200/- विषेष वर्तन के पद पर मचिवालय में पूर्णतया अस्थाई तौर पर तत्काल में पदोन्नत करने के सहर्ष आदेश दर्शाये हैं:—

1. श्री नोहन लाल गुप्ता
2. श्री योगिन्द्र सिंह

यह पदोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील नं 2615/87, श्री गृह लाल नेहीं तथा अन्य वनाम भगत राम कपरेट और अन्य तथा माननीय प्रशासनिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश में दायर अपील नं ४/१९८८, श्री वंधु राज और अन्य वनाम हिमाचल प्रदेश राज्य तथा अन्य तथा अपील नं १६१/१९८८ श्री ज्योति स्वरूप और अन्य वनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य के अन्तिम निर्णय पर निर्भर हायी।

इस पदोन्नति के कलहरूप उपरोक्त अधिकारी का इस पद पर नियुक्त रहने, वरिष्ठता वा नियमित पदोन्नति का अधिकार नहीं हायी।

के आदेश में
हस्ताक्षरित
आयुक्त एवं मचिव।

(नि-१)

शिमला-171002, 7 जनवरी, 1993

संख्या 3-३/३-३-डी००१०-नियुक्ति.—इस विभाग द्वारा अधिसूचना सम से० दिनांक 22-१२-१९९२ में आणिक संशोधन करते हुए भारत के राष्ट्रपति सहव आदेश करते हैं कि श्री पी० आई० सूद, भा० प्र० से०, सदस्य (वित्त एवं लेखन सामग्री), हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अतिरिक्त कार्यमार्ग मण्डलायुक्त, कर्मज्ञ मण्डल, धर्मज्ञाला के अधिकार अवधारणा दिनांक 1-१-१९९३ से १८-२-१९९३ के दौरान उनका कार्य अधिकार, हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड अतिरिक्त रूप से देखेंगे।

शिमला-171002, 7 जनवरी, 1993

संख्या 3-४/७२-डी००१०-नियुक्ति.—भारत के राष्ट्रपति, श्री ए० स० के० सूद, भा० प्र० मे०, आयुक्त एवं मचिव (नियाई एवं जनस्वास्थ्य, पर्यटन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी), हिमाचल प्रदेश सरकार के पक्ष में २५ दिनों का अधित अवधारणा दिनांक 27-१-१९९३ से २०-२-१९९३ तक तथा राजपत्रित अवधारणा दिनांक २४-१-१९९३ से २६-१-१९९३ व २१-२-१९९३ को जोड़ने की अनुमति सहित सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. भारत के राष्ट्रपति वह भी सहर्ष आदेश करते हैं कि श्री ए० स० के० सूद, भा० प्र० से० की उपरोक्त अवधारणा अधिकार के दौरान उनका कार्य श्री ए० स० ए० परमार, भा० प्र० से०, प्रबन्ध नियंत्रण, हिमाचल प्रदेश, राज्य वित्तीय नियम, शिमला एवं आयुक्त एवं मचिव (गृह एवं सतकंता), हिमाचल प्रदेश सरकार अतिरिक्त रूप से देखेंग।

शिमला-171002, 7 जनवरी, 1993

नंदा ३-५/७२-डी००१०-नियुक्ति.—भारत के राष्ट्रपति, श्री ए० स० परमार, भा० प्र० मे०, प्रबन्ध नियंत्रण, हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय नियम एवं अतिरिक्त कार्यमार्ग आयुक्त एवं मचिव (गृह एवं सतकंता) हिमाचल प्रदेश सरकार के पक्ष में १३ दिनों का अधित अवधारणा दिनांक 11-१-१९९३ से २३-१-१९९३ तक तथा राजपत्रित अवधारणा दिनांक ९, १०-१-१९९३ व २४, २५, २६-१-१९९३ को जोड़ने की अनुमति महिने सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. भारत के राष्ट्रपति वह भी सहर्ष आदेश देने हैं कि श्री ए० स० परमार, भा० प्र० मे० के उपरोक्त अवधारणा के दौरान उनका कार्य श्री ए० स० के० सूद, भा० प्र० मे०, आयुक्त एवं मचिव (नियाई एवं जनस्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश सरकार अतिरिक्त रूप में देखेंगे।

3. श्री ए० स० परमार, भा० प्र० मे० के पक्ष में १९९०-९३ की रियायत याकार अवधारणा सुविधा देखने परिवार के आधित मदस्यों महिने शिमला में गोआ तक तथा वापसी की उपरोक्त अवधारणा के दौरान व्यतीत करने की अनुमति प्रदान दी जाती है।

शिमला-171002, 8 जनवरी, 1993

संख्या ३-१५/७१-डी००१०-नियुक्ति.—इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना समसंबद्धक दिनांक 27-१२-१९९२ में आविक संशोधन करते हुए, भारत के राष्ट्रपति, कुमारी परमिन्दर हीरा, भा० प्र० मे०, आयुक्त एवं मचिव (कल्याण, अम, मुद्रण एवं लेखन सामग्री), हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अतिरिक्त कार्यमार्ग मण्डलायुक्त, कर्मज्ञ मण्डल, धर्मज्ञाला के अधित अवधारणा दिनांक १८-१-१९९३ से ६-२-१९९३ के दौरान उनका कार्य निम्न अधिकारियों वा अपने कार्य के अतिरिक्त संरेख के सहर्ष आदेश देते हैं:—

- (१) श्री योगेश खन्ना, भा० प्र० मे० आयुक्त एवं मचिव (प्रशासनिक सुधार एवं प्रणिक्षण), हिमाचल प्रदेश सरकार दिनांक 27-१-१९९३ से ६-२-१९९३ तक आयुक्त एवं मचिव (कल्याण, अम, मुद्रण तथा लेखन सामग्री), हिमाचल प्रदेश सरकार के रूप में।
- (२) श्री के० लाल, भा० प्र० मे०, मण्डलायुक्त, मण्डी मण्डल, मण्डा, दिनांक १८-१-१९९३ से ६-२-१९९३ तक दौरान मण्डलायुक्त, कांगड़ा मण्डल, धर्मज्ञाला के रूप में।
- (३) श्री पी० मित्रा, भा० प्र० मे०, विशेष सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार दिनांक १८-१-१९९३ से २३-१-१९९३ के दौरान विशेष सचिव (कल्याण, अम, मुद्रण तथा लेखन सामग्री), हिमाचल प्रदेश सरकार के रूप में।

हस्ताक्षरित/- मुख्य मचिव।

शिमला-171002, 12 जनवरी, 1993

संख्या का (नि-१)-बी (३)-२७/७८-११—इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना समसंबद्धक दिनांक 27-११-१९९२ का कम जारी रखते हुए, भारत के राष्ट्रपति, श्रीमती सरोजनी ठाकुर, भा० प्र० मे०, विशेष सचिव (कृषि), हिमाचल प्रदेश सरकार के २३ दिनों के अधित अवधारणा दिनांक १-१-१९९३ से २३-१-१९९३ तक व्यतीत करने के लिए दिनांक ३०-१२-१९९२ (प्रपराहन) को दिल्ली में कार्यमार्ग छोड़ने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

हस्ताक्षरित/- आयुक्त एवं मचिव।

शिमला-171002, 14 जनवरी, 1993

(नि-0-II)

57

--

92

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NOTIFICATIONS

Fairlawns, Shimla-171012, the 21st December, 1987

No. HIPA (Exam.) 5/74-XII.—The result of the departmental examination of the Excise and Taxation Inspectors in the Excise and Taxation Department of Himachal Pradesh Government held during October, 1987 is notified as below:—

Sl. No.	Name, designation & Address	Roll No.	S U B J E C T S							Papers in which the officer has already passed			Papers in which the officer must pass in order to complete the Deptt. Exam.	
			Law of Cri- mes	Excise Law	Law Relat- ing to Allied Taxes	Prop- erty Tax Law & Prac- tice	Sales Tax Law & Prac- tice	Book Keep- ing & General Commer- cial Know- ledge	Landa Script (Amrit- sari or Maha- jani)	Session	Roll No.	Papers		
1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
S/Shri														
1.	Rajesh Kumar Sharma, ETI, C.L.B.P. Mehatpur, Distt. Una.	2201	—	—	Pass	—	—	Fail	—	9/86 4/87	1106 1605	5 1,2,4,7	3,6	
2.	Ram Sarup, ETI, M.P. Barrier, Kandrori, Distt. Kangra (H. P.)	2202	—	Pass	—	Fail	—	Fail	Pass	4/87	1617	1,3,5	4, 6	
3.	Naresh Gupta, ETI, V & P.O. Nupur, Naizpur (Kangra).	2203	Pass	—	—	—	—	Pass	—	9/86 4/87	1113 1613	5, 7 2,3,4	—	
4.	Parshotam Chand, ETI, M.P. Barrier, Behrai Distt. Sirmaur.	2204	—	Pass	—	—	—	Fail	—	9/86 4/87	1110 1618	3,4,5 1,7	6	
5.	Bhagi Rath Dhalaria, ETI, M. P. Barrier Tunu-Hatti, Distt. Chamba.	2205	Fail	Fail	Fail	Fail	Fail	Fail	Pass	—	—	—	1 to 6	
6.	Rajinder Prasad, ETI, M. P. Barrier Dharwal.	2206	A	A	—	—	A	A	—	4/86 4/87	1414 1619	3, 7 4	1,2,5,6	
7.	Chhantan Gutuk, ETI, Pooh Circle at Pooh, Distt. Kinnaur.	2207	A	A	—	A	—	A	—	9/86	1101	3,5, 7	1,2,4,6	
8.	Manoj Kumar, ETI, M. P. Barrier Govindghat, Distt. Sirmaur.	2208	A	A	A	A	A	A	—	9/86	1114	7	1 to 6	
9.	Yog Raj Sharma, ETI, C/o A. E. & T. C. Bilaspur.	2209	Pass	Fail	Pass	Fail	Fail	Fail	Fail	—	—	—	2, 4, 5, 6, 7.	
10.	Santosh Kumar Sharma, ETI, Katsog, Distt. Mandi.	2210	—	Pass	—	—	—	—	—	11/82 7/85	2519 2507	3,4,5,6,7 1	—	
11.	Surinder Singh Jamwal, ETI, M/s Rangar Breweries Ltd., Mehatpur, Distt. Una.	2211	A	A	A	A	A	A	A	—	—	—	1 to 7	583

1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12.	Parshotam Ram, ETI, M. P. Barrier Kandwal, Teh. Nurpur, Distt. Kangra.	2212	—	Fail	Pass	—	—	—	—	4/86 9/86	1410 1119	1,4,6 5,7	2	
13.	Rajinder Parshad Sharma, ETI, M. P. B. Parwanoo, Distt. Solan.	2213	—	Fail	Pass	—	—	A	—	4/86 9/86	1417 1118	1,4 7	2,6	
14.	Sham Lal Negi, ETI, M. P. B. Parwanoo, Distt. Solan.	2214	—	Fail	—	—	—	Fail	—	4/83 4/86 9/86 4/87	7817 1418 1117 1610	3,5 1 7 4	2,6	
15.	Ajay Kumar Awasthi, ETI, M.P. B. Parwanoo, Distt. Solan.	2215	—	Fail	Fail	—	—	Fail	—	4/86 9/86 4/87	1419 1116 1608	4,5 7 1	2,3,6	
16.	Mohar Singh Hitashi, ETI, M.P. B. Parwanoo, Distt. Solan.	2216	—	Fail	Pass	—	—	Fail	—	9/86	1115	5,7	2,6	
17.	Amar Nath, ETI, M. P. Barrier Goalthi, Bilaspur.	2217	—	—	Pass	—	—	—	—	1/85 7/85 9/86	2504 2515 1109	5,6 2,4,7 1	—	
18.	Gopal Krishan Mehta, E T I, M. P. Barrier, Santokhgarh, Distt. Una.	2218	Fail	Fail	—	—	—	Fail	A	—	4/79	132	3,4,7	1,2,5,6
19.	Pratap Chauhan, ETI, Solan Brewery, Distt. Solan.	2219	—	—	—	—	—	Fail	—	9/79 7/85 4/86	1527 2513 1422	2,3,5 7 1,4	6	
20.	Sher-Singh Sidhta, ETI, M. P. B. Bahral, Distt. Sirmaur, H. P.	2220	—	—	Fail	—	—	Fail	—	9/86 4/87	1105 1604	1,4,5,7 2	2,6	
21.	Nag Singh, ETI, Tehog, Distt. Shimla	2221	A	A	A	A	A	A	A	—	—	—	1 to 7	

NOTES :—

(i) 'A' indicates 'Absent'.

(ii) Every possible care has been taken in compiling information given in column Nos. 8, 9, 10 & 11. It is, however, possible that some mistake therein may have occurred inadvertently. All concerned are therefore requested to check the aforesaid information and to bring to the notice of the Board any mistake found therein.

Sd/-

(MRS. SHANTA CHAUHAN),
Secretary,
H. P. Board of Departmental Examinations,
Fairlawn, Shimla-171012.

No. HIPA (Exam) 59/80-VI.—The result of the Himachal Pradesh State Electricity Board Supervisory Accounts Service (Part-II) Examination held during the month of April, 1992 is hereby notified as below:—

Sl. No.	Name and Designation with place of posting	Roll No. assigned	P A P E R S							
			Paper V Precis and Draft		Paper VI Advance Accounting and Auditing		Paper VII Industrial and Com- mercial Laws		Paper VIII Accounts Rules and Procedures	
			Maximum Marks 150	Marks obtained with %age	Maximum Marks 200	Marks obtained with %age	Maximum Marks 100	Marks obtained with %age	Maximum Marks 200	Marks obtained with %age
1	2	3	4	5	6	7				
1.	Shri Subhash Chander, Divisional Accountant, Electrical Division H. P. S. E. B., Jawali, District Kangra (H. P.).	929001	—	94** (47%) Fail	—	—	—	—	—	—
2.	Shri Krishan Singh Rana, Divisional Accountant, Office of the Executive Engineer, Baner Construction Division, H. P. S. E. B., Jia, District Kangra (H. P.).	929002	39 (26%) Fail	52 (26%) Fail	39 (39%) Fail	96 (48%) Fail	—	—	—	—
3.	Shri Sudarshan Kumar, Divisional Accountant, Power House Civil Maintenance Division, H. P. S. E. B., Bhabanagar.	929003	50 (33.3%) Fail	98 (49%) Fail	40 (40%) Fail	80 (40%) Fail	—	—	—	—
4.	Shri O. P. Kaushal, Divisional Accountant, Office of the Executive Engineer, M & T Division, H. P. S. E. B., Sundernagar-174 402 (H. P.).	929004	—	75 (37.5%) Fail	—	—	—	—	—	—
5.	Shri D. R. Sharna, Divisional Accountant, Office of the Chief Accounts Officer, F & A Wing (Pay Fixation Section), H. P. S. E. B., Vidyut Bhavan, Shimla-171 004.	929005	—	—	—	—	—	—	—	97** (48.5%) Fail
6.	Shri Baldev Raj Gupta, Divisional Accountant, Office of the Executive Engineer, Electrical Division, Sarkaghat, District Mandi (H. P.).	929006	A	A	A	A	A	A	A	A

** Is required to obtain 60% marks in the next examination.

1	2	3	4	5	6	7
7.	Shri Chhaju Ram Verma, Divisional Accountant, Electrical Division, H. P. S. E. B., Nahan.	929007	68 (45.3%) Fail	60 (30%) Fail	—	—
8.	Km. Suneta Sharma, Divisional Accountant, Transmission Division, H. P. S. E. B., Saproon Solan, Distt. Solan (H. P.).	929008	—	118** (59%) Fail	—	—
9.	Shri Krishan Chand Verma, Divisional Accountant, Electrical Division, H. P. S. E. B., Kumarsain, District Shimla (H. P.).	929009	A	A	A	A
10.	Shri Mehar Chand Sharma, Divisional Accountant, Office of the Chief Accounts Officer, Finance & Accounts Wing, H. P. S. E. B., Vidyut Bhawan, Shimla-171 004.	929010	—	107** (53.5%) Fail	—	—
11.	Shri Om Prakash Bhardwaj, Divisional Accountant, Office of the Chief Accounts Officer, F & A Wing, H. P. S. E. B., Kumar House, Shimla-171 004.	929011	35 (23.3%) Fail	33 (16.5%) Fail	41 (41%) Fail	83 (41.5%) Fail
12.	Shri Tara Dutt Sharma, Divisional Accountant, Office of the Executive Engineer, City (Electrical) Division, H. P. S. E. B., Shimla-171 001.	929012	—	76** (38%) Fail	—	—
13.	Shri Gulshan Aggarwal, Divisional Accountant, Office of the Accounts Officer, NJPC, F & A Wing, Shakuntlam, Sanjauli, Shimla-12.	929013	—	74 (37%) Fail	—	88 (44%) Fail
14.	Shri Gita Ram Sharma, Divisional Accountant, Office of the Accounts Officer, Nathpa Jhakri Power Corporation Ltd. Jhakri (H. P.).	929014	—	84** (42%) Fail	—	—
15.	Shri Mohinder Nath Tewari, Divisional Accountant, Electrical Division, H. P. S. E. B., Jawali, District Kangra (H. P.).	929015	48 (32%) Fail	51 (25.5%) Fail	45 (45%) Fail	81 (40.5%) Fail

1	2	3	4	5	6	7
16.	Shri Manohar Lal Chandel, Divisional Accountant, Thirot Construction Division No. II, H.P. State Electricity Board, Bhuntar, District Kullu, Himachal Pradesh.	929016	50 (33.3%) Fail	84 (42 %) Fail	45 (45%) Fail	—
17.	Shri Inder Singh Patial, Divisional Accountant, Parbati Investigation Division No. I, H.P.S.E.B., Sarabai, P.O. Bhuntar, District Kullu (H. P.).	929017	A	—	—	—
18.	Shri Ganga Ram Thakur, Divisional Accountant, Investigation-cum-Construction Division No. I, H.P.S.E.B. Kol Dam, Sundernagar, District Mandi, (H. P.).	929018	—	85** (42.5%) Fail	—	—
19.	Shri Satish Kumar, Divisional Accountant, Banking Section, Finance and Accounts Wing, H.P.S.E.B., Vidyut Bhavan, Shimla-4.	929019	—	62** (31%) Fail	—	—
20.	Shri Ravinder Nath Sharma, Divisional Accountant, Electric Gaj and Baner Power House Division, H.P.S.E.B., Kangra (H. P.).	929020	A	A	A	A
21.	Shri Amar Singh Verma, Divisional Accountant, Finance and Accounts Wing, H.P.S.E.B., Kumar House, Shimla-171 004.	929021	31 (20.6%) Fail	A	31 (31%) Fail	56 (28%) Fail
22.	Shri Bhagat Ram, Divisional Accountant, (Electrical) Division, Manali, District Kullu (H. P.).	929022	35 (23.3%) Fail	38 (19%) Fail	25 (25%) Fail	110 (55%) Fail
23.	Shri Rattan Lal Kaundal, Divisional Accountant, F & A Wing, WAP-I, H.P.S.E.B., Kumar House, Shimla-171 004.	929023	—	50** (25%) Fail	—	—
24.	Shri Beli Ram, Divisional Accountant, Electrical Division, H.P.S.E.B., Nadaun, District Hamirpur, H.P. Pin-177 033.	929024	A	A	A	A
25.	Shri Ranesh Kumar Kaushal, Divisional Accountant, F & A Wing, H.P.S.E.B. Vidyut Bhavan, Shimla-171 004.	929025	38 (25.3%) Fail	59 (29.5%) Fail	46 (46%) Fail	95 (47.5%) Fail

** Are required to obtain 60% marks in the next examination.

1	2	3	4	5	6	7
26.	Shri Mani Ram Sharma, Divisional Accountant, Office of the Executive Engineer, Electrical Division, H. P. S. E. B. Rajgarh, District Sirmaur H. P., Pin-173101.	929026	—	A	—	—
27.	Shri Bhoop Chand Guleria, Divisional Accountant, Shimla Electrical Division No. I, H. P. S. E. B., Shimla-171002.	929027	48 (32%) Fail	A	39 (39%) Fail	79 (39.5%) Fail
28.	Shri S. D. Sharma, Divisional Accountant, Larji Construction Division No. II, Larji, District Kullu (H. P.).	929028	—	95 (47.5%) Fail	—	—
29.	Shri Jaswant Singh, Divisional Accountant, Central Store Division H. P. S. E. B. (NJPC), Parwanoo.	929029	—	134 (67%) Pass	—	—
30.	Shri Nant Ram Kashyap, Divisional Accountant, Office of the Executive Engineer, Bhaba Construction Division No. II, H. P. S. E. B. Katgaon, District Kinnaur (H. P.).	929030	A	A	A	A
31.	Shri Y. P. Kapoor, Divisional Accountant, Office of the Executive Engineer, HID H. P. S. E. B. Mandi (H. P.).	929031	68 (45.3%) Pass	98 (49%) Pass	—	95 (47.5%) Pass

ABBREVIATIONS : 'A' denotes 'ABSENT'.

Sd/-
Secretary.

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएँ

शिमला-171002, 22 जनवरी, 1993

संख्या कोप-ए(2)-14/85.—मारत के राष्ट्रपति, हिमाचल प्रदेश सहकारी सभायें अधिनियम, 1968 (वर्ष 1969 का 3) की धारा 35(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचक अधिसूचना दिनांक 14-12-1992 द्वारा जारिकर्ता केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित, सोनल के सचालन मण्डल में मनोनीत दो सहकारी नवदलों नवंदी राजकार मृत्यु थी विलोक्त नाथ, डग्गाई, डॉ. डग्गाई, तहसील व जिला सालन तथा श्री हुत ग्राम शर्मी सुनुव श्री पूर्ण चन्द, गंव डडोग, डाकघासा घार चण्डी, वाया दाङ्गापाट, तहसील याकी जिला सोनल का मनोनीत इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से रद्द करने का स्वर्ण आदेश प्रदान करते।

Shimla-171002, the 22nd March, 1993

File No. Coop. A (4)-3 93.—The President of India, is pleased to constitute a Screening Committee in the office of the Registrar, Co-operative Societies, Himachal Pradesh consisting of the following members to scrutinise the sanction of funds by the State Government and the National Co-operative Development Corporation, New Delhi under Centrally Sponsored Scheme of distribution of consumer articles in rural areas:—

1. Registrar, Co-operative Societies Himachal Pradesh, Shimla-9.	<i>Chairman</i>
2. Joint Secretary (Co-operation) to the Government of Himachal Pradesh.	<i>Member</i>
3. Deputy Regional Director, National Co-operative Development Corporation, Deputy Regional Office, Shimla-1.	<i>Member</i>
4. Deputy Registrar (Consumer) Directorate of Co-operation, Shimla-9.	<i>Member-Secretary</i>

The above Screening Committee will meet once in a month and consider consolidated proposals of Lead and Link Societies. Minutes of meeting may be sent to the NCDC for further necessary action. The proposals in respect of Link Societies for margin money approved by the Screening Committee will be submitted to the State Government for sanction. The proposals of Lead Societies for margin money assistance will be submitted to the Regional Director, NCDC for sanction whereas the other components of assistance i.e. Transport Vehicle to the Lead Societies and Furniture and Fixtures to Lead and Link Societies will be sent to the State Government for further submission to National Co-operative Development Corporation.

By order,

A. N. VIDYARTHI,
Financial Commissioner-cum-Secretary.**FOREST FARMING AND CONSERVATION
DEPARTMENT****NOTIFICATIONS**

Shimla-171002, the 3rd February, 1988

No. 1-18/72-SF(Estt)-II.—In partial modification of this department notification of even Number, dated 4th February, 1987, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to define the following two working Plan Divisions in the Department of Forest, Farming and Conservation in place of the Divisions earlier defined vide this

department notification of even number, dated 4th February, 1987 with immediate effect:—

Sl. No.	Name of Division earlier defined 1	Name of Division now defined 2	Name of Hqrs. 4
1.	Hamirpur working Plan Division.	Bharmaur working Plan Division.	Bharmaur
2.	Dharamshala wor- king Division.	Karsog working Plan Division.	Karsog

Shimla-171002, the 12th February, 1988

No. Fts(1)B(2)3/86(Estt).—The Governor, Himachal Pradesh, on the recommendation of the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to accord sanction for the continuation of *ad hoc* appointment of Shri O. P. Ahlawat, Deputy Director (Statistics) Class-I Gazetted for a period of 3 months i.e. with effect from 25-11-1987 to 29-2-1988 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier. This is in continuation of this department notification of even number, dated the 29th June, 1987.

Shimla-171002 the 12th February, 1988

No. Fts(A)2-1/86.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the Deputy Director Technical (Forest) posted in the Enforcement Wing of Vigilance Department of Himachal Pradesh Government as Forest Officer to do all acts and exercise all powers of a Forest Officer under the following provision of the Indian Forest Act, 1927 and the Himachal Pradesh Forest Produce Transit (Land Routes) Rules, 1978, within the territory of Himachal Pradesh:—

Sections of the Indian Forest Act, 1927 under which powers are given	Brief description and nature of power conferred
1. Section 52	Power to seize property liable to be confiscated.
2. Section 64	Powers to arrest without warrant.
3. Section 65	Powers to release on a bond a person arrested.
4. Section 66	Powers to prevent commis- sion of forest-offences.
5. Section 72(b)	Power of Civil Court to compel the attendance of witnesses and production of documents.
6. Section 72(d)	Power to hold an enquiry into forest-offences and in the course of such enquiry to receive and record evidence.

Rules under which powers are given:—

- Rule 14 of the Himachal Pradesh Forest Produce Transit (Land Routes) to produce pass/challan Rules, 1978 framed under section 41 & 42 of Indian Forest Act, 1927.
- Rule 15 of the Himachal Pradesh Forest Produce Transit (Land Routes) Rules, 1978 framed u/s 41 and 42 of Indian Forest Act, 1927.
- Rule 16 of the Himachal Pradesh Forest Produce Transit (Land Routes) Rules, 1978 framed u/s 41 and 42 of Indian Forest Act, 1927.

Shimla-2, the 12th February, 1988

Shimla-171002, the 23rd February, 1988

5

No. Fts-I (B) 10-1-88. The grievances of retired Government servants/employees in respect of the pensionary matters have been engaging the attention of the Government for some time past. Therefore, in order to ensure that pensionary claims of the Government servants are settled expeditiously, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to set up the Departmental Pension Adalat in the Department of Forests Farming and Conservation which shall comprise the following:—

1. Secretary (Forests)
 2. Pt. Chief Conservator of Forests.
 3. Sr. Accounts Officer/Accounts Officer of the Forest Department failing which officer concerned with pension cases.
 4. Accounts Officer from A.G. Office, if necessary (on special invitation).
2. The departmental pension Adalat shall consider the following matters:—

1. Cases of the Forest Department retirees where pension/gratuity has not been sanctioned in favour of the retiree.
2. Wrong fixation of pension on the initial stage as a result of revision of pension against which a pensioner may have represented to the department.
3. Other grievances relating to the pensioner of the department.
4. Cases of such pensioners of the Forest Department who may have gone to the Court of Law for the redress of their grievances with a view to have their settlement outside the Court.
5. Reviewing of pending pension cases in the Forest Department and finding solution to bring down pendency to minimum and expeditious settlement of pension cases.
6. Monitoring for expeditious settlement of pension cases at level of Departmental Adalat.

3. Therefore keeping in view the above contents the cases of the retirees will be examined by the Forest Department on receipt of representation from the retiree to settle their pension cases, and thereafter will be placed before the departmental pension Adalat. But the pensioner will be at liberty to address the application to Finance Department (State Pension Adalat) or the Forest Department or both. In cases where it will not be possible to find out a solution, the case will be referred to State Pension Adalat constituted by the Finance Department *vide* their notification No. Fin (C) B (10)-5/87, dated 25th August, 1987.

4. The meeting of the departmental pension Adalat will be held once every month.

Shimla-2, the 18th February, 1988

No. Van. (Kha) 3-38/79(Estt)-Vol-II.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order the promotion of Shri C. L. Sudhera, I.F.S., Conservator of Forests (Level-II) to Conservator of Forests (Level-I) in the pre-revised scale of pay of Rs. 2000-125/2-2250 with effect from 5th April, 1984 and thereafter with effect from 1-1-1986 in the revised scale of Rs. 4500—5700.

2. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order that the above-mentioned promotion of Shri C. L. Sudhera, I.F.S., C. F. (Level-II) is subject to the decision of the court case pending against him. He will be reverted back to the lower post of C. F. (Level-II) in the event of his non-exoneration or his non-acquittal by the Hon'ble Court from the charges levelled against him due to the Court case.

No. Fts.I(B)2-3/85(Estt).—In continuation of this department notification of even number, dated the 13th March, 1987, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to promote the following Superintendent Grade-I (*ad hoc*) on regular basis in the pay scale of Rs. 825—1580 with immediate effect:—

1. Shri Brij Lal
2. Shri Bhanu Dutt

By order,

S. S. SADHU,
Secretary.

Shimla-2, the 23rd February, 1988

No. Fts. I (B)9-2/83 (Estt).—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to promote Shri P. L. Goswami, Supdt. Grade-I to the post of Registrar (Vigilance) Class-II Gazetted, in the pay scale of Rs. 1200-1700 purely on *ad hoc* basis with immediate effect upto 31-8-88 (*i.e.* the date of his retirement).

2. The *ad hoc* promotion will not confer any right in the matter of seniority or regular promotion upon Shri P. L. Goswami.

By order,

S. S. SIDHU,
Commissioner-cum-Secretary.

Shimla-171002, 8 जनवरी, 1993

संघरा वन-1 (बो1) 6-2/92.—भारत के राष्ट्रपति सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री एस० बी० इस्लाम, भा० व० से०, उप-प्ररण्यपाल, कण्डी परियोजना, सोलन अपने कार्य के अतिरिक्त आगामी आदेशों तक श्री एस० के० पाण्डेय, भा० व० से०, परियोजना निवेशक, कण्डी परियोजना निवेशक, सोलन का कार्य भी देखेंगे।

2. यह आदेश तत्काल लागू होंगे।

Shimla-171002, 8 जनवरी, 1993

संघरा वन-1 (बो1) 6-2/92.—भारत के राष्ट्रपति सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री जोगिन्द्र सिंह, भा० व० से०, अरण्यपाल (सामाजिक बनिकी) द्वितीय वृत धर्मशाला अपने कार्य के अतिरिक्त आगामी आदेशों तक श्री एच० के० गुप्ता, हि० प्र० झ० मे०, वा० म०ड़ाविकारी (मू-कार्य योजना) क्षिता० का कार्य भी देखेंगे।

2. भारत के राष्ट्रपति यह भी आदेश देते हैं कि श्रीमती विजयलक्ष्मी तिवारी, भा० व० से०, वन मण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी), शिमला अपने कार्य के अतिरिक्त आगामी आदेशों तक श्री एच० के० गुप्ता, हि० प्र० झ० मे०, वा० म०ड़ाविकारी (मू-कार्य योजना) क्षिता० का कार्य भी देखेंगे।

3. यह आदेश तत्काल लागू होंगे।

Shimla-171002, 8 जनवरी, 1993

संघरा वन-1 (बो1) 6-2/92.—इस विभाग की सभ संचयक अधिकृति, दिनांक 4-1-1992 में आधिक परिवर्तन करते हुए भारत के राष्ट्रपति श्री एस० एस० खुण्डिल, हि० प्र० व० से०, सहायक अरण्यपाल, रामपुर वन मण्डल स्थानान्तरणाधीन, सहायक अरण्यपाल, वन मण्डल मुद्रणवार पुष्पालय स्थित नरवाहाट की विशेष कार्य अधिकारी, अरण्यपाल रामपुर वृत तैनात करने के लोकहित में सहर्ष आदेश देते हैं।

ये आदेश तत्काल लागू होंगे।

गिम्न.-171002, 11 जनवरी, 1993

संभवा वन-1 (बी०) 6-2/92.—भारत के राष्ट्रपति निम्ननिवित्त
एवं दोष वा विवरणों के लाक हिं में स्वागतरण एवं
ताती तदात करने के महर्य प्राप्ति देते हैं:—

मानक अधिकारी का वर्तमान तैनाती नई तैनाती
नाम

श्री मोहिनी धान, भारत सरकार में केन्द्रीय उप-प्रश्नपाल (एम०
भा० व० से०। प्रतिनियुक्ति से प्रत्याए० एण्ड ई०), शिमला,
वर्तमान पर।

श्री एम० एस० उप-प्रश्नपाल (एम० वन मण्डलाधिकारी
सनी, भा० व० से०। एण्ड ई०), शिमला। (भू-कार्य योजना)
शिमला, श्री हेमन्त
गुटा, हिं० प्र० व०
से० के स्थान पर।

श्री इन० डी० आरी, वन मण्डलाधिकारी, उप-प्रश्नपाल, Institute of Rain
भा० व० से०। रेणुका वन मण्डल। and Moist
Deciduous Forest Research Jorhat
(Assam).
(प्रतिनियुक्ति पर)

2. भारत के राष्ट्रपति वह भी आदेश देते हैं कि श्री विनोद
पाठ, भा० व० से०, वन मण्डलाधिकारी, नाहन वन मण्डल कार्य
प्रभारिक वन मण्डलाधिकारी, रेणुका वन मण्डल का कार्यभार भी
पासी आदेशों तक सम्भालेंगे।

3. वह आदेश तुरन्त लागू होंगे।

आदेश द्वारा,

पी० टी० व० व० व० व०
वित्तायुक्त एवं सचिव।

FINANCE (REGULATION) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th January, 1988

No. Fin. C (A)-2-1/84-II.—In continuation of this department Notification of even number dated the 1st June, 1987, declaring Sub-Divisional Officer (Civil) Bharmaur, District Chamba as Drawing and Disbursing officer in r/o the establishment of Food and Supplies Department posted at Bharmaur, under head “2408-
Food Storage and Warehousing, 01-Food (796)-Tribal area Sub Plan, 01-Expenditure on Food Organisation.” ie Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that the Sub-Divisional Officer (Civil) Bharmaur shall so function as Controlling Officer for T.A. in r/o Class I and IV officials of the Food and Supplies Department posted in Bharmaur area.

कार्यालय जापन

शिमला-171002, 4 जनवरी, 1993

प्र.—डोडराक्षार क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों को अधिकारम
ठहराव भत्ते की देयता।

संभवा फिन (सी) बी० (7)-21/77-VIII.—प्रधोहस्ताक्षरी को
कहने का निदेश हुआ है कि शिमला के डोडराक्षार क्षेत्र
में तैनात हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को प्रतिपूरक भत्ते
की देयता का सामान्य कुछ समय से सरकार के विचाराधीन था।
मामले पर विचार करने के उपरान्त भारत के राष्ट्रपति इस
विभाग के कार्यालय जापन संघरा फिन (सी) बी० (7)-21/77,
दिनांक 19-8-1987 को जारी किए गए आवेदनों में आंशिक
संशोधन करने हुए डोडराक्षार तहसील/उपमण्डल को ग्रूप IV के
स्थान पर ग्रूप III में प्रतिस्थापित करने के नहर्य आदेश देते हैं।
जिसके कानूनवृत्त वर्तमान में उक्त क्षेत्र में कार्यरत भत्ती कर्मचारियों
को प्रतिपूरक भत्ता विभाग के का० जा० समसंधिक दिनांक
10-4-88 में ग्रूप III की विहित मु० 475/- रुपये मासिक दर
से देय होगा।

में तैनात श्रमकार के कर्मचारियों को अधिकारम ठहराव जना
प्रदान किये जाने का सामान्य कुछ समय से सरकार के विचाराधीन
था। मामले पर विचार करने के उपरान्त भारत के राष्ट्रपति,
जनजातीय विभाग के पर्व मण्डली एल जी (एक) 5-8/80-टी०८०८०
दिनांक 7 मित्तम्बर, 198 एवं टी०८०८० (बी) 12-5/81, दिनांक
28-11-198 में जनजातीय क्षेत्र हेतु विहित दरों एवं शर्तों के
प्रायाध पर अधिक ठहराव भत्ते की सुविधा को जिला शिमला के
डोडराक्षार नहीं एवं उप मण्डल में कार्यरत राज्य सरकार के
कर्मचारियों की दिनांक 1-11-1992 से प्रदान करने के नहर्य आदेश
देते हैं।

अधिकारम ठहराव भत्ते की दरों निम्ननिवित्त होती:—

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. चंदे वर्ष में | .. 10 प्रतिशत मूल वेतन का |
| 2. पांचवे वर्ष में | .. 17 प्रतिशत मूल वेतन का |
| 3. छठे वर्ष में | .. 25 प्रतिशत मूल वेतन का |
| 4. मात्रवें या उससे अधिक | .. 35 प्रतिशत मूल वेतन का |

उक्त भत्ते की न्यूनतम भीमा 50/- रुपये व अधिकारम 500/-
रुपये प्रतिमास होती है। यह अत्या उहीं कर्मचारियों की देय होगा जो
उक्त क्षेत्र के स्वाइ निवासी नहीं होंगे तथा जिन्हें जन हित में एवं
सरकार के आदेशों के अनुरागत उक्त क्षेत्र में तीत वर्ष की तैनाती
अवधि पूर्ण होने के पश्चात भी उक्त क्षेत्र में कार्यरत रहना पड़ता
है। सम्बन्धित कर्मचारियों को इस भत्ते की स्वीकृति के आदेश
प्रत्येक मामले में नियुक्त प्राविधिकी द्वारा जारी किये जायेंगे तथा
आहरण एवं विनरण अधिकारी उक्त भत्ते को आवृण करते समय
यह प्रमाणित करेंगे कि सम्बन्धित कर्मचारी का उक्त क्षेत्र में अधिकारम
ठहराव जन हित में है।

शिमला-171002, 4 जनवरी, 1993

विषय.— डोडराक्षार क्षेत्र को प्रतिपूरक भत्ता की देयता हेतु
ग्रूप 4 से ग्रूप 3 में प्रतिस्थापित करने वारे।

संभवा फिन (सी) बी० (7)-21/77-VIII.—प्रधोहस्ताक्षरी को यह
कहने का निदेश हुआ है कि जिला शिमला के डोडराक्षार क्षेत्र
में तैनात हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को प्रतिपूरक भत्ते
की देयता का सामान्य कुछ समय से सरकार के विचाराधीन था।
मामले पर विचार करने के उपरान्त भारत के राष्ट्रपति इस
विभाग के कार्यालय जापन संघरा फिन (सी) बी० (7)-21/77,
दिनांक 19-8-1987 को जारी किए गए आवेदनों में आंशिक
संशोधन करने हुए डोडराक्षार तहसील/उपमण्डल को ग्रूप IV के
स्थान पर ग्रूप III में प्रतिस्थापित करने के नहर्य आदेश देते हैं।
जिसके कानूनवृत्त वर्तमान में उक्त क्षेत्र में कार्यरत भत्ती कर्मचारियों
को प्रतिपूरक भत्ता विभाग के का० जा० समसंधिक दिनांक
10-4-88 में ग्रूप III की विहित मु० 475/- रुपये मासिक दर
से देय होगा।

ये आदेश दिनांक 1-11-1992 से प्रभावी होंगे।

हस्ताक्षरित/
उप सचिव।

वाच्य एवं आपूर्ति विभाग

प्रबिसूचना

शिमला-171002, 14 जनवरी, 1993

संभवा एक० डी० ए० वी० (15)-3/91.—भारत के राष्ट्रपति,
इस विभाग को समस्तूक प्रविसूचना दिनांक 24 जनवरी, 1992
की विस्तृता में श्री एस० जी० नेही, उप-निदेशक, खाद्य एवं
आपूर्ति को हिमाचल प्रदेश राज्य नामिक आपूर्ति निगम में प्रबन्धक
(कार्मिक) के पर पर बने रहने हेतु दिनांक 2-1-93 से 1-1-94

तक एक वर्ष प्रतिनियुक्ति समय बढ़ाने के लिए, इस विभाग के पक्ष सद्या एफ०डी०एस०र्डी०(2) (15) 1/90, दिनांक 1-8-1990 में दो गई तरंगाम निवन्धन एवं शर्तों पर स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

General, Himachal Pradesh, in the pay scale of Rs. 825—1580 (Class-II) per month, on *ad hoc* basis, for six months purely on temporary basis or till the time, the post is filled up in accordance with the rules for the said post whichever is earlier.

शिमरा-171002, 18 फरवरी, 1993

सं ० एक० डी० एम०-ए० (४)-५/८७।—इस विभाग की प्रधिसूचना संख्या एक० डी० एम०-ए० (४)-५/८७, दिनांक २७-२-१९ के क्रम में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, १९८६ (१९८६ का केन्द्रीय अधिनियम सं ० ६८) को धारा १६(२) के अन्तर्गत जो हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, १९८८ के उप-नियम १४ के साथ पढ़ा जाए, में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति, श्रीमती प्रियंका मल्होत्रा, एम० ए० एल० एल० डी० को २७-२-१९३ से हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता विवाद प्रतिवेश “राज्य आयोग” की मददगार अंशगालीन आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं, जिसकी शर्त व निवन्धन निम्न प्रकार से होंगी:—

1. श्रीमती प्रतिमा मल्होत्रा को प्रतिदिन प्रति सूनवाई के लिए मंचित मानदेय मु० 250/- रुपये (दो सौ पचास) के लिए दिए जाएंगे।
 2. श्रीमती प्रतिमा मल्होत्रा दो वर्ष की अवधि तक सदस्या के पद पर रहने की पात्र होंगी।
 3. श्रीमती प्रतिमा मल्होत्रा, यात्रा व दैनिक भत्ता प्रदेश सरकार के उच्चतम ग्रेड-1 के अधिकारियों को दिए जाने वाली यात्रा व दैनिक भत्ते की दरों के बढ़ावर प्राप्त करने की हकदार होंगी।

‘इनकी नियुक्ति की दृष्टियों शर्तें व निबन्धन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 व हाइकोर्ट प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1988 के प्रावधानों के अन्तर्गत ही निहित होंगी।

आदेश द्वारा,

अमर नाथ विद्यार्थी,
वित्तायकत एवं सचिव) ।

**GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(C-SECTION)**

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26/29th January, 1988

No. GAD (2)(B) 5/82-GAC.—The Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Hon'ble Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha, is pleased to appoint Shri L. S. Kashyap, HPAS as Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha in place of Shri V. Verma, with effect from 1-2-1988, on deputation basis.

B. C. NEGI,
Chief Secretary.

HOME (B) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd February, 1988

No. Home-II (B) 2-2/81.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Shri Ram Murti Bisht, Advocate, as Law Officer in the office of the Advocate

1. श्री बी० ए० थापा, वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (प्रशासन) ।
2. श्री जे० ए० थाकुर, वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (प्र० व० ओ०) ।
3. श्री के० के० दीदी, मण्डल आवेदक, धर्मसाला ।

एस० एस० प्रसार-

४८०

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ

एस० एस० परमार,
आयुक्त एवं सचिव ।

OFFICE ORDER

Shimla-171002, the 13th January, 1993

Subject. -Final Seniority list of Commandants/Junior Staff Officers of Home Guards & Civil Defence Department Himachal Pradesh as on 31-8-1992.

No. HOME-B (B) 13-1/86.—As per the decision in O. A. No. 119/88 of the Hon'ble Administrative Tribunal Shimla on 22-11-1991 to quash seniority list of Commandants/Junior Staff Officer circulated vide this department letter No. 6-58/70-Home, dated 29-6-1983 and to re-draw this seniority list as on 31-1-1982.

In view of above, the final seniority list of Commandants/Junior Staff Officer of Home Guards & Civil Defence Department as on 31-8-1992 is hereby circulated for the information of all concerned.

No representation against this list will be entertained except for clerical omission/mistake or mistakes of the like nature if any, which may be intimated within 15 days from the date of circulation.

FINAL SENIORITY LIST OF COMMANDANTS/JUNIOR STAFF OFFICERS OF HOME GUARDS & CIVIL DEFENCE DEPARTMENT HIMACHAL PRADESH AS ON 31-8-1992

Sl. No.	Name of the Officer	Date of birth	Date of joining the Govt. Service/Date of appointment	Date of Confirmation	Remarks
1	2	3	4	5	6
S/Shri:					
1.	V. S. Thapa	5-3-40	13-8-70	13-12-73	Promoted as SSO.
2.	J. S. Thakur	16-1-42	13-8-70	13-12-73	Promoted as SSO.
3.	K. K. Didi	2-7-43	18-9-70	13-12-73	Promoted as Divisional Commandant.
4.	T. S. Paul	7-1-38	4-2-74	24-12-76	Promoted as Divl. Commandant.
5.	K. S. Pundir	25-9-40	3-6-74	28-9-77	Promoted as Commandant Training Junga on ad hoc basis.
6.	Jai Lal Manta	10-8-37	7-8-75	8-2-85	
7.	Bahadur Singh Tomar	20-6-39	4-1-82	8-2-85	
8.	J. R. Sharma	1-7-39	1-1-82	8-2-85	
9.	Ajay Kumar Katot	6-2-47	24-4-78	8-2-85	
10.	Upendra Singh	15-7-40	1-1-82	8-2-85	
11.	Brij Lal Gautam	21-5-41	20-7-83	Temporary	
12.	Rakesh Kumar Sharma	19-5-58	16-4-86	-do-	
13.	Deepak Katyan	9-4-42	15-12-86	-do-	
14.	Birender Singh Paul	13-9-49	21-1-88	-do-	
15.	Ranbir Singh Rana	1-2-45	28-8-91	-do-	

NARENDER CHAUHAN,
Joint Secretary.

(SECTION-D)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 16th February, 1993

No. Home. D (B-3)-4/92.—The President of India is pleased to order that during the probation period, Shri Prem Kumar Thakur, Himachal Pradesh Police Service (Probationer) shall remain attached to Police Training School, Jurga for practical training etc.

Sd/-
Commissioner-cum-Secretary.

CORRIGENDUM

Shimla-171002, the 26th March, 1993

No. Home-B(B)13-1/86.—Please read in the serial No. 3 date of birth of Shri Rakesh Kumar Sharma, Commandant 19-8-1958 instead of 19-5-1958 in the second page of Final Seniority List of Commandant/Junior Staff Officer of Home Guards and Civil Defence Department, Himachal Pradesh on 31-1-1992, which has been circulated vide this department of even number dated 13-1-1993.

NARINDER CHAUHAN,
Joint Secretary.

आवास वोर्ड

महिला संस्करण

मिल्का-2, 23 जनवरी, 1993

मंजुषा आवास-1 (ए) ०-३/८०.—प्राप्ति, भारत सरकार इस नियम के तमसंबंधीक अधिसूचना फ़िल्म, १९९०,

५ जनवरी, 1991, २७ अप्रैल, 1991 तथा २६ जून, 1992 का अधिकमण करते हुए और हिमाचल प्रदेश आवास वोर्ड अधिनियम, १९७२, घारा ५ के साथ पिल घारा ३ द्वारा प्रदत्त ग्रन्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश आवास वोर्ड का नियमित न्यूप में तुरन्त पुनर्गठन करते हैं ग्रन्ति:—

1. महाहकार (पी)
 2. आयुक्त एवं मन्त्रिव (वित्त)
 3. वित्तायुक्त एवं मन्त्रिव (आवास)
 4. वित्तायुक्त एवं मन्त्रिव
(वित्तायुक्त प्रशासन विभाग)।
 5. प्रमुख अधिकारी, सिचाई एवं जन स्वास्थ्य
 6. मुख्य अधिकारी, लोक निर्माण विभाग
 7. निदेशक, नार एवं आम मोजना विभाग
 8. मन्त्रिव एवं मुख्य अधिकारी आवास वोर्ड
- मन्त्रिव मदस्य
मन्त्रिव मन्त्रिव

आवास वोर्ड का मुख्यान्य शिमला में स्थित होगा।

ग्राहक द्वारा,

एस० एस० लिंग;
वित्तायुक्त एवं मन्त्रिव।

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th January, 1988

No. Health-B (9) 6/85.—The Governor, Himachal Pradesh, on the recommendation of Departmental Promotion Committee, is pleased to confirm the following Professors, Associate Professors and Assistant Professors in the pay scale of Rs. 1500-2500, 1200-1900 plus Rs. 100/- special pay and Rs. 1200-1900 respectively

from the dates shown against each :—

Sl. No.	Name of the doctor	Department	Post against which confirmation med	Date 22-7-82
1.	Dr D. J. Dasgupta	Medicine	Profesor.	22-7-82
2.	Dr. (Mrs.) Tara Gupta	Ob & Gyana.	-do-	4-5-86
3.	Dr. R. C. Sharma	Skin & VD	-do-	4-5-86
4.	Dr Yogender Mohan	Psychiatry	-do-	4-5-86
5.	Dr. R. K. Sexena	E. N. T.	-do-	22-7-82
6.	Dr. D. V. Behl	C.T.S.	-do-	31-5-86
7.	Dr. S. K. Bansal	Medicine	Ass.	22-7-82
8.	Dr L. S. Paul	-do-	-do-	4-5-86
9.	Dr. B. K. Goel	Ophthalmology	-do-	22-7-82
10.	Dr. M. L. Sharma	E.N.T.	-do-	30-9-83
11.	Dr. (Mrs.) Raj Puri	Physiology	-do-	22-7-82
12.	Dr. D. N. Sharma	Pathology	Asstt.	12-9-82
13.	Dr B. B. Sharma	-do-	-do-	13-12-82
14.	Dr. (Mrs.) Jai Shree Sharma.	-do-	-do-	28-7-87
15.	Dr. S. R. Thakur	Orthopaedics	-do-	12-9-82
16.	Dr. Mrs. Suman Sharma.	Medicine	-do-	12-5-83
17.	Dr. B. S. Prashar	-do-	-do-	28-2-84
18.	Dr. Surinder Kashyap	Opthalmology.	-do-	8-10-87
19.	Dr. V. Bansal	Skin	-do-	2-3-82
20.	Dr. N. L. Sharma	E.N.T.	-do-	4-9-82
21.	Dr. Chander Mohan	Bio-Chemistry.	-do-	16-3-87
22.	Dr. R. M. Pathak	Physiology	-do-	7-6-82
23.	Dr. P. K. Nanda	PSM	-do-	10-7-81
24.	Dr. B. P. Gupta		-do-	1-6-82

The above confirmations do not indicate the order of seniority.

AJAY PRASAD,
Secretary.

शिमला-2, 6 दिसम्बर, 1991

क्रमांक हैल्य-बी(3)-89/87.—हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय, डाक्टर जगदीप मिह राणा को स्वास्थ्य सेवा के 1974 के नियम 9 के अधीन रूपये 2250—4000 के वेतनमान में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य नेवा के पद पर नियमित रूप से दिनांक 23-1-1991 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं। डाक्टर जगदीप मिह राणा 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेगा।

शिमला-2, 10 दिसम्बर, 1991

क्रमांक हैल्य-बी(3)-49/91.—हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय, डाक्टर जगदीप मिह को स्वास्थ्य सेवा के 1974 के नियम 9 के अधीन रूपये 2250—4000 के वेतनमान में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री के पद पर नियमित रूप से दिनांक 31-1-1991 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं। डाक्टर जगदीप मिह 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेगा।

शिमला-2, 12 दिसम्बर, 1991

क्रमांक हैल्य-बी(3)-49/87.—हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय, डाक्टर जगदीप मिह जम्मान को स्वास्थ्य नेवा के 1974 के नियम 9 के अधीन रूपये 2250—4000 के वेतनमान में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य नेवा के पद पर नियमित रूप से दिनांक 22-1-1991 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं। डाक्टर जगदीप मिह जम्मान 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेगा।

शिमला-171002, 12 दिसम्बर, 1991

क्रमांक हैल्य-बी(3)-28/91.—हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय, डाक्टर जगदीप कुमार गोयल को स्वास्थ्य सेवा के 1974 के नियम 9 के अधीन रूपये 2250—4000 के वेतनमान में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवा के पद पर नियमित रूप से दिनांक 8-3-1991 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं। डाक्टर जगदीप कुमार गोयल 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेगा।

शिमला-2, 18 दिसम्बर, 1991

संख्या हैल्य-बी(3)-18/90.—हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय, डाक्टर जगदीप कुमार शर्मा को स्वास्थ्य सेवा के 1974 के नियम 9 के अधीन रूपये 2250—4000 के वेतनमान में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवा के पद पर नियमित रूप से दिनांक 2-3-1991 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं। डाक्टर जगदीप कुमार शर्मा 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेगा।

शिमला-2, 18 दिसम्बर, 1991

संख्या हैल्य-बी(3)-60/90.—हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय, डाक्टर जगदीप उपाध्याय को स्वास्थ्य सेवा के 1974 के नियम 9 के अधीन रूपये 2250—4000 के वेतनमान में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवा के पद पर नियमित रूप से दिनांक 16-1-1991 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं। डाक्टर जगदीप उपाध्याय 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेगा।

प्रारूप के 0 यात्रद, विनापुरुष एवं सचिव।

शिमला-2, 11 मार्च, 1991

संख्या हैल्य-बी(3)-50/80-II.—विभागीय कमेटी की सिफारिश पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय, डाक्टर दीना नाथ शर्मा को स्वास्थ्य सेवा नियमों 1974 के नियम 9 के अधीन रूपये 4500—7300 के वेतनमान में आचार्य पेंडोलीजि के एक पद पर नियमित रूप से दिनांक 24-1-1991 से नियुक्त करते हैं। डाक्टर दीना नाथ शर्मा दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेगा।

हस्ताक्षरित,
सचिव।

शिमला-2, 6 जनवरी, 1993

संख्या एच०एफ०डब्ल्य०-बी०(एफ०)२-५/८८-II.—इस विभाग के नमसंचयक अधिकारीनामे दिनांक 5-4-90 का अधिकारण करते हुए राष्ट्रपति, भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के अल्टर्नेट क्षेत्र परियोजना (UNFPA) को त्वचारू रूप से कार्यान्वित करने हेतु निम्न निर्दिष्ट सदस्यों को राज्य सभीय शासी किया (Governing Body) का सहर्ष, गठन करते हैं:—

1. राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश
2. सचाहकार राज्यपाल (के)
3. मुख्य मंत्री, हिं० प्र० सरकार
4. मंत्री (वित्त)
5. मंत्री (शोजना) हिं० प्र० सरकार
6. मंत्री (स्वास्थ्य) हिं० प्र० सरकार
7. मंत्री (शिक्षा) हिं० प्र० सरकार
8. मंत्री (शारीरिक विकास) हिं० प्र० सरकार
9. मंत्री (लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य एवं प्रिवाई) हिं० प्र० सरकार
10. मंत्री (कल्याण) हिं० प्र० सरकार
11. उप मंत्री (स्वास्थ्य) हिं० प्र० सरकार
12. निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हिं० प्र०
13. प्रमुख अधिकारी (लो० निं०) हिं० प्र०
14. प्रमुख अधिकारी (जन स्वास्थ्य एवं सिवाई) हिं० प्र० मंदस्य

15. निदेशक, योजना, हि० प्र०	मदल्प
16. निदेशक, कल्याण, हि० प्र०	मदल्प
17. निदेशक, ग्रामीण विकास, हि० प्र०	मदल्प
18. निदेशक, शिक्षा, हि० प्र०	मदल्प
19. निदेशक, परियोजना, यू० एन० एफ० पी० ए०	मदल्प-पचिब।

पदोन्नत करने के सहर्ष आदेश करते हैं। यह पदोन्नति तत्काल म प्रभावी होगी।

2. डाक्टर एस० सी० शर्मा दो वर्ष के लिए परियोजना पर रहेंगे।

इस तिकाय की बेंक छह मास में एक बार होगी तथा इसका कार्य निम्न होगा :—

- (i) परियोजना प्रगति की गतिविधियों को कार्यान्वित करने वारे समीक्षा।
- (ii) जारी विकास द्वारा परिवार कल्याण एवं परियोजना की नीति सम्बन्धी मामले तथा करना।
- (iii) परिवार कल्याण हेतु परियोजना की मुख्य अन्तर विभागीय समस्याओं का निवारण तथा परियोजना कार्य के लिए राय कोष से धन तथा विदीय स्रोतों से इत्यादि का जटाना।

3. यात्रा दैनिक भूता जहाँ दैव हो वह मदल्प प्रत्येक मध्यनिवृत्त विभाग से प्राप्त करेगा।

अमर नाथ विद्यार्थी,
वित्तायुक्त एवं मचिव।

शिमला-2, 6 जनवरी, 1993

संदर्भ हैल्थ-बी(3) 184/91.—हिमाचल प्रदेश लोक सेवा ग्रामीण की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय, डा० प्रीतम शिह शर्मा को स्वास्थ्य सेवा के 1974 के नियमों के नियम 9 के प्रधीन द्वाये 2250—4000 के वेतनमान में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवा द्वितीय श्रेणी के एक पद पर नियमित रूप से दिनांक 8-7-1992 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं। डा० प्रीतम शिह शर्मा 2 वर्ष के लिए परियोजना पर रहेगा।

शिमला-2, 11 जनवरी, 1993

संदर्भ स्वास्थ्य-बी (3) 2/93.—हिमाचल प्रदेश लोक सेवा ग्रामीण की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय, डा० प्रीतम शिह शर्मा को स्वास्थ्य सेवा के 1974 के नियमों के नियम 9 के प्रधीन द्वाये 2250—4000 के वेतनमान में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवा द्वितीय श्रेणी के एक पद पर नियमित रूप से दिनांक 2-7-1992 से नियुक्त करते हैं। डा० प्रीतम शिह शर्मा 2 वर्ष के लिए परियोजना पर रहेगा।

शिमला-2, 14 जनवरी, 1993

संदर्भ हैल्थ-बी(3)-1/93.—राष्ट्रपति महोदय, डा० (श्रीमती) चौहान, हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवा, जनरल इन्फॉर्मेशन और प्रविकारी प्रेड-ए के पद पर 2250—4000 द्वाये के वेतनमान में अनुवन्ध प्राप्ताद पर लः माह के लिए 25-7-1992 से या तब तक के लिए जब तक कि आसामी नियमित रूप से नहीं भरी जाए, जो भी नहले हो, नियुक्त करते हैं।

शिमला-2, the 26th March, 1993

No. Health-B(3)123/89.—The President of India is pleased to accept the resignation of Dr. Kanwar Singh, Dental Surgeon w.e.f. 7-1-93 (A.N.).

शिमला-171002, 30 मार्च, 1993

संदर्भ हैल्थ-बी(2) 2/93.—राष्ट्रपति महोदय, विभागीय संस्थानों की सिफारिश पर डाक्टर एस० सी० शर्मा, सहायक प्राधीन्य (दल्त विभाग), हिंदूरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, श्रीमन्ना को हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवायें नियम, 1974 के उप-नियम 9(8) (1) के प्रधीन उत्तर महाविद्यालय में दल्त विभाग में ही शार्यार्थ के रूप में ₹ 4500—7300 के वेतनमान में

शिमला-171002, 30 मार्च, 1993

क्रमांक हैल्थ-बी(3) 76/91.—हिमाचल प्रदेश लोक सेवा ग्रामीण की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय, डाक्टर विमा राम शर्मा को स्वास्थ्य सेवा के 1974 के नियमों के नियम, 9 के प्रधीन द्वाये 2250—4000 के वेतनमान में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवा द्वितीय श्रेणी के पद पर नियमित रूप से दिनांक 12-1-1992 (पूर्वाह्न) से नियमित नियुक्त करते हैं। डाक्टर विमा राम शर्मा दो वर्ष तक परियोजना पर रहेगा।

हस्ताक्षरित/-
वित्तायुक्त एवं निवारण (स्वास्थ्य)।

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Shimla-2, the 5th January, 1988

No. Udyog (Chh) 21-14/82 (TPT).—In supersession of this Government notification No. Udyog (Chh) 21-14/82, dated 22-3-1985, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to re-constitute with immediate effect the State level Committee consisting of the following in order to settle all claims of transport subsidy arising in the Pradesh, under the Transport Subsidy Scheme, 1971 of the Central Government :—

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Director of Industries, Himachal Pradesh. | Chairman |
| 2. Joint Secretary (Fin.)/Deputy Secretary (Fin.) to the Government of Himachal Pradesh. | Member |
| 3. Deputy Secretary (Industries) to the Government of Himachal Pradesh. | Member |
| 4. Deputy Director of Industries/Senior Technical Officer, Himachal Pradesh. | Member Secretary. |

Shimla-171002, the 8th February, 1988

No. Udyog-II (Chh) 11-11/87.—In pursuance of sub-section (1) of Section 7 of the State Financial Corporation Act, 1951 (LXIII of 1951), the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Board of Directors of Himachal Pradesh Financial Corporation, Shimla and based on the advice of the Industrial Development Bank of India, hereby fixes the rate of interest, currency of bonds, and issue price on the bonds of the value of Rupees 100.00 lacs (Rupees one crore) only with an option to retain 10% excess subscription to be issued by the Himachal Pradesh Financial Corporation during the year 1987-88 :—

Currency of bonds Issue price	15 years. Rupees 100/- per bond worth Rupees 100/- (At par).
Rate of interest Brokerage and Underwriting commission.	11% per annum. 12 paise and 38 paise respectively per Rupees 100/-.

2. This issues with the prior concurrence of F.D. obtained vide Dy. No. 141-Fin-8/88, dated the 29th January, 1988.

Shimla-171002, the 8th February, 1988

No. Udyog-II (Chh) 11-11/87.—In exercise of powers as contained in sub-section (1) of Section 7 of the State Financial Corporations Act, 1951 (LXIII of 1951), the

Governor, Himachal Pradesh is pleased to guarantee the repayment of principal and payment of interest thereon in respect of bonds of the value of Rupees 100.00 lacs (Rupees one crore only) with a right to retain 10% extra subscription over the notified amount to be issued by the Himachal Pradesh Financial Corporation with the prior approval of the Industrial Development Bank of India after observing all codal formalities.

2. The Corporation will pay guarantee fee at the usual prescribed rate of 0.5% and commitment charges @ 0.1% on the total guaranteed amount and furnish a copy of challan to this department, Finance Department and the Director of Industries within one month from the issue of this notification or the availment of money whichever is earlier.

3. This issues with the prior concurrence of F. D. obtained vide their Dy. No. 141-Fin-8/88, dated the 29th January, 1988.

By order,

O. P. YADAVA.
Commissioner-cum-Secretary.

जिम्ला-2, 3 दिसम्बर, 1991

संस्कृत उद्योग (ख) 9-1/84-स्ट्र.—भारत सरकार की ओरजना के अन्तर्गत निवेशालय उद्योग, हिमाचल प्रदेश में नियुक्तियाँ सैन्यमें आवृत्तिक मैन्यज के कार्य हेतु महा प्रबन्धक (सैन्यज) के पद की नियन्त्रिती की स्वीकृति न होने में के फलस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, और मस्त राम शर्मा, महा प्रबन्धक (सैन्यज) को महा प्रबन्धक, जिना उद्योग केन्द्र, लाहौल-स्पिति के रिक्त पद पर समायोजित करने के तकाल सहृष्ट आदेश करते हैं।

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, यह भी सहृष्ट आदेश करते हैं कि थो मस्त राम शर्मा, महा प्रबन्धक, उद्योग निवेशालय में लाहौल-स्पिति के महा प्रबन्धक के पद के विरुद्ध तैनात किये जाते हैं, जब तक कि लाहौल-स्पिति का रोहतांग इर्दी न खुले।

जिम्ला-2, 26 दिसम्बर, 1991

संस्कृत उद्योग (व)-2-3/87-एस्ट.—जबकि श्री अधिकारी, को सोलन से मण्डी को इस विभाग की अधिसूचना नम संघा दिनांक 16-9-1991, द्वारा स्थानान्तरण किया गया था;

जबकि श्री अधिकारी शर्मा, खनन अधिकारी के उक्त स्थानान्तरण आदेशों को इस विभाग की अधिसूचना सम संख्यक दिनांक 20-11-1991, द्वारा यह किया गया था, और श्री मदन लाल, खनन अधिकारी, को सोलन से मण्डी स्थानान्तरण किया गया था;

अब जबकि श्री मदन लाल, खनन अधिकारी, द्वारा भानीय हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकारण शिमला, में उनके स्थानान्तरण के विरुद्ध याचिका सूच्या: 1724/91 दायर की गई है कि यस पर माननीय हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकारण, शिमला, ने अन्तिरम आदेश दिनांक 22-11-1991, को श्री मदन लाल, खनन अधिकारी के सोलन से मण्डी किये गये स्थानान्तरण पर रोक लगा दी है तथा सोलन में कार्यात रहने के आदेश किये हैं।

आ. राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, माननीय हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकारण, के अन्तिरम आदेशों के पालना हेतु, थी मदन लाल, खनन अधिकारी, के सोलन से मण्डी के स्थानान्तरण आदेशों को रह करने तथा श्री अधिकारी शर्मा, खनन अधिकारी, के सोलन से मण्डी के स्थानान्तरण आदेशों को माननीय स्थायीलय के अधिगारी/अन्तिम आदेश तक बहाल रखने के सहृष्ट आदेश करते हैं।

आदेश द्वारा,
वी. ० वी. ० ट्रान्स.
विमायुक्त एवं सचिव।

IRRIGATION AND PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Shimla-171002, the 30th January, 1988

No. IPH (4)-15/85.—In continuation of this Department Notification of even number dated the 6th October, 1987, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to extend the period of High Level Committee to scrutinise the recurring claims of compensation for the loss of crops, gharats and private land due to diversion of water as a result of construction of Shah-Nehar Project by the Punjab Government upto 31-12-1988.

The Committee may kindly scrutinise/ finalise its recommendations within the aforesaid period and sent its report to the Government before 31-12-1988 positively.

By order,

A. N. VIDYARTHI,
Secretary.

Shimla-2, the 9th February, 1988

No. IPH-4 (1)-41/87.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the High Powered Committee for the purchase of Non-Levy Cement in the Department of Irrigation and Public Health Himachal Pradesh consisting of the following with immediate effect :—

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Minister of State (Welfare and I. P. H.) Himachal Pradesh. | Chairman |
| 2. Secretary (I. P. H.) | Member |
| 3. Secretary (Food and Supplies) | do- |
| 4. Director of Industries, Himachal Pradesh. | do- |
| 5. Special Secretary (Finance) | do- |
| 6. Chief Engineer (I. P. H.), Himachal Pradesh. | Member Secretary. |

The function of the High powered Committee :

- All the proposals for the purchase of Non-Levy Cement of the Department is to be submitted to the Committee for consideration and their recommendation thereof before the case is sent to the Government for approval and expenditure sanction.

By order,

A. K. MOHAPATRA,
Secretary.

LAW DEPARTMENT

OFFICE ORDER

Shimla-2, the 9th February, 1988

No. LLR-B (4) 3/76-II.—In exercise of the powers vested in him under F. R. 25, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to allow Shri George, Assistant District Attorney-cum-PP, to cross the efficiency bar at the stage of Rs. 1200/- in the pay scale of Rs. 825-25-850-30-1000/40-1200/50-1400-60-1580 w. e. f. 1-8-87 thus raising his pay to Rs. 1250/- P. M. w. e. f. 1-8-1987 F. N.

Sd/-
Secretary.

NOTIFICATIONS

Shimla-2, the 17th February, 1988

No. LLR-B (3) 3/74.—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in him under Rule 56(d) of the F. R., is pleased to grant further extension in service for a period of three months from 1-2-1988 to 30-4-1988 in public interest to Shri Shiv Lal Vaidya, Deputy Director (Prosecution) Himachal Pradesh, whereafter he shall stand retired from Government service.

2. This issues with the prior concurrence of the Finance Department obtained *vide* their U.O. No. F-54-Fin (C)-B (7)13/83, dated 18-1-1988.

Shimla-2, the 24th February, 1988

Subject.—Constitution of Departmental Pension Adalat.

No. LLR-A(1)1/87.—In order to ensure that pensionary claims of Government servants settled expeditiously, the Governor Himachal Pradesh is pleased to constitute a Departmental Pension Adalat in the Law Department which shall comprise of the following:

1. Secretary (Law)
2. Joint Director (Prosecution)
3. Deputy Director (Prosecution)
4. Accounts Officer from A. G. Office, if necessary (on special invitation).

2. The following matters shall be considered by the said Departmental Pension Adalat:

1. Cases of the Law Department's retirees where pension/gratuity has not been sanctioned in favour of retirees.
2. Wrong fixation of pension on the initial stage as a result of revision of pension against which a pensioner may have represented to the Department.
3. Other grievances relating to the pensioners of Law Department.
4. Cases of such pensioners of Law Department who may have gone to the court of law for the redress of their grievance, with a view to have their settlement outside the court.
5. Reviewing of pending pension cases in that Department and finding solutions to bring down pendency to minimum and expeditious settlement of pension cases.
6. Monitoring for expeditious settlement of pension cases.
3. The meeting of the said Adalat will be held once every month, if necessary.

शिमला-171002, 11 फरवरी, 1993

संख्या एल 0 एल 0 आर 0 बी (1)-2/78-II.—भारत के राष्ट्रपति, अधियोजन विभाग, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित जिला न्यायवादियों के निम्न प्रकार से तुरन्त स्थानान्तरण के जनहित में सहर्ष आदेश देते हैं:

क्रम अधिकारी का नाम	वर्तमान तेजाती स्थान	प्रस्तावित स्थानान्तरण	टिप्पणी
1. श्री जे 0 सी 0 कपूर जिला न्यायवादी, जिला न्यायवादी, श्री कुलवर्त सर्वतंत्र (वन)।	सतकंता।	सिंह, जिला न्यायवादी के स्थान पर।	
2. श्री कुलवर्त सिंह जिला न्यायवादी, जिला न्यायवादी, श्री के 0 सी 0 सर्वतंत्र।	प्रवर्तन (वन)।	कपूर, जिला न्यायवादी के स्थान पर।	

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव।

माया एवं मंडुकुरि विभाग

प्राधिकृतना

शिमला-2, 29 जनवरी, 1988

संख्या-भाषण-एफ- (4)-2/84.—गजपत्र, हिमाचल प्रदेश निम्न व्यविधियों का इस विभाग की ममतावालक अधिकृतना दिनांक 20-1-1987 द्वारा स्वतन्त्रा में जानियों पर इतिहास नियन्त्रण के लिए गठित स्कीमिंग कमेटी में सदस्य के रूप में मनोनीत करने को सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1. डा० ए० प्रा० बान, प्राधिकारक (इजिहास), हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला। ..मदन्य
2. नियोगांवदर्घन सिंह, लाइब्रेरियन, हिमाचल प्रदेश नियन्त्रण, शिमला ..पदस्य
3. श्री अमर चन्द शर्मा, 115-2 पुरानी मण्डी, मण्डी, हिमाचल प्रदेश। ..पदस्य

उक्त सदस्य उपरोक्त कमेटी के सदस्य होने के नाते उन्हीं शर्मों के अनुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिकी भत्ता लेने के द्रक्ष्यात् होंगे जिनका दैनिक अधिकृतना दिनांक 20-1-1987 के साथ लगे परिणाम में दिया गया है, जिसकी प्रति धनंजय है।

इसे वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश की डायरी संख्या एफ-89-फिन-मी-बी (15)-1-0/87 दिनांक 19-1-1988 द्वारा प्राप्त पूर्व स्वीकृति के साथ जारी किया गया है।

परिणाम “अ”

T. A. AND D. A.

The T. A. and D. A. to the non-official members will be paid in the following manners:

1. (i) (a) TRAVELLING ALLOWANCES:

(b) Journey By Rail:

They will be treated at par with Government servants of the first grade and will be entitled to actual rail fare of the class of the accommodation actually used, but not exceeding the fare to which government servants of the first grade are normally entitled i.e. accommodation of the highest class, by whatever name it may be called, provided on the railway by which the journey is performed.

(ii) Journey By Road:

They will be entitled to actual fare for travelling by single seat in a bus, and if the journey is performed by motor/cycle/scooter mileage allowance at 60 paise per km in plain areas and @ 80 paise per km in the hill areas and if the journey is performed by engaging own car/taxi the member will be entitled to mileage allowance @ Rs. 2/50 per km in hilly areas and @ Rs. 2.50 per km in plain areas.

(iii) In addition to the actual fare or mileage as per item (i) and (ii) above, a member shall draw daily allowance for the entire absence from his permanent place of residence beginning with departure from the place and ending with return to that place, at the same rate and subject to the same terms and conditions as apply to Grade-I officers to the State Government.

2. DAILY ALLOWANCE:

(iv) Non-official members will be entitled to draw daily allowance for each day of the meeting at the highest rate as admissible to a Government servant of the first grade for the respective locality.

(v) In addition to daily allowance for the day(s) of the meeting, a member shall also be entitled to daily allowance for halt on tour at out station in connection with the affairs of the Committee as under:-

- (a) If the absence from headquarter does not exceed Six hours .. Nil.
- (b) If the absence from headquarters exceeds six hours but does not exceed twelve hours .. 70%.
- (c) If the absence from headquarter exceeds Twelve hours .. Full daily.

Daily allowance will be subject to the usual conditions laid down in Supplementary Rules 1973 as amended from time to time.

3. CONVEYANCE ALLOWANCE:

A non-official member, resident at place where the meeting of the committee is held will not be entitled to travelling and daily allowance on the scale indicated above but will be allowed only the actual cost of conveyance hire, subject to a maximum of Rs. 10/- per day. Before the claim is actually paid, the controlling officer should verify the claim and satisfy himself after obtaining such details as may be considered necessary, that actual expenditure was not less than the amount claimed. In case he is not satisfied with the details, he may, at his discretion, limit the conveyance allowance to road mileage.

If such member uses his own car, he will be granted mileage allowance at the rates admissible to officials of the first grade subject to a maximum of Rs. 10/- per day.

The travelling and daily allowances will be admissible to a member on production of a certificate by him to the effect that he has not drawn any travelling or daily

allowance for the same journey and halts from any other government sources.

The non-official members will be eligible for travelling allowance for the journey actually performed in connection with the meeting of the Committee from and to the place of their permanent residence to be named in advance. If any member performs journey from a place other than the place of his permanent residence to attend meeting of the Committee or return to place other than the place of his permanent residence after the termination of the meeting, travelling allowance shall be worked out on the basis of the distance actually travelled or the distance between the place of permanent residence and the venue of the meeting, whichever is less.

The provision of rules 4.17 and 6.1 of the Himachal Pradesh Treasury Rules relating to over payments made to government servants will apply *mutatis mutandis* in the case of over payment made on account of Travelling Allowance to non-official members.

The Director, Language and Culture, Shimla will be Controlling Officer in respect of countersigning of the Travelling Allowance bills of the non-official member and T. A. bills shall also be prepared in his office.

Official Members.—The official members shall be entitled to the T. A. and D. A. according to the rules governing them.

श्री देश द्वारा

महाराज झुज्जन काव,
वित्तायुक्त एवं सचिव।

अम विभाग

ग्राधिसूचना

शिमला-2, 27 फरवरी, 1993

संख्या: 19-8/90-श्रम-V.—भारत के राष्ट्रपति, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17(1) में निहित शब्दों का प्रयोग करने हुए पर्यामीन अधिकारी, श्रम व्यायाम/औद्योगिक अधिकारण, हिमाचल प्रदेश द्वारा निम्नलिखित मासलों में दिए गए अवार्ड्ज को हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित करने के सहर्ष आदेश देते हैं:—

क्रम सं	क्रम नं	ग्राधिसूचित पक्षों का नाम	धारा	टिपणी
1	2	3.	4	5
1.	रेफ-107/91	प्रकाश चन्द बनाम मैसर्ज विद्यार्थ सूपर सिपिनिंग बिल्ज लि 0, नालागढ़ जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।	धारा 10	प्रकाशन हेतु
2.	रेफ-123/90	दिलबहार खां बनाम भैमर्ज ग्राम्यगढ़ ट्रैक्टर लि 0, सैकटर 2, पश्वाण, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।	"	"
3.	रेफ-62/91	जगदीश चन्द व अन्य बनाम बन मण्डल अधिकारी, पालमपुर, जिला कागड़ा, हिमाचल प्रदेश।	"	"
4.	रेफ-106/91	प्रीतम चन्द बनाम —यथोपरि—	"	"
5.	रेफ-13/92	मुरिन्द मिह बनाम अधिकारी सभी नियन्ता निर्माण काल, क्षेत्रीय इंजिनियरिंग कालेज, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।	"	"
6.	रेफ-68/86	तोष चन्द बनाम मैसर्ज वैदा स्टूल प्रौजेक्ट मूरगानी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।	"	"
7.	रेफ-74/92	भगवान दाम बनाम अधिकारी अधिकारी निविल कॉस्ट्रक्शन मण्डल, पात्र ० पी० ए१० ई१० बी०, कुनिहार, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।	"	"
8.	रेफ-23/87	प्रेम मिह रावत बनाम मै० सर्वेचा केवल ग्रा० लि० मेहतपुर, जिला ऊता, हिमाचल प्रदेश।	"	"
9.	रेफ-79/90	सुभाष कुमार बनाम अधिकारी प्रवंधक, ए.च. ०वार ०टी०पी० नाहन, जिला निर्माण, हिमाचल प्रदेश।	"	"

1	2	3	4	5
10.	रैफ-27/88	मर्वशी वीरा मिह व मूरता राम बनाम अवामीय अभियना व धारा 10 प्रकाशन देतु	धारा 10	
		अधिकारी अभियना, शानन पावर हाउस, जागिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हि० प्र०।		
11.	रैफ-93/91	मतनजीत बनाम मौ० जे० के० लैदराइज़ प्रा० लि०, महेतपुर, जिला ऊना, हि० प्र०।	"	"
12.	रैफ-16/90	दलेन विह बनाम मौ० चानना स्टील ट्यूबज़ प्रा० लि०, पटवाण, जिला सोलन, हि० प्र०।	"	"

ग्रामीणनुसार,
प० हीरा,
आयुका एवं नवित्र।

Before Shri R. K. Mahajan, Presiding Officer, Labour Court, Himachal Pradesh, Shimla

Ref. 107/91-

Parkash Chand

..Petitioner.

Versus

M/S Sidhartha Super Spinning Mills, Ltd. Nalagarh, District Solan (H.P.). .. Respondents.

Shri Parkish Chand, Petitioner in person.
Shri Arun Purohit, Authorised Representative of the respondents.

AWARD

1. The parties have arrived at a settlement amicably. The respondent management has agreed to pay Rs. 15,000/- (Fifteen thousand) only to the petitioner in full and final settlement of his claim. In view of this settlement arrived at between the parties amicably, the petitioner has also given up the claim of service with the respondent management forthwith including any other claim which according to the petitioner is not pending at this stage. In the light of the aforesaid settlement arrived at between the parties as per statements made by them in this court to-day and also in the light of the proposals given by this court earlier during its Circuit at Balaghat and accepted by the respondent management at that time, no dispute now survives between the parties. The petitioner has also no objection if the aforesaid amount is deposited in the fixed deposit for a period of one year by the respondent management in the name of the petitioner. The respondent management is directed to ensure under intimation to this court that the aforesaid amount is deposited in the fixed deposit for a period of one year in the name of the petitioner and Fixed deposit pass Book is handed over to him. The petitioner will not be entitled to withdraw this amount for a period of one year from to-day except with the permission of this court in the event of dire necessity. Reference is answered accordingly in terms of the aforesaid settlement arrived at between the parties. Award is passed. Let a copy of this award be sent to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2, for its due publication in the official gazette i.e. H.P. Rajpatra in accordance with the law. The parties are, however, left to bear their own costs of these proceedings. A copy of this award be given to the parties free of costs, if applied for by them. The file be consigned to the record room after its due completion.

Announced on this 1st day of February, 1993, in open court at Shimla.

Seal.

R. K. MAHAJAN,
Presiding Officer,
Labour Court, Himachal Pradesh,
Shimla. 1-2-1993.

Before Shri R. K. Mahajan, Presiding Officer, Labour Court, Himachal Pradesh, Shimla

Ref.-Case-123/90-

Dilbahar Khan

.. Petitioner.

Versus

M/S Eicher Tractors, Ltd., Sector-2, Parwanoo, District Solan (H.P.).

.. Respondents.

Shri A. K. Sharma, Authorised Representative of the petitioner.

Shri V. K. Gupta, Authorised Representative of the respondents.

AWARD

1. The Government of Himachal Pradesh, Shimla via its notification, dated the 17th April, 1990, referred the following dispute to this court for adjudication under section 10 of the Industrial Dispute Act, 1947 (Hereinafter shortly referred to as the 'Act') on failure of the conciliation proceedings between the parties:—

"Whether the action of the management of M/S Eicher Tractors, pvt., Ltd., Sector-2, Parwanoo, District Solan (H.P.) in terminating the services of Sari Dilbahar Khan after taking into consideration the enquiry report is legal and maintainable? If illegal, what relief and amount of compensation, Sari Dilbahar Khan is entitled?".

2. Shri Dilbahar Khan, petitioner was employed by one Shri Abdul Hamid Contractor of the respondent management through one Shri Kamrudin Munshi of the Contractor. In other words, the petitioner alleges that he was employed by the Contractor Shri Abdul Hamid on 23-11-1985 @ Rs.600/- per month for the work to be done in connection with the management of the Eicher Tractors, pvt., Ltd., Parwanoo. The petitioner claims himself to be a trade unionist and as such the respondent framed the false charges against him and thereafter terminated his services on 9-1-1990. He further alleges that no enquiry was conducted by the respondents in consonance with the principles of natural justice. He claims his re-instatement with all the consequential benefits including back wages.

3. The respondent filed the written statement alleging that enquiry was conducted in consonance with the principles of natural justice by appointing Shri V. K. Gupta as the Enquiry Officer and due opportunity was given to the petitioner to defend his case before the enquiry officer but he did not participate in the enquiry proceedings on 23-12-1989 at Parwanoo and was thereafter proceeded *ex parte*. The Enquiry Officer on the charges against the petitioner with respect to beating of one Shri Kamrudin Munshi and other charges regarding not attending duties on 3-10-1989 and 4-10-1989 in heat

treatment furnaces were established against the petitioner by the Enquiry Officer. The enquiry officer also found that the reply to the show cause notice was also not given by the petitioner. After considering the enquiry report, Abaul Hamid Contractor terminated the services of the petitioner as he found the charges were of serious nature and were proved during the course of enquiry. The plea of the second respondent is that there is no relationship of master and servants between the parties. The matter under dispute cannot be adjudicated upon in these proceedings *qua* the respondent management. The allegations of *mala fide* and union activities on the part of the petitioners have been denied, by the respondent No. 2. From the pleadings of the parties the following issues were framed by me on 4-2-1991:—

1. Whether the petitioner has been terminated by not following the principles of natural justice in the matter of holding the enquiry against him? ..(O.P.P.).
2. Relief.

4. FINDINGS ON ISSUES :

Issue No. 1 :

The petitioner has placed on record the evidence of P.W. 1 Shri Dilbahar Khan petitioner as his own witness stating that he was not allowed by the Enquiry Officer to take the help of Shri A. K. Sharma in assisting his case and as such he absented from the enquiry proceedings. He also states that there is another ground also for absenting from the enquiry proceedings in view of non-changing of the enquiry officer on account of lack of his impartial character in conducting the enquiry and he had no faith in him. The respondent management produced and placed on record the enquiry report. Abaul Hamid also made an offer to the petitioner that he would adjust the petitioner at Faridabad on the same pay as there is no work at Parwanoo but the petitioner declined the offer of the respondent management. The respondent management also produced R.W. 1 Shri Kamrudin Munshi supporting the allegations of the respondent management against the petitioner. He further states that the petitioner is working in SOR Company in sector-5, Parwanoo. The respondent of the petitioner has submitted that enquiry was not conducted in consonance with the principles of natural justice, as he was not allowed to assist the petitioner in the enquiry proceedings. I am unable to agree with the petitioner representatives' contention as the petitioner was offered assistance of a co-worker working with the same management. The enquiry was also held at Parwanoo for the convenience of the petitioner but he did not participate in the enquiry proceedings there also on 23-12-89. The venue was shifted from Chandigarh to Parwanoo at the request of the petitioner. The petitioner was aware of the date and did not participate in the enquiry proceedings at Parwanoo on 23-12-1989 intentionally. The statements of the eye witnesses were also recorded by the Enquiry Officer i.e. Gyasudin and Mahinder Pal regarding the misconduct of the petitioner. They have also supported the case of the respondent management/contractor regarding beating and non attending of duties etc. Enquiry report cannot be set aside unless it is unreasonable and perverse. This is not the case in the present enquiry proceedings. Regarding fairness of the Enquiry Officer as alleged by the petitioner, I also find no reasons to hold that it is a biased enquiry merely on the grounds that he happened to conduct this case in the Labour Court as he conducted the enquiry in this case. The petitioner himself admits that he has no dispute with the enquiry officer. There is no bar in Industrial Law regarding conducting enquiry by a senior officer and defending the case by that officer. In the facts and circumstances of this case and considering the attitude and conduct of the petitioner, I find no merits in this case and the same is dismissed. I would advise the union leaders not to allow the *ex-parte* enquiry proceedings to be held forthwith and they would persuade the workers rather educate them to participate in the enquiry proceedings so that the workers could be granted relief in reasonable cases and

ends of justice may be met. I, therefore, for the reasons recorded decide this issue against the petitioner and in favour of the respondent management.

5. RELIEF :

In view of my findings on issues and the reasons recorded, I pass an award in favour of the respondent management and against the petitioner holding the termination of the petitioner fully legal and justified by the respondent management in the acts and circumstances of this case and the petitioner is not entitled to any relief at this stage. Reference is answered accordingly in negative. Let a copy of this award be sent to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2, for its due publication in the official gazette i.e. H. P. Rajpatra in accordance with the law. A copy be given to the parties free of costs, if applied for by them. The parties are, however, left to bear their own costs of these proceedings. The file be consigned to the record room after its due completion.

Announced on this 27th day of January, 1993, at Shimla.

Seal.

R. K. MAHAJAN,
Presiding Officer,
Labour Court, Himachal Pradesh,
Shimla. 27-1-1993.

Before Shri R.K. Mahajan, Presiding Officer, Labour Court, Himachal Pradesh, Shimla

Ref-62/91-

Jagdish chand and others ..Petitioners.

Versus

Divisional Forest Officer, Palampur, District Kangra (H.P.) ..Respondents

Shri Ajay Dogra, Authorised Representative of the Petitioners.

Shri S.L.Sharma, Authorised Representative of the respondents.

AWARD

1. The Government of Himachal Pradesh, Shimla vide its notification, dated the 10th May, 1991, referred the following dispute to this court for adjudication under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Hereinafter shortly referred to as the 'Act') on failure of the conciliation proceedings between the parties:—

"Whether the termination of services of S/Shri Jagdish Chand and Kuldip Kumar workers by the Divisional Forest Officer, Palampur, District Kangra (H.P.) is legal and justified? If illegal, to what relief and amount of compensation, the above daily wages workers are entitled?".

2. The petitioner, Shri Jagdish Chand and the other Shri Kuldip Kumar have grievances against the respondent management that their services were terminated by the respondent management on 2-7-1990 and 10-8-1990 respectively without following the proper procedure as required under section 25F of the Act. Shri Kuldip Kumar's version is that he worked with the respondent management for six years in the nursery as Mali on daily wages and acquired skill in the trade and an experience certificate to that effect was also given to him by the respondent department, which is placed on record. Similarly, Shri Jagdish claims that he was employed a Mali by the respondent department in 1984 and he was shunted out from service on 2-7-1990 arbitrarily. He was also given an experience certificate by the respondent department which is placed on record as Ex-P.W. 2/A .

Shri Kuldip Kumar has admitted that the nursery was wound up. Similarly, Jagdish Chand has deposed that no junior was kept at Marinda Nursery. They pray for their re-instatement with all consequential benefits including back wages.

3. The version of the respondent is that the department required seasonal labour for seasonal work depending upon the availability of funds etc. and other factors. The petitioners were employed in nursery i.e. at Rakh in case of Kuldip Kumar from May, 1985 till August, 1990 as daily wages casual worker with intermittent breaks in service. He was also told verbally to work in the nearby nurseries when there was no work at Rakh Nursery but he declined to do so. Similarly, Shri Jagdish Chand, petitioner, who was working at Nagri was removed on account of reduction of work as he was junior-most. From the pleadings of the parties, the following issues were framed by me on 23-1-1992:—

1. Whether the petitioners have been terminated by the management without any justification? If so, its effect? ..(OPP).
2. Relief.

4. FINDINGS ON ISSUES:

Issue No. 1 :

At the very outset, I would like to point out that with the efforts of this court and reasonable attitude of the respondent department, the petitioner Shri Jagdish Chand has been adjusted at Marinda Nursery by the department though the petitioner wanted to be adjusted within the area very close to his native place which was not at all possible. Marinda is only at a distance of 8 kilometres on foot and 17 kilometres by bus from the native place of the petitioner. Similarly, Shri Kuldip Chand was also adjusted at Rakh Nursery. Mr. Dogra, representative of the petitioners has only submitted that back wages and be awarded and the petitioners be regularised in accordance with the law. The respondent has opposed his contention on the grounds that there are budgetary constraints and it also depends upon the availability of the work. The department has assured that there will not be any termination except in accordance with law. I am unable to accept the submissions of Mr. Dogra on the following reasonings. Firstly, the work of a nursery is of a seasonal nature. Secondly, the department has been offering them the jobs in the nearby nurseries and the petitioners were not inclined to accept the offers. Thirdly, the respondent department has accommodated them to the best possible extent but they were not happy in spite of all this and it is not always possible for the department to accommodate the petitioners at the places of their choice. The Government is to give the work within its limits of economic capacity and right to work is a qualified right depending upon the economic limitations and their factors. The respondent department has also assured that there will not be any termination except in accordance with law. Moreover, I have also found that no junior person to the petitioners has been kept by the respondent department. In view of this, I am of the view that it is not a case of termination but is a case of unwillingness of the petitioners to join as revealed from the material placed on record. I, therefore, see no force in the claim of the petitioners and the same is dismissed. I, therefore, for the reasons recorded decide this issue against the petitioners and in favour of the respondent department.

5. RELIEF:

In view of my findings on issues and the reasons recorded, I pass an award accordingly in favour of the respondent management and against the petitioners. They are not entitled to any relief at this stage. Reference is therefore, answered accordingly in negative. Let a copy of this award be sent to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2, for its due publication in the official gazette i.e. H.P. Rajpatra in accordance with the law. A copy be given to the parties free of

costs, if applied for by them. The parties are, however, left to bear their own costs of these proceedings. The file be consigned to the record room after its due completion. Announced on this 23rd day of October, 1992, at Shimla.

Seal.

R. K. MAHAJAN,
Presiding Officer,
Labour Court, Himachal Pradesh,
Shimla. 23-10-1992.

Before Shri R. K. Mahajan, Presiding Officer, Labour Court, Himachal Pradesh, Shimla

Ref.-106/91

Pritam Chand

.. Petitioner.

Versus

Divisional Forest Officer, Palampur, District Kangra (H.P.) .. Respondents.

Shri Ajay Dogra, Authorised Representative of the Petitioner.

Shri Rakesh Sood, Divisional Forest Officer, Palampur, Authorised Representative of the respondents.

WARD

1. The Government of Himachal Pradesh, Shimla vide its notification, dated the 7th October, 1991, referred the following dispute to this court for adjudication under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter shortly referred to as the 'Act') on failure of the conciliation proceedings between the parties:—

"Whether the action of the Divisional Forest Officer, Palampur, District Kangra (H.P.) in keeping Shri Pritam Chand away from service w.e.f. 10-8-89 to 9-7-1991 without any notice and reasons and then to re-employ him on the same post and place, w.e.f. 10-7-1991, is legal and justified? If not, to what amount of compensation and service benefits, Shri Pritam Chand is entitled?"

2. Shri Pritam Chand, petitioner claims that he was working as a chowkidar on daily wages basis with the respondent department w.e.f. 1986 till 10-8-1989 when he was discharged from duties arbitrarily by the respondents as alleged by him. He further alleges that he has been working honestly, diligently and to the best of his ability and his services were recognised and appreciated. He claims that his services were terminated on 10-8-1989 and he was again re-employed on 10-7-1991 by the respondent department. Keeping him away from service for two years has been described to be illegal by the petitioner. He prays that past services may be regularised as he has completed 240 days of continuous service and he may be given all the consequential benefits including wages of Rs. 37/- per day instead of Rs. 22/- per day on the doctrine of "Equal pay for equal work".

3. The case of the respondent department as appears from the written statement and statement of R. W. 1 Shri Jai Chand Katoch, Forest Ranger is that he was employed as chowkidar on temporary basis till regular chowkidar was appointed vide annexure "B". Annexure "D" shows that the petitioner was offered the work on daily wages elsewhere on the appointment of a regular chowkidar but he declined the offer. The letter is dated 15-3-1991 placed on record. Annexure "E" dated 17-7-1989 is an order from the Divisional Forest Officer, Palampur showing that since a regular chowkidar has been appointed at Kosri and as such the daily wages chowkidar be removed immediately. Annexure "F" shows that the regular chowkidar was appointed. The plea of the department that the petitioner was appointed as daily wages chowkidar and duty of the chowkidar is to protect the property of the department and to look it

after. In other words, it was a make shift arrangement till the appointment of a regular chowkidar by the respondent department. It is also alleged that the petitioner also refused to work in the nursery where he was offered the alternative work. From the pleadings of the parties, the following issues were framed by me on 19-2-1992:

1. Whether the petitioner has been terminated illegally? (OPP).
2. Whether the petitioner has not been paid the wages of chowkidar as alleged? (OPP).
3. Relief.

4. FINDINGS ON ISSUES:

Issue No. 1 & 2:

Both these issues are inter-connected and would be disposed off together in order to avoid the duplicity in discussion.

5. Mr. Dogra has submitted on behalf of the petitioner that the termination of the petitioner's unjustified and he be paid the wages of chowkidar as he was doing the job of a chowkidar with the respondent department. The plea of the respondents is that the petitioner was entitled to the wages of a daily wages labourer and that has already been paid to him during "Make Shift Arrangement". The petitioner has adduced evidence by producing P. W. 1 Sari Pritam Chand, petitioner himself as his own witness and respondent has produced R.W. 1, Shri Jai Chand Katoot, Forest Ranger. The respondent has also placed on record the muster-rolls of the year, 1987 for 10/87 showing that the petitioner was paid emoluments of water and ward and not of chowkidar. Other muster rolls also reflect the same versions of the respondent department. Later on, with the efforts of this court, and the reasonable attitude of the respondent department, the petitioner has been adjusted. I am unable to agree with the contention of the representative of the petitioner that he has been terminated illegally by the respondents. It was a case of *ad hoc* arrangement and such appointment does not confer any right on the petitioner for regularisation especially when the regular incumbent has been appointed. He was made aware of the terms of the appointment. The record also shows that the petitioner was not willing to accept the offer of appointment given to him by the respondents for alternative work. He was only appointed as a temporary labourer. Moreover there is no specific reference regarding determination of the status of the petitioner. In view of his adjustment so his assertion that he was kept away from service, is not correct. I do not find any force in his claim petition on merits or otherwise and the same is, therefore, dismissed. I, therefore, for the reasons recorded decide both these issues accordingly in favour of the respondent department and against the petitioner.

RELIEF:

6. In view of my findings on issues and the reasons recorded, I pass an award accordingly in favour of the respondent department and against the petitioner. The petitioner is not entitled to any relief at this stage. Reference is, therefore, answered accordingly in negative. Let a copy of this award be sent to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2, for its due publication in the official gazette i.e. H.P. Rajpatra in accordance with the law. A copy be also given to the parties free of costs, if applied for by them. The parties are, however, left to bear their own costs of these proceedings. The file be consigned to the record room after its due completion.

Announced on this 23rd day of October 1992 at Shimla.

Seal.

R. K. MAHAJAN
Presiding Officer,
Labour Court, Himachal Pradesh,
Shimla. 23-10-1992.

Before Shri R. K. Mahajan, Presiding Officer, Labour Court, Himachal Pradesh, Shimla

Ref. 13/92—

Surinder Singh

..Petitioner,

Versus

Executive Engineer, Construction Cell, Regional Engineering College, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.) .. Respondent,

Sari Surinder Singh, Petitioner in person.

Non for the respondents.

AWARD

1. The Government of Himachal Pradesh, Shimla vide its notification, dated the 2nd April, 1992, referred the following dispute to this court for adjudication under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter shortly referred to as the 'Act') on failure of the conciliation proceedings between the parties:—

"Whether the termination of services of Shri Surinder Singh, former Morter Mate w.e.f. 18-9-1990 without any reason and without any notice by the Executive Engineer, Construction Cell, Regional Engineering College, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.) is legal and justified? If not to what amount of compensation and service benefits, Shri Surinder Singh is entitled?"

2. The petitioner, Sari Surinder Singh alleged that he was employed by the respondent firstly as beldar upto 22-4-1987 on daily wages and continued upto 25-11-1987. From 26-11-1987, he was given the muster-roll of Morter Mate at the rates prevalent at the relevant times and he worked with the respondent as such upto 10-9-1990. His grievance is that he was shunted out from service by the respondent on 18-9-1990 without any rhyme and reasons. No enquiry was held. No notice was given. No retrenchment compensation was also given to him. He claims back wages as he has completed 240 days of continuous service with the respondent besides the continuity of service. He further says that termination has not been done by following the proper procedure under section 25(F) of the Act.

3. Written statement was filed by the respondents and it has been stated that in November, 1991, offer was given to the petitioner to work as beldar but he declined the said offer and as such he is not entitled for full wages on the principle of, "No work, no pay". The petitioner failed to reply some specifications of ratio of Cement Morter and thereafter he was terminated by the respondent department for his incompetence in the public interest w.e.f. 19-9-1990. It is further alleged by the respondents that he was offered the job of beldar before leaving the service but he was not inclined to work as beldar. The respondent did not attend the Court inspite knowledge of the date and was as such proceeded *ex parte* on 19-11-1992 and 10-12-1992, after framing the issues. The Court vide its order, dated 6-7-1992 directed the respondent management to keep him as a beldar without prejudice to the rights of both the parties in the present dispute and I was informed that the respondent kept him as beldar by virtue of the court order. I have recorded the statement of the petitioner *ex parte* and the petitioner has established his claim by making a statement on oath. There is also certificate on the record showing that the petitioner worked as a Morter Mate. In my view, Morter Mate is higher than the Beldar irrespective of wages and skill. Even Superintending Engineer has found some defects and he should have given memo of explanation to the petitioner and an opportunity to be heard which has not been done in this case. It is also a violation of principles of natural

justice. I, therefore, for the reasons recorded quash and set aside the termination of the petitioner by the respondent management on this ground also as well according to the petitioner, Suresh Kumar, Junior to have been kept by the respondents and according to the petitioner, still one post is lying vacant with the respondent management.

4. RELIEF :

In view of my above findings, I pass an award accordingly in favour of the petitioner and against the respondent department holding the petitioner entitled for the reinstatement alongwith the continuity of service to him in such a manner as it his services were not terminated. He is however, not entitled any back wages except to the compensation of Rs. 2,000/- (Two thousand) only in lieu of back wages and in case he has joined as a beldar in pursuance of this court order, dated 6th July, 1992, the amount be adjusted accordingly. This would, however not, disturb the amount of compensation, only the difference of wages between Master Mate and beldar is to be paid to the petitioner, for the relevant period of the different works done by him from the date of joining reference is answered accordingly in affirmative. Let a copy of this award be sent to the Government of Himachal Pradesh Shimla-2, for its due publication in the official gazette i.e. H. P. Rajpatra in accordance with law. A copy of this award be also given to the parties free of costs, if applied for by them. The parties are, however, left to bear their own costs of these proceedings. The file be consigned to the record room after its due completion.

Announced on this 23rd day of December, 1992 at Shimla.

Seal

R. K. MAHAJAN,
Presiding Officer,
Labour Court, Himachal Pradesh,
Shimla. 23-12-92.

Before Shri R.K. Mahajan, Presiding Officer, Labour Court, Himachal Pradesh, Shimla

Ref. Case-68/86

Teep Chand

.. Petitioner.

Versus

M/s Baira Sieul Project, Surangani, District Chamba, (H. P.) .. Respondents.

Shri Teep Chand, Petitioner in person.
Shri V. K. Gupta, Authorised Representative of the respondents.

AWARD

The Government of Himachal Pradesh, Shimla vide its notification, dated 31-3-1986, has referred the following dispute to this court for adjudication under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter shortly referred to as the 'Act') on failure of the conciliation proceedings between the parties:-

"Whether the termination of services of Shri Teep Chand, Ex-beldar by the Management of M/s Baira Sieul Project, Surangani, District Chamba (H. P.) is justified and in order? If not, to what assistance and exact amount of compensation, Shri Teep Chand is entitled?".

2. The petitioner, Shri Teep Chand claims that he was employed by the respondent management as beldar in the year, 1976 i.e. on 20-5-1976 on daily wages. He was appointed as work-charged on 18-6-1979 in the same capacity on 29-11-1982, as revealed from the statement of the petitioner, he suffered an injury on the damage and was taken to Surangani Hospital for treatment and remained under treatment there from 30-11-1982 to

8-12-1982. He further states that he remained on medical leave upto 7-4-1983 and has been sending leave applications from 14-12-1982 onwards on different dates. He approached the respondent management for joining the duties on 8-4-1983 with a medical fitness certificate. He approached again and even reported to the Executive Engineer of the respondents to join duty but the latter refused to accept the joining report of the petitioner and he handed over his joining report to the Head Clerk against a receipt. Head clerk happened to talk to the Executive Engineer on telephone at Tissa and on receipt of the instructions from the Executive Engineer from Tissa, the petitioner was asked to join at Tissa. He joined on 9-4-1983 at Tissa vide annexure P. 2 placed on record. He has further alleged that he has worked at the residence of the Executive Engineer from 9-4-1983 to 30-4-1983 and he became very upset when he came to know that he was not being marked as present by the authorities. He approached the Sub-Divisional Officer on this aspect and Sub-Divisional Officer told him that he could be marked present from 30-4-1983 onwards only and not prior to that. He represented to the Chief Engineer of the respondent Project on 2-5-1983, vide P. 3 (Annexure) but of no avail. The petitioner states to have been shocked on 24-5-1983 when he received a termination letter from the respondent management. Termination order is dated 5-5-1983. Thereafter he has been running from pillar to post for justice but of no avail. He prays for his re-instatement in the service of the respondent management with all consequential benefits including back wages. It may be mentioned also that the petitioner approached the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh but Hon'ble High Court vide its order placed on record and mentioned in the petition as well dismissed the writ petition filed by the petitioner on the grounds that adjudication was a question of facts and his case may be considered sympathetically. The petitioner has also described his termination illegal arbitrary and unjust as he was not given opportunity to be heard as provided under the standing orders of the Management to explain his absence. The dismissal has also been described as illegal for want of an enquiry in consonance with the principles of natural justice for overstay on leave. It may be mentioned at the very outset that the respondent management employed him before the present termination on sympathetic grounds as he remained absent at different reasons and time mercy was shown to him. I am told that the petitioner has been given mercy treatment four times on earlier occasions for condoning his fault and re-employed him. The respondent management was ready for settlement with the petitioner by paying Rs. 10,000/- (Ten thousand) only to him in full and final settlement of his claim in lieu of service considering the litigious attitude of the petitioner and also to bring harmony and peace but the petitioner declined the offer of the respondent management.

3. The case of the respondent management as revealed from the written statement filed by them as well as from the evidence of Shri Anil Gaikwad, Personnel Manager of the respondents is that the petitioner remained absent for more than 600 days between 18-6-1979 to 23-4-1983 vide copies of the service record placed on record by the respondents vide EX.R.W.1/A. The petitioner never came on duty from 9-12-1982 after the production of the medical certificate from Project hospital w.e.f. 13-11-82 to 8-12-82. On 8-4-1983, the petitioner did not report for duty. The petitioner got entered falsely in the office record an application to the effect that he was not allowed to join duty on 9-4-83. On 23-4-1983, the petitioner was again informed to join duty but he did not join at all. Both parties have placed voluminous correspondence on record, especially the petitioner. After receiving the report from the Assistant Manager to the effect that the petitioner was not working and was absent, his services were terminated by the respondent management. Copy of the report is EX.R.W.1/B. From the pleadings of the parties, the following issues were framed by my learned predecessor on 3-8-1986:-

1. Whether the termination of services of the petitioner are in accordance with the law and the

rules governing his condition of service ? If so, to what effect ? (OPR).

2. Relief

4. Later on, the amended pleadings were filed by the parties and the following additional issue was framed by me on 24-4-1991 :—

A Whether real dispute has been referred, as the petitioner has abandoned the service ? (OPR).

5. FINDINGS ON ISSUES:

Issue No. 1 and 1-A.

Both the above issues are inter-connected and would be disposed off together in order to avoid the duplicity in discussion.

6. Mr. Teep Chand, petitioner has placed on record voluminous correspondence and also has appeared in the witness box as his own witness stating that his services were terminated unlawfully and without justification and he was not taken on duty by the respondent management with a view to harm him. He has also produced P.W. 2, Parkash Chand Sharma, who has stated that he received the copies submitted by the petitioner dated 9-4-1983 as Work Assistant and then submitted the same to the Head Clerk Documents is EX. P. W. 4/A. It is also in his evidence that he cannot say if the petitioner came in office on 8-4-1983 as alleged by him. P.W. 2, Shri Gulam Mohammad is a witness regarding supply of medicines for three days to the petitioner and has proved slip to that effect as EX. P. W. 2/A. It is admitted by the respondent management that he got manipulated the application regarding his joining of duties by him submitting the same to the Head Clerk. Actually, he did not join the duty before the Sub-Divisional Officer or the Executive Engineer. He has made false allegations against the respondent management that he was not allowed to join the duty in the facts and circumstances of the case.

7. The respondent management informed the petitioner on 23-4-1983 to join the duty but he did not join at all. The respondent management took a lenient view and gave him employment on compassionate grounds four times on earlier occasions as mentioned in the earlier part of this award. The management had no remedy except to inform the petitioner to join duty or in the event of his failure to do so, the contract of employment automatically expires. It has been argued by the petitioner that he was not given an opportunity to explain his case before the respondent management. This plea has been coined up by the petitioner afterthought and cannot be accepted, especially taking into consideration the background of his past service record of closure rate of absenteeism. The plea of the petitioner that he was shocked to learn that he was not marked present by the SDO when he was working with the XEN, cannot be believed as the SDO can not dare the superiors, if the petitioner does not join duty even after the receipt of the information as stated by the management's witness, R.W. 1, the only inference is that he is not interested to join the service. The management sent a letter to the petitioner on 23-4-1983 to join duty but he did not join. What more could be expected from the management in such situation 7. This is evident from the termination order served on the petitioner dated 5-5-1983. The respondent management promised in this order to regularise the period of absence of the petitioner from 6-12-1982 to 22-4-1983 on submission of the application supported by a medical evidence certificate by the petitioner which he did not do at all. The petitioner remained silent in May, 1983 and then started giving notice to the respondent management and in the end of June, 1983 for redressal of his grievances. I think that under these circumstances and the situation created by the petitioner besides the evidence adduced in this court, the respondent management is fully justified in terminating the services of the petitioner. The respondent management gave him the opportunities to explain his conduct

by way of informing him from time to time to join duties besides employing him four times on earlier occasions on compassionate grounds in spite of his conduct as mentioned *ibid*. Since he was not interested in joining the duties, the provisions of section 17 of the Model Standing Orders are not attracted in his case. It would be a travesty of justice if a situation is created by a worker and application of section 17 is sought then in such circumstances, it would amount to put a premium on an indisciplined and habitual unbecoming conducts of the worker. In my view, real dispute is nothing but that of the termination of the petitioner by the respondent management which has been upheld above. I, therefore, for the reasons recorded decide both these issues against the petitioner and in favour of the respondent management.

8. RELIEF :

In view of my findings on issues and the reasons recorded, I pass an award accordingly in favour of the respondent management and against the petitioner holding that the petitioner is not entitled to any relief at this stage in the facts and circumstances of this case. Reference is answered accordingly in negative. Let a copy of this award be sent to the Government of Himachal Pradesh Shimla-2, for its due publication in the official Gazette i.e. H.P. Rajapatra in accordance with the law. A copy of this award be given to the parties free of costs, if applied for by them. The parties are, however, left to bear their own costs of these proceedings. The file be consigned to the record room after its due completion.

Announced on this 28th day of January 1993, at Shimla.

Seal.

R. K. MAHAJAN,
Presiding Officer,
Labour Court, Himachal Pradesh,
Shimla 28-1-93.

Before Shri R. K. Mahajan, Presiding Officer,
Industrial Tribunal, Himachal Pradesh, Shimla

Ref.-74/92—

Bhagwan Dass

...Petitioner.

Versus

Executive Engineer, Civil Construction Division,
Himachal Pradesh State Electricity Board, Kunihar,
District Solan (H.P.).
...Respondents.

Shri J. C. Bhardwaj, Authorised Representative of the petitioner.

Shri S. P. Sharma, Authorised Representative of the respondents.

AWARD

The Government of Himachal Pradesh, Shimla vide its notification, dated the 19th August, 1991, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter shortly referred to the 'Act') on failure of the conciliation proceedings between the parties:—

1. "Whether the retrenchment of Shri Bhagwan Dass s/o Shri Jagat Ram by the Executive Engineer, HPSEB, Civil Construction Division, Kunihar w.e.f. 24-5-1990 is legal and justified ? If illegal, to what relief and amount of compensation, Shri Bhagwan Dass is entitled ?".

2. "Whether the action of the Executive Engineer, HPSEB, Civil Construction Division, Kunihar in taking 22 workers back in service and ignoring Shri Bhagwan Dass Mistry is justified and in order ? If not, to what relief and amount of compensation, Shri Bhagwan Dass is entitled ?".

2. Shri Bhagwan Dass, petitioner alleges that he was employed by the respondent management as a mistry I grade on 21-10-1986 and he had enjoyed a good record of service as a mistry. The respondent despite large number of pending construction works on account of paucity of funds issued retrenchment notices dated 24-5-90 to the petitioner along with other co-workers without rhyme and reasons. It is also alleged that no reason was communicated to the workers. Later on, it appears that the Government withdrew retrenchment order *vide letter*, dated 14-8-1990 through its Secretary. In other words, Government expressed unwillingness to retrench the workers and it is further alleged that the petitioner was not taken on duty whereas other 22 workers were taken on back duty and as such the management has committed unfair labour practice. The petitioner prays for his re-instatement with all consequential benefits as the provision of section 25 F&H were not followed by the respondent management.

3. The case of the respondent management is that the respondent along with other workers was served notice of termination but later on, it was withdrawn *vide Ex. RW. 1/A*. It is also pleaded that the respondent was offered job to the petitioner of beldar which was available with him but he declined to accept the offer. From the pleadings of the parties the following issues were framed by me on 15-11-1991.

1. Whether the termination of the petitioner is not justified and legal? (OPP).
2. What is the effect of withdrawal of termination order dated 21-8-1990 *qua* the petitioner by the Management? (OPR).

3. Relief.

4. FINDINGS ON ISSUES:

Both the above issues are inter-connected and would be disposed off together in order to avoid the duplicity in discussion.

5. It is admitted fact that notice of termination was taken back by the respondent management as admitted by Shri Bhagwan Dass, petitioner, who appeared as PW. 1 as his own witness. It is also in dispute that all the co-workers were allowed to join duty *vide Ex. R. 1*. Mr. Bhardwaj's submission that he was not allowed to join the duty and given the work of mason grade-I, cannot be accepted on the following reasons. Firstly, the retrenchment notice was issued as there were no funds available with the respondent management to continue their services. Later on, it was assured by Secretary of the respondent Board *vide Ex. P.W. 1/B* that the workers would not be retrenched as adequate funds would be placed at the disposal of the Chief Engineer of the respondent Board *vide Ex. R.W. 1/A*, it was ordered by the Assistant Executive Engineer, Kunihar that the workers who have not received compensation, they would not be retrenched and would be absorbed on the job. There is a letter, dated 21-8-1990 from the Assistant Engineer, Kunihar to workers that alternative job as daily paid labourers can be made available to them and in this letter, the name of the petitioner also appears. The reason mentioned was absence of sufficient funds. Again the petitioner was also informed to join duty on 25-9-1990 with reference to the earlier letter of dated 21-8-1990 and a time of one week was given to him to join duty failing which the offer was to be treated as cancelled. Bhagwan Singh petitioner did not join. The respondent management is still ready to take him as beldar and adjust him as a mistry depending upon the availability of the work. In my view, the worker is asking something which is not within the means of the management. The management is to offer the job within its economic means and not beyond that. The plea of the Mr. Bhardwaj that the provisions of section 25F and H were not complied with by the management, is not valid as one month's notice as required under the rules was given to the petitioner and that later on the termination notice was withdrawn by the management.

The offer of retrenchment compensation as required under section 25(F) was also made *vide letter*, dated 24-5-1990. Before this event was to happen, the retrenchment notice was withdrawn by the respondent management and offer for alternative job available with the management at that time was made to the petitioner which was not accepted by him and as such the compliance of section 25(F) of the Act has also been fully made. In fact, the termination orders were nullified by the management and the workers including the petitioner were given benefit of adjusting them suitably against the available jobs. In industrial law, the workers are made to work against the particular assignments and as soon as that assignment is over, their services can be terminated by following the proper procedure of section 25(F) etc. If the management has no job work to be given to the workers, the workers cannot compel the management to provide the work against that job. He is only entitled to get the benefit under section 25(F) of the Act. In the facts and circumstances of this case, the worker is not entitled to any relief at this stage. The management is to offer him a job if he likes to work as a beldar as and when available with the management and offered to him depending upon the availability of work with them. I, therefore, for the reasons recorded decide both these issues accordingly in favour of the respondent management and against the petitioner.

6. RELIEF :

In view of my findings on issues and the reasons recorded, I pass an award accordingly in favour of the respondent management and against the petitioner. He is not entitled to any relief at this stage. The parties are left to bear their own costs of these proceedings. A copy of this award be given to the parties free of costs, if applied for by them. A copy be sent to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2, for publication in the official gazette i.e. H.P. Rajpatra in accordance with the law. The file be consigned to the record room after its due completion. Announced on this 22nd day of December, 1992, at Shimla.

R. K. MAHAJAN,
Presiding Officer,
Seal. Labour Court, Himachal Pradesh,
Shimla-2. 22-12-1992.

Before Shri R. K. Mahajan, Presiding Officer
Labour Court, Himachal Pradesh, Shimla

* Ref. Case-23/87

Prem Singh Rawat. . . Petitioner.

Versus

M/S Salecha Cables, Pvt. Ltd., Mehatpur, District Una (H.P.). . . Respondent.

Shri Prem Singh Rawat, Petitioner in person.

Non for the respondents.

AWARD

1. The Government of Himachal Pradesh, Shimla *vide* its notification, dated the 17th January, 1987, referred the following dispute to this court for adjudication under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter shortly referred to as the 'Act') on failure of the conciliation proceedings between the parties:-

"Whether the termination of Shri Prem Singh Rawat by the Management of M/S Salecha Cables, Pvt Ltd., Mehatpur, district Una (H.P.), is justified and if so, to what relief and amount

RELIEF :

6. In view of my findings on issues and the reasons recorded, I pass an award accordingly in favour of the respondent management and against the petitioner. He is not entitled to any relief at this stage in the facts and circumstances of this case. Reference is answered accordingly in negative. Let a copy of this award be sent to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2, for its due publication in the official gazette i.e. Himachal Pradesh Rajpatra in accordance with law. A copy be also given to the parties free of costs, if applied for by them. The parties are, however, left to bear their own costs of these proceedings. The file be consigned to the record room after its due completion.

Announced on this 24th Day of December, 1992,
at Shimla.

Seal.

R. K. MAHajan,
Presiding Officer,
Labour Court, Himachal Pradesh,
Shimla-2, 24-12-1992.

Before Shri R. K. Mahajan Presiding Officer
Labour Court Himachal Pradesh, Shimla

Ref.-27/88

S/Shri Biri Singh and Murta Ram ...Petitioners.

Versus

Resident Engineer and Superintending Engineer,
Shanan Power House, Jogindernagar, District Mandi,
Himachal Pradesh.Respondents.

Shri S. S. Pathania, Authorised Representative of
the petitioners.

Shri Chaturbhuj Garg, Authorised Representative
of the respondents.

AWARD**1. The petitioners have alleged as under:-**

Shri Biri Singh claims that he worked in Shanan Power House, Jogindernagar under various evasions as daily wages worker from 1972 to 1982 and 1987 to 1988. His grievance is that he has been shunted out arbitrarily without chargesheet and enquiry. He further alleges that some juniors have been kept in the employment and he has been ignored. His grievance is also that the management has violated the policy of Electricity Board, Punjab dated 28-7-1986 regarding the conversion of daily rated workers who have put more than 1000 days into work-charged category. He has also alleged that the management has violated the settlement dated 30-1-1988 regarding re-employment. He wants re-instatement with back wages and continuity of service. Similarly, in case of Murta Ram, the workman states that he worked from 1972 to 1984 and his services were terminated without following procedure in 25F of the Industrial Disputes Act, 1947 and policy decision of Electricity Board of Punjab regarding conversion of his service from daily rated worker to work-charged. He also alleges that the management has not implemented the conciliation agreement EX-PW-2/R for regularisation of service which was to be referred by S.E. Shanan Power House, Jogindernagar to General Manager, Shanan Power House, Jogindernagar. He also seeks re-inst. tenent with back wages and continuity of service. Murta Ram was stated to have been shunted out first time in 1984 and Biri Singh on 10-6-1982. It is also stated that both were re-employed for two months in 1987-88.

2. The case of the respondent is that the management neither appointed nor terminated their services. Their simple plea is that the circle in which they were working ceased to function and as such their services were no more

required. It is also disputed that Biri Singh has worked more than 240 days. It is denied by the management that the petitioner worked for more than 240 days. It is also pleaded that the workers left the job voluntarily.

3. From the pleadings of the parties, following issues were framed by my predecessor:-

1. Whether the petition is not maintainable as alleged ? (OPR).
2. Whether the Construction Project became *functus-officio* and the petitioners could not be re-employed by the respondents as alleged ?
3. Whether the retrenchment of the petitioners by the respondents is legally justified and in orders? If not to what effect ? (OPR).
4. Whether the petitioners are entitled to be reinstated as alleged ? If so, to what relief and amount of compensation, they are entitled ? (OPR).

5. Relief :**4. Issue No. 1:**

1. This issue has not been pressed during the course of arguments by the respondents. Once a reference has been made by the Government after applying the mind this Court has to answer in one way or the other. I hold that the reference is maintainable.

5. Issues No. 2, 3 and 4:

Issues No. 2, 3 and 4 are inter-connected and they are disposed off not jointly, duplicity in discussion on facts and law is bound to arise. Mr. Pathania representative of the worker submitted that the procedure of retrenchment under section 25F of the Industrial Disputes Act, 1947 has not been followed. He further submitted that workcharge policy as discussed above has not been implemented *qua* the workers. He describes the termination is illegal on these grounds. He further submits that procedure of 25 H of the Industrial Disputes Act, 1947 has not been followed. The plea of the respondent is that offices in which they were working were abolished. The management has also submitted that the petitioners deserted the job and no question of compensation arises. In my view, the management has not honoured the conciliation agreement PW. 1/C dated 30-1-1988 by virtue of which the case was to be referred of both workers to the General Manager for regularising them on work-charge basis. The conciliation is binding on the management, once a competent authority as a party to it i.e. S. E. C. Mr. B. K. Bhatia Shanan Power House, Jogindernagar. The repeated reminders were sent to the management but of no use as appears from the letter dated 5-3-1988, addressed by the conciliation Officer to the Resident Engineer, Shanan Power House, Jogindernagar.

It is also on record that these workers have served for more than three years as per certificates issued by the department *vide* Ex-PW-2/N consisting of five pages. It is also an admitted fact that no compensation was given as required under section 25F of the Industrial Disputes Act, 1947. It is also on record that so many persons were employed such as Jai Singh, Amar Singh, Puran Chand and Pyar Chand and no other opportunity was given to the petitioners under section 25H read with H. P. Rules framed under the I. D. Act, 1947. It is admitted by RW-1 Shri Kishori Lal from the list Ex-P-1 that eight workers have been made work charged who have completed more than 1000 days. He states that he does not know whether the petitioners completed 1000 days on 31-8-1988. It is also admitted by him that even workers who have completed 500 days, they have been made workcharged in different circles. List has been produced with respect to the working days of the petitioner Shri Biri Singh and it appears that he worked for 429 days from 1975 to 1980. The fact remains that the

Workers have been retrenched without payment of compensation and no notice required under section 25F of the Act was issued. This provision is mandatory and has to be followed in letter and spirit as it is meant for the protection of the workers. Even if the offices in which they were working, were abolished with the completion of job, the management was bound to follow the provision of section 25H of the Act. The management has so violated the spirit of 25F-H of the Act and rule 82 and 83 of the H.P. Industrial Disputes Rules, 1974 (hereinafter shortly referred to as the rules).

I would like to quote the provision of the 25H and rules of the Act.

Section 25 H.—It lays down where any workman is retrenched or are retrenched and the employer proposes to take into his employment any persons, he shall, in such manner as may be prescribed, give an opportunity to the retrenched workmen who are citizens of India to offer themselves for re-employment and such retrenched workmen who offer themselves for re-employment shall have preference over other persons.

Rule 82 : Maintenance of Seniority list of workmen.—The employer shall prepare a list of workmen in the particular category from which the retrenchment contemplated arranged according to the seniority of their service in that category and cause a copy thereof to be pasted on a notice board in a conspicuous place in the premises of Industrial establishment at least seven days before the actual date of retrenchment.

Rule 83 : Re-employment of retrenched workmen : At least ten days before the date on which vacancies are to be filled, the employer shall arrange for the display on a notice board in a conspicuous place of the Industrial establishment details of those vacancies and shall also give intimation of those vacancies by registered post to everyone of all the retrenched workmen eligible to be considered therefore, to the address given by him at the time of retrenchment at any time thereafter.

The management has not produced the record to revert the statement of PW-1 and PW-2 i.e. the petitioners who are illiterate to show that no fresh workers junior to them, have been employed. The management has also not produced seniority list of the workers *qua* other workers. The spirit of the aforesaid rule is that no arbitrariness is shown in the matter of retrenched workers, if they are otherwise suitable for re-employment. The management is bound to offer opportunity of re-employment to the retrenched employees.

In my view, the management has not completed the legal formalities of 25F of the Act while retrenching the workers and also 25H of the I.D. Act, 1947. Their termination is void *ab initio*. The management has also not honoured the commitment arrived at the time of settlement and poor workers have not taken any action under section 29 of the I.D. Act, 1947. The Conciliation Officer also did not take any step. The settlement is binding under section 18 of the I.D. Act, 1947. I do not find any substance in the objections raised by the respondent.

In view of the reasons recorded above, the termination of the petitioners is unjustified and illegal and the same is quashed and set aside. I decide the issues in favour of the petitioners and against the respondent.

RELIEF :

In view of my finding on issues/reasons recorded I set aside the termination orders of the petitioners holding them illegal and unjustified and award compensation in lieu of back wages of Rs. 6,000/- (Rupees Six Thousand) only to each worker in the facts and circumstances of the case. I further order that the workers are re-instated with all consequential benefits of continuity of service and seniority and the management

is ordered further to implement the settlement for the purpose of regularization. The management is not to retrench them except in accordance with law. They would be considered to be in service as if no order of retrenchment has been issued as their termination is illegal. The award on such terms is passed in favour of the petitioners and against the respondent. Reference is answered accordingly in affirmative. Let a copy of this award be sent to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2, for its due publication in the official gazette i.e. H.P. Rajpatra in accordance with law. A copy be also supplied to the parties free of costs, if applied for by them. The parties are, however, left to bear their own costs of these proceedings. The file be consigned to the record room after its due completion.

Announced on this 29th day of December, 1992, at Shimla.

Seal.

R. K. MAHAJAN,
Presiding Officer,
Labour Court, Himachal Pradesh,
Shimla. 29-12-1992.

Before Shri R. K. Mahajan, Presiding Officer,
Labour Court, Himachal Pradesh, Shimla

Ref. Case No. 93/91

Satanjeet.

... Petitioner.

Versus

M/s J. K. Leatheries (P) Ltd., Mehatpur, Una,
District Una (H.P.) ... Respondents.

Shri P. L. Berry, Authorised Representative of the petitioner.

Shri V. K. Gupta, Authorised Representative of the respondents.

AWARD

1. The Government of Himachal Pradesh, Shimla has referred the following dispute to this court for adjudication under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter shortly referred to as the 'Act') on failure of the conciliation proceedings between the parties vide its notification, dated the 22nd August, 1991:—

"Whether the action of the management of M/s J.K. Leatheries (P) Ltd., Mehatpur, Una District, Himachal Pradesh in terminating the services of Shri Satanjeet, Helper on the charges of theft is legal and justified? If not, to what relief and amount of compensation, Shri Satanjeet is entitled?"

2. Shri Satanjeet, petitioner was employed by the respondent management as a packer of leather goods in the year October, 1990. Firstly he served the management as a helper and then as a packer. It is alleged by the petitioner that when he reported for duty on 6-12-1990 at 4 P.M. in second shift, he was told by the Supervisor that he should cut up the scraps near the factory. His grievance is that he had not committed any theft as alleged by the respondents of the Rexine Cloth and false charge has been concocted against him. No enquiry was held. No chargesheet was given for misconduct. No compensation was given. He describes his termination as arbitrary and unjustified. He has also described the letter of his resignation as fictitious alleging that the company obtained so many signatures of the petitioner on the blank papers and later manufactured the record of its own choice. He was not allowed to join duty on 6-12-1990 which is reportedly date of his termination of the services. He prays that he may be reinstated with all the consequential benefits including the back wages.

3. The plea of the respondent management is that the petitioner resigned of his own on 6-12-1990, on 7-12-90 vis à vis Ex. R. 1 which is on record. The resignation was accepted by the respondent management on 8-12-1990 and all dues were cleared on 15-12-1990 as stated by the respondent management and which the petitioner has received. Respondent management has denied all the allegations levelled against them by the petitioner. Rather it has emphatically pleaded that the resignation was submitted to the plant Manager by the petitioner and there is no question of preparing the concocted documents as alleged by the petitioner. From the pleadings of the parties, the following issues were framed by me on 16-5-1992:—

1. Whether termination of the petitioner by the respondent management is legal and justified on the grounds of allegations of theft? (O.P. Parties).
2. Whether the reference is bad as it is not maintainable under section 12(5) of the Industrial Disputes Act, 1947? (OPR).
3. Whether the reference is without any basis in the form in which it has been made? (OPR).
4. Whether no dispute has been raised by the petitioner himself? (OPR).
5. Relief.

FINDINGS ON ISSUES

Issue No. 1

4. Mr. Dogra and Mr. Berry have been representing the petitioner at different intervals. Sometime they appeared and sometime they did not appear before this Court. I have heard the petitioner. The petitioner has told the court that he did not commit any theft as alleged at all. He further submitted that he has signed on the original resignation, the photostat copy of which is Ex. R.1 placed on record. His explanation is that the respondent management got signatures on so many blank papers at the time of his initial recruitment. They used these papers according to their convenience. He has admitted that he signed only the bio-data which was given to the respondent management by him at the time of his recruitment. He also admits that he has received the payment of all his due on 15-12-1990. There is a gap of one week in acceptance of the resignation and payment of dues to the petitioner. The respondent has led evidence regarding the theft allegedly committed by the petitioner of R.W. 1 and R.W. 2. According to Jai Dev, R. W. 1, the respondent management has placed a roll of 90 meters of rexin cloth near the wall and out of which the petitioner cut 5 meters of cloth without permission of the competent authority. He further states that it was a part of duty to cut the roll. He reported the matter to the Supervisor. R.W. 2 states that when the petitioner was asked for cutting the roll and for what purpose he replied the rexin cloth. The reason the petitioner was that he needed it but did not specify the purpose. The matter was reported to the Director who made a verbal enquiry. Thereafter, the petitioner was sent to duty. The petitioner came the next day and submitted his resignation. In my view if the petitioner has committed the theft, the best course to the management was to hold an enquiry in consonance with the principles of natural justice. There is an evidence of theft but there is no specific mentioning in the resignation as to what were the circumstances of the resignation by the petitioner. Theft was committed on 6-12-1990. Resignation was submitted on 7-12-1990 and it was accepted on 8-12-1990 and the dues were cleared by 15-12-1990. Later on the petitioner persuaded the union to lodge a complaint on 23-1-1991 regarding practice of obtaining the signatures on the blank papers by the respondent management which is not substantiated. From the circumstances, it is revealed that if a veil is lifted, then the purpose of resigning was commission of theft

by the petitioner but the gravity was not been concealed by the respondent management. Question not leading evidence under section 11(A) of the Act does not arise as there was no enquiry at all. Resignation does not appear to have been made after taking into consideration the consequences. In view of this technical defect, set-aside the order of termination of the petitioner but do not consider it appropriate to re-instate him as there is a loss of confidence and the respondent management and the petitioner are not in a position to maintain harmonious industrial relations. However, the petitioner is ordered to be paid a sum of Rs. 7,000/- (Seven thousand) only as compensation by the respondent management taking into consideration the facts and peculiar circumstances of this case. I, therefore, for the reasons recorded decide this issue accordingly.

Issues No. 2, 3, and 4

5. These issues have not been pressed during the course of either evidence or the arguments not are the subject matters of the reference. No findings are, therefore, required to be made in respect of these issues. These issues are, therefore, decided accordingly.

RELIEF :

In view of my finding on issues and the reasons recorded, I pass an award accordingly setting aside the termination orders of the petitioners without re-instatement but allowing him a compensation of Rs. 7000/- (Seven thousand) only to him payable by the respondent management. Reference is answered accordingly. Let a copy of this award be sent to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2, for its due publication in the official gazette i.e. H.P. Rajpatra in accordance with the law and a copy be given to the parties free of costs, if applicable by them. No orders as to the costs of these proceedings. The file be consigned to the record room after its due completion.

Announced on this 1st day of January, 1992 at Shimla.

Seal.

R. K. MAHAJAN,

Presiding Officer,

Labour Court, Himachal Pradesh,

Shimla.

1-1-1993.

Before Shri R. K. Mahajan, Presiding Officer,
Labour Court, Himachal Pradesh, Shimla

Ref.-Case-16/90

Dalel Singh

.. Petitioner

Versus

M/s Chanana Steel Tubes, (P) Ltd., Parwanoo, District Solan (H.P.)

.. Respondent

Shri Dalel Singh, Petitioner in person.
Shri Daljeet Singh, Clerk, for the respondents.

AWARD

1. The Government of Himachal Pradesh, Shimla vide its notification, dated the 26th February, 1990 has referred the following dispute to this court for adjudication under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter shortly referred to as the 'Act') on failure of the conciliation proceedings between the parties:—

1. Whether the termination of services of Shri Dalel Singh by the Management of M/s Chanana Steel Tubes (P) Ltd., Parwanoo is legal and maintainable? If illegal, to what relief and service benefits, Shri Dalel Singh is entitled?
2. Whether the action of the management not to implement the settlement, dated 3-10-198

constitutes unfair labour practice under schedule 5th, item No. 13 of the Industrial Disputes Act, 1947 or not ? If yes, what penalty is to be imposed on the employer ?

3. Whether the management has made unfair labour practice under 5th schedule, item No. 5(6) of the Industrial Disputes Act, 1947, terminating the services of Sri Dalel Singh in utter disregard to the principles of natural justice ? If unfair on this account, what penalty is to be imposed on the employer ?

2. The petitioner, Sri Dalel Singh joined with the respondent management as Turner on 7-12-1983 @ of Rs. 900/- per month. He worked with the respondent management for six years. His grievance is that he was induced out by the respondent management from service on 15-9-1989 and was not allowed to join duty. No chargesheet was given, No. compensation was given. No enquiry was held against him in consonance with the principles of natural justice. He further alleges that the respondent management did not want to regularise him as the management feared that the petitioner would form a union and would also claim the terminal benefits. The petitioner approached the Labour Inspector, Parwanoo who he was not allowed to join duty by the respondent management and during conciliation proceedings, it was agreed by the respondent management *vide* Ex. P.W. 1/A dated 3-10-1989 that the petitioner would be taken on duty on 4-10-1989 and his seniority will be kept in tact and further agreed to pay him the half wages for the period of his absence. The settlement was not implemented as alleged by the petitioner and he again approached the Labour Inspector, Parwanoo for redressal of his grievances by way of a demand notice. Ultimately no conciliation proceedings failed and this matter was referred to this court by the Government of Himachal Pradesh, Shimla for adjudication. The petitioner says that he may be re-instated with all the consequential benefits including the back wages. The case was heard before this court in pursuance of the directions assed by the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, Shimla but the management has been playing hide and seek policy sometimes by attending the court and remaining absent for most of the dates. Today, the respondent management has deputed a clerk requesting for an adjournment on account of illness of senior authorised representative of the respondents. It may be mentioned that Company appointed representative, who cross examined the witnesses, of the petitioner, has never produced the evidence of his own. The delaying tactics on the part of the respondent management is not conducive to the norms of justice and the management wants to exhaust the petitioner by not co-operating with this court for expediting the quick disposal of this case. The respondent management has been proceeded *ex parte* on 23-9-1992 as the representative of the company was present on 27-8-1992, i.e. the earlier date. I would proceed to decide this case on the basis of the material and evidence brought on record by the parties.

3. The respondent management has put in a written statement and denied all the allegations against them by the petitioner. It was averred that the respondent management never resiled from implementing the settlement, dated 3-10-1989. In fact, the petitioner himself absented from duties and has made out his case of voluntary abandonment. From the pleadings of the parties, the following issues were framed by my learned predecessor on 28-5-1990:—

1. Whether the termination of service of the petitioner by the respondent management is illegal and invalid ? If so, to what effect ? (OPP).
2. Whether there is any settlement, dated 3-10-89 arrived at in between the parties, as alleged ? (OPP).

3. If issue No. 2 is held in the affirmative, whether non-implementation thereof amounts to unfair labour practice, as alleged ? (OPP).

4. In case, issue No. 1 is decided in the affirmative, whether the petitioner is entitled to be reinstated in service with full benefit of back wages etc., as alleged ? (OPP).

5. Relief.

FINDINGS ON ISSUES

Issues No. 1 and 2 :

4. Both the above issues are inter-connected and would be disposed off together in order to avoid the duplicity in discussion.

5. The petitioner adduced evidence of Shri Dalel Singh, who appeared as his own witness as P.W. 1 and Placed reliance on the settlement, dated 3-10-1989, Ex. P.W. 1/A. The respondent has produced R.W. 1, Shri Daljit Singh, Office Clerk. He states that he was telephonically informed by Shri Bipul Chaudhary, Manager to take the petitioner on duty, if he happened to come but the petitioner did not turn up. Sri Daljit Singh is referring this sequence of events after the settlement placed on record. Daljit Singh, R.W. 1, Office Accounts Clerk states that he has no knowledge whether the petitioner submitted application on 4-10-1989 to the Labour Inspector, Parwanoo informing him of the violation of the settlement by the respondent management. The petitioner submitted that had the management *bonafide* intentions to implement the settlement, dated 3-10-1989, then he would not have filed application before the Labour Inspector, Parwanoo for further conciliation proceedings on which the matter was later on referred to the Labour Court for adjudication. The respondent management also did not show sincere efforts to implement the settlement, dated 3-10-1989 even later on or at the time of the conciliation proceedings. There is nothing on record to show that any registered letter was sent to the petitioner asking him to join duty by the respondent management, in case he was showing reluctance to do so. The conduct of the petitioner shows that he was willing to join duty with the respondent management but it was the respondent management which did not accept him on duty.

6. The respondent management has violated the settlement, dated 3-10-1989 arrived at between the parties in his presence i.e. the Labour Inspector. It means that the settlement was arrived at during the conciliation proceedings and falls within the 5th Schedule item No. 13 of the Act. The Court cannot take any action but action can be initiated by the Labour Commissioner, Himachal Pradesh under section 29 read with section 34 of the Act for breach of settlement and this complaint can be filed before the competent authority. As regards the termination of the petitioner by the respondent management, I find from the record that no enquiry has been conducted against the petitioner in consonance with the principles of natural justice. No chargesheet was served on him. No retrenchment compensation has been given to him as required under section 25(F) of the Act. In view of this, the termination of the petitioner by the respondent management is void *a^b initio*. I, therefore, for the reasons recorded decide both the above issues accordingly in favour of the petitioner and against the respondent management by setting-aside his termination order by the respondent management as if no such order was ever passed.

Issue No. 3 and 4

7. The action of the respondent management amounts to unfair labour practice as discussed above against issues No. 1 and 2. As regards issue No. 4, this issue requires no separate findings.

Relief :

8. In view of my findings on issues and the reasons recorded, I pass an award accordingly in favour of the petitioner and against the respondent management. The petitioner is ordered to be re-instated in the service of the respondent management in such a manner as if no termination order was ever passed by the respondent management against the petitioner. I award to the petitioner a sum of Rs. 20,000 (Twenty thousand) only as the compensation in lieu of back wages with the continuity of service rendered by him with the respondent management. The amount of compensation would be payable by the respondent management to the petitioner within a period of two months from the date of publication of this award in the official gazette i.e. H.P. Rajpatra failing which an interest of 18% would be payable by the respondent management on this amount to the petitioner. Reference is answered accordingly in affirmative. Award is passed in terms of the above. Let a copy of this award be sent to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2, for its due publication in the official gazette i.e. H.P. Rajpatra in accordance with the law. A copy be given to the parties free of costs, if applied for by them. The parties are, however, left to bear their own costs of these proceedings. The file after its due completion, be consigned to the record room.

Announced on this 22nd day of January, 1993, in open court at Shimla.

Seal.

R. K. MAHAJAN,
Presiding Officer,
Labour Court, Himachal Pradesh,
Shimla-22-1-1993.

बहुदेशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 1991

संक्षेप एम 0 पी 0-ए 0(3) 11/76-पार्ट.—हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (अध्यक्ष की शक्ति और अध्यक्षता सदस्यों को सेवाओं के नियन्त्रण और शार्तें) नियम, 1991 के नियम 19 के उपबन्धों के अनुमति में, राज्य सरकार, यह आदेश करता है कि मन्त्रिव (बहुदेशीय परियोजनाएं एवं विद्युत), हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष को बोर्ड के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए यात्रा करना/करने की अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राविकारी होगा और अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, बोर्ड के सदस्यों को बोर्ड के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए यात्रा करने की अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राविकारी होगा और अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, बोर्ड के सदस्यों को बोर्ड के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए यात्रा करने की अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राविकारी होगा।

2. यह भी आदेश किया जाता है कि: न्यूट्र सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, अध्यक्ष और/या बोर्ड के सदस्यों द्वारा किसी विदेश दौर के लिए सरकार वा पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

3. आगे यह भी आदेश किया जाता है कि अध्यक्ष और/या बोर्ड के सदस्यों द्वारा किसी विदेश दौर के लिए सरकार वा पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/
मुख्य सचिव।

[Authoritative English text of the Government Notification No. M. P. P.-A (3) 11/76-Part, dated 7-12-1991 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution].

Shimla-2, the 7th December, 1991

No. MPP-A (3) 11/76-Part.—In pursuance of the provisions of Rule 19 of the Himachal Pradesh State

Electricity Board (Power of the Chairman and terms & conditions of services of the Chairman & Members) Rules, 1991 the State Government is pleased to order that the Secretary (MPP & Power) will be the competent authority to allow the Chairman, H. P. S. E. B. to undertake journey for the discharge of duties of the Board and the Chairman, H. P. S. E. B. shall be the competent authority to allow the members of the Board to undertake journey for the discharge of duties of the Board.

2. It is also ordered that Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh shall be the competent authority to allow the Chairman and/or the members of the Board to undertake tours outside the State in case such tours are proposed to be undertaken in the vehicle of the Board.

3. It is further ordered that any tours abroad by the Chairman and/or members of the Board will need prior approval of the Government.

By order,
Sd/-
Chief Secretary.

शिमला-171002, 30 मार्च, 1993

संख्या विद्युत-छ (5)-24/92.—यहतः भारत के राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना नियम संगिति (एम 0 पी 0 सी 0) जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के छण्ड (सी 0 सी 0) के अध्यान्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक नियम है, के धारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु चर्मसा जल विद्युत परियोजना प्रथम के जलाशय धेत के लिए भूमि अर्जित अपेक्षित करती है। अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अनुर्गत जीरी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में काँचरत सभी अधिकारियों, उनके अधिकारियों और अधिकारियों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और मर्वेशन करने और उप धारा द्वारा अपेक्षित था अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए प्राविकार देते हैं।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए भारत के राष्ट्रपति उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

विवरणी

जिला: चम्बा

तहसील: चम्बा

मुहाल	खसरा नं 0	बी 0 विं 0 विस्तृत		
		3	4	5
प्राहनूद	712	0	3	0
	714	0	7	0
	715	1	19	0
	716	0	7	0
	717	3	6	0
	718	0	4	0
	719	0	1	0
	720	0	3	0
	721	0	2	0
	722	0	2	0

2	3	4	5
723	0	3	0
724	0	3	0
725	0	2	0
726	0	2	0
727	0	12	0
728	0	7	0
729	0	11	0
730	0	7	0
731	0	4	0
733	0	0	8
734	0	0	18
736	0	1	0
737	0	0	13
738	0	1	0
739	0	2	0
740	0	4	0
741	0	2	0
742	0	2	0
743	0	3	0
744	0	1	0
745	0	2	0
746	0	2	0
748	0	6	0
751	2	17	0
752	1	0	0
753	1	9	0
754	4	11	0
755	0	7	0
756	0	4	0
758	0	0	14
759	0	1	0
697/1	3	14	0
704/1	0	6	0
705/1	0	9	0

कित्ता ... 45 25 13 13

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Shimla-2, the 4th February, 1988

No. PBW-2-B (4) 14/17.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to place the services of Shri Raj Kumar, Assistant Engineer presently posted as Assistant Engineer (Design), 9th Circle, Nurpur with the Himachal Pradesh Forest Corporation Limited, Shimla on deputation with immediate effect, for one year in the first instance.

The terms and conditions of deputation will be issued separately.

By order,
Sd/-
Commissioner-cum-Secretary.

"Special Cell"

Shimla-2, the 6th February, 1988

No. 1-98/72-PWD-Vol-V.—Whereas the Joint Integrated Seniority list of Assistant Engineers (Civil), Himachal Pradesh Public Works Department as on 1-11-1966 was declared final and issued *vide* letter No. 1-241/69-P.W.D., dated 6-1-1973;

2. Whereas on the basis of above seniority list of Assistant Engineers (C) the Departmental Promotion Committee for promotion to the posts of Executive Engineers (Civil) Himachal Pradesh Public Works Department was held in Himachal Pradesh Public Service Commission on 27th, 28th and 29th December, 1973 and 11th January, 1974;

3. Whereas on the recommendations of the said Departmental Promotion Committee, 48 Assistant Engineers (Civil), Himachal Pradesh Public Works Department were promoted to the posts of Executive Engineers (Civil), Himachal Pradesh Public Works Department on officiating basis *vide* notification No. 1-98/70-PWD-Vol-II, dated 22-3-1974;

4. Whereas, the Himachal Pradesh Government in the department of Personnel *vide* their O. M. No. 1-19/73-DP(Appit-II), dated 28-9-1973 circulated a judgement of the Supreme Court of India laying down certain principles for refixing the seniority of Government servants;

5. Whereas in accordance with the above judgement of the Supreme Court of India, the integrated seniority of Assistant Engineers (Civil), Himachal Pradesh Public Works Department as on 1-11-1966 was refixed and with the prior approval of Government of India made final and accordingly circulated amongst all concerned *vide* letter No. 1-241/69-PWD-Vol-II, dated 1-7-1987;

6. Whereas as a result of revision of the final joint integrated seniority list of Assistant Engineers (Civil), Himachal Pradesh Public Works Department as on 1-11-1966, it became imperative to review the proceedings of the earlier Departmental Promotion Committees, held on 27th, 28th 29th December, 1973 and 11th January, 1974;

7. Whereas the review Departmental Promotion Committee was held in the Himachal Pradesh Public Service Commission on 18th to 21st January, 1988 and 29th January, 1988 to review the earlier proceedings of the departmental Promotion Committee for promotion to the post of Executive Engineers (Civil), Himachal Pradesh Public Works Department;

8. Now, therefore, on the recommendations of the review Departmental Promotion Committee and in

आदेश द्वारा,
पी० एस० नंगी,
आयुक्त एवं सचिव।

लोक सम्पर्क विभाग
अधिसचिव
शिमला-171002, 18 फरवरी, 1993

सं ० पब-बी(२)-१/८६-III.—इस विभाग की अधिसचिवना समसंबद्ध किनांक 31-७-1992 के क्रम को जारी रखते हुये, हालांकि, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से निम्नलिखित स्थाई महायक लोक सम्पर्क अधिकारियों को जिला लोक सम्पर्क अधिकारियों/मूर्चना अधिकारियों वेतनमान रूपये 2200—4000 (श्रेणी-II) के पद पर तदर्थ सेवाएं दिनांक 1-1-1993 से 30-6-1993 तक वढ़ाने या जब तक ये पद नियमित रूप में न भरे जायें, जो भी पहले ही, को सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1. श्री सी० एस० कपूर
2. श्री आर० एस० नंगी
3. श्री के० एल० रैण
4. श्री रोशन लाल
5. श्री आर० सी० शर्मा

consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to promote the following Assistant Engineers (Civil), Himachal Pradesh Public Works Department to the post of Executive Engineer (Civil), H.P.P.W.D. on regular basis from the dates mentioned against each:—

S/Shri:		
1. T. L. Sharma	22-3-1974	
2. J. R. Kainth	-do-	
3. Amar Nath	-do-	
4. A. K. Bhatia	-do-	
5. Y. R. Kashyap	-do-	
6. Dewan Chand	-do-	
7. D. S. Parmar	-do-	
8. S. K. Aggarwal	-do-	
9. N. P. Vakil	-do-	
10. S. D. Kathuria	-do-	
11. Dilbag Singh	-do-	
12. H. N. Gandhi	-do-	
13. Krishan Lal	-do-	
14. N. C. Trehan	-do-	
15. M. P. Sachdeva	-do-	
16. Thakur Singh	-do-	
17. K. K. Mahajan	-do-	
18. S. P. Sharma	-do-	
19. Mehta Singh	-do-	
20. D. N. Handa	-do-	
21. Raj Kumar Sharma	-do-	
22. P. C. Bisht	-do-	
23. S. N. Bhatia	-do-	
24. Varinder Kapoor	-do-	
25. V. P. Mongra	-do-	
26. B. P. Singh	-do-	
27. Ram Asra	-do-	
28. I. C. Goel	-do-	
29. R. D. Jain	-do-	
30. G. C. Gupta	-do-	
31. I. C. Kapoor	-do-	
32. S. K. Vaidya	-do-	
33. D. V. Handa	-do-	
34. J. S. Roorkee	-do-	
35. Behari Lal	-do-	
36. R. L. Vaidya	-do-	
37. Mohinder Partap	-do-	
38. B. P. Handa	-do-	
39. Sadhu Singh	-do-	
40. R. K. Kaura	-do-	
41. T. C. Bhagoria	8-10-1974	
42. S. S. Juneja	22-3-1974	
43. R. B. Singh	-do-	
44. Yashpal Sharma	-do-	
45. Balwant Rai	-do-	

9. This supersedes all the notifications in this behalf issued previously from time to time.

ATTAR SINGH,
Financial Commissioner-cum-Secretary.

Shimla-2, the 8th February, 1988

No. PBW-I-B (3) 48/77.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer and posting of Shri Lavanya Malhotra, A. E., Shimla Development Authority, Shimla to 5th Circle, Palampur as Assistant Engineer (D) on repatriation with immediate effect in public interest.

2. He is entitled to T. T. A. and joining time as admissible under the rules.

Shimla-2, the 10th February, 1988

No. PBW-2-B-12/79.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the posting of Shri K. K. Sen, Assistant Engineer (Civil) on repatriation from H. P. State Co-operative Bank Ltd., Shimla in Sub-Division, Jassor against the vacant post with immediate effect in the public interest.

2. He is entitled to T. T. A. and joining time as admissible under the rule,

By order,
A. K. MAHOPATRA,
Commissioner-cum-Secretary.

Shimla-2, the 10th February, 1988

No. PBW (B&R) 26(B) (95)/86.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute Shimla Art and Heritage Committee with immediate effect. The Constitution of the Committee will be as under:—

- | | | Chairman
Vice-Chairman
Member |
|--|--|-------------------------------------|
| 1. Chief Minister | | |
| 2. Minister of State (B&R) | | |
| 3. Chief Secretary | | |
| 4. F. C.-cum-Secretary (Art, Language and Culture) | | -do- |
| 5. Secretary (Urban Development and LSG) | | -do- |
| 6. Director (Art, Language and Culture) | | -do- |
| 7. Mayor, M. C., Shimla | | <i>Non-Official Member</i> |
| 8. Shri Harbhajan Singh, M.L.A., Shimla | | -do- |
| 9. Mr. Bani Prasano (Artist) | | -do- |
| 10. President, Himalayan Environment Group | | -do- |
| 11. President and Secretary, INTACH, Shimla | | -do- |
| 12. Senior Architect | | -do- |
| 13. Prof. Moitra, Town Planner, Delhi | | <i>Outside expert</i> |
| 14. Prof. B. N. Goswami, Head of Department of Fine Arts, Panjab University, Chandigarh | | -do- |
| 15. Director, TCPO | | <i>Member-Secretary.</i> |
| 2. The Function of the Committee will be as under:— | | |
| (i) To identify the distinct characteristics of Shimla's architecture in the context of her history and built heritage. | | |
| (ii) To suggest a range of architectural Styles consistent with Shimla's distinct architectural Character and heritage so that new construction can be regulated to be in harmony with her distinct character. | | |
| (iii) To suggest guide lines in specific terms on the basis of which facades, roof paints, colour-schemes of the buildings, designs of hoarding etc. can be regulated. | | |
| (iv) To examine all other matters relating to the preservation, enhancement and modifications of Shimla's cultural and built heritage in harmony with her past and further beautification of Shimla and suggest appropriate measures. | | |
| (v) To formulate appropriate regulatory measures to ensure preservation of Shimla's heritage and harmonisation of new construction activities repairs, renovations and all other activities connected with exterior-design of the buildings of Shimla with her heritage. | | |

A. K. MAHOPATRA,
Commissioner-cum-Secretary.

Shimla-2, the 24th February, 1988

No. PBW-2 (B) 6/87.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to promote Shri Ram Lal Sharma, Junior Engineer (Horticulture), H. P. P. W. D. to the post of Assistant Engineer (Hort.) in the pay scale of Rs. 940-30-1000/40-1200/50-1400/60-1700-75-1850 purely on *ad hoc* basis from the date of his taking over the charge of the post.

2. The *ad hoc* appointment will not confer on him any right of seniority/continuity as Assistant Engineer (Hort.).

3. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the posting of Shri Ram Lal Sharma,

as Assistant Engineer (Horticulture) in the newly created H. P. P. W. D. Horticulture Sub-Division, Bilaspur against the vacant post.

शिमला-2, 28 नवम्बर, 1991

संख्या ०१० बी० डब्ल्यू०१ बी० (२)-१/७७.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश की समसंबद्धक अधिकारी, दिन क २९-१०-१९९१ ग्रा० आंशिक संयोग करते हुए, श्री आर० ई० कौड़ल, अधीकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नति किए जाने पर मन्त्री अभियन्ता (उत्तर), हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, अभियन्ता के कार्यालय में तैनात किया गया था, को मुख्य अभियन्ता (दिविल), हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिमला के कार्यालय में सतकंता अधिकारी के रिक्त पद पर तत्काल जनहित में समायोजित करने के महर्व आदेश देते हैं।

शिमला-2, 10 दिसंबर, 1991

स० लो० नि० वि० (क) २ (बी०) ६-१/९१.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, श्री आर० पी० आचार्य, महायक अभियन्ता (सिविल) को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से निचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में आवंटित करने के सहर्व आदेश करते हैं।

2: राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की समसंबद्धक अधिकारी, दिनांक २९-८-९१ को आंशिक रू० से संयोगित करते हुए श्री आर० पी० प्रचार्य, सहायक अभियन्ता (पिविल) जोकि विभाग विभाग, अभियन्ता से लोक निर्माण उप-मण्डल, आनंदार के लिए स्थानान्तरणाधीन थे को निचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में बतौर महायक अभियन्ता के रिक्त पद के तहत निचाई एवं जन स्वास्थ्य उप-मण्डल, चंडियार में तत्काल जनहित में व्यायोजित करने के महर्व आदेश करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
वित्तायुक्त एवं सचिव।

शिमला-171002, 6 जनवरी, 1993

संख्या १-७/७३-री०डब्ल्यू०१०-भा०ग-II.—भारत के राष्ट्रपति महोदय, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित महायक अभियन्ता (पिविल) को तदर्थे आधार पर अधिकारी अभियन्ता (विद्युत) के पद पर बैतनमान ₹० ३०००—४५०० में पदोन्नति करने के महर्व आदेश देते हैं:—

- श्री जे० के० खना, डिप्लोमा होल्डर
- श्री भारतेन्दु कपूर, स्नातक

2. यह आदेश उ० नियि से लागू होगे जिस नियि से उत्तर अधिकारी अभियन्ता कार्यभार ग्रहण करेंगे।

3. यह भी स्टडी किया जाता है कि पदोन्नति विशुद्ध रूप से तदर्थे आधार पर की जा रही है और इस तदर्थे पदोन्नति से अधिकारी को बरिष्ठता तथा नियमित पदोन्नति का कोई हक्क हासिल नहीं होगा।

4. सरकार उ० तदर्थे पदोन्नति को रद्द करने तथा उसे वापिस उत्तीर्ण पद पर भेजने का अधिकार सुरक्षित रखती है जिस पद पर में उसे पदोन्नति किया जा रहा है।

5. भारत के राष्ट्रपति महोदय, उपरोक्त अधिकारी अभियन्ताओं (विद्युत) को पदोन्नति के उत्तरान् हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित विद्युत मण्डलों में तैनाती के जनहित में महर्व आदेश देते हैं:—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	तैनाती स्थान
१	२	३
१.	श्री जे० के० खना	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, विद्युत मण्डल न०-II, शिमला रिक्त स्थान पर।

१	२	३
२.	श्री भारतेन्दु कपूर	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, विद्युत मण्डल, मण्डो रिक्त स्थान पर।

उत्तर अधिकारी प्रथमे-प्रथमे तैनाती स्थान पर तुरन्त कार्यभार ग्रहण करेंगे और कार्यभार ग्रहण करने को मूल्यना इस विभाग को मर्ज़ेंगे।

शिमला-2, 15 जनवरी, 1993

संख्या १-४३/७५-पी० डब्ल्यू०१०-वोल-II.—भारत के राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित महायक अभियन्ता (पिविल) को तदर्थ आधार पर अधिकारी अभियन्ता (पिविल) बैतनमान रूप से ३०००—४५०० में पदोन्नति करने के महर्व आदेश देते हैं। यह आदेश उम तियि से लागू होंगे जिस तियि में यह अधिकारी पदोन्नति पद पर कार्यभार सम्भालेंगे:—

- श्री ललित कुमार वैद्य, स्नातक
- श्री माधो प्रसाद लोहिया, डिप्लोमा प्राप्त
- श्री कमलेश कुमार गुप्ता, स्नातक
- श्री प्रकाश चन्द, स्नातक

2. उपरोक्त पदोन्नतियां, जो श्री पी० सी० गोनम, महायक अभियन्ता (पिविल) ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में तिविल रिट पैटीजन संख्या २२४/१९८४ दायर की थी आर० जो बाद में माननीय हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकारण में बतौर टी० ए० २४०/१९८६ स्थानान्तरित हुई थी, के अन्तिम नियम पर मात्र नम्भी जाती। यह भी मण्ड दिया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नतियों का उनके बरिष्ठता एवं नियमिता से कोई मन्त्र नहीं होगा और जब अधिकारी अभियन्ता (पिविल) की नियमित पदोन्नतियों होंगी तब उनकी बरिष्ठता निर्वारित की जाएगी। सभी पदोन्नति अधिकारी एवं उस बारे प्रपता कार्यभार नभालने से पूर्व एक शपथ-नदव भी कार्यग्रहण सूचना के साथ मर्ज़ेंगे।

3. भारत के राष्ट्रपति महोदय, उपरोक्त अधिकारी प्रथमांत्रियों को पदोन्नति के उत्तरान् हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में तैनाती के निम्नलिखित रूप से जनहित में महर्व आदेश देते हैं:—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	तैनाती का स्थान
१	श्री ललित कुमार वैद्य	लोक निर्माण मण्डल, कुमारसैन में रिक्त स्थान पर।
२	श्री माधो प्रसाद लोहिया	नगर एवं ग्रामीण बोजना में प्रतिनियुक्ति पर।
३	श्री कमलेश कुमार गुप्ता	अधिकारी अभियन्ता (रूपांकन), लोक निर्माण मृदगालय, शिमला, रिक्त स्थान पर।
४	श्री प्रकाश चन्द	लोक निर्माण मण्डल, शिलाई (कफोटा), रिक्त स्थान पर।

4. श्री माधो प्रसाद लोहिया, अधिकारी अभियन्ता की प्रतिनियुक्ति की निवन्धन और जर्ते बतौर अधिकारी अभियन्ता अलग से जारी की जाएंगी।

5. सभी अधिकारी अपने-प्रपते तैनाती के स्थान पर तुरन्त कार्यग्रहण करेंगे और कार्यग्रहण सूचना इस विभाग की तुरन्त भर्ज़ेंगे।

शिमला-2, 23 जनवरी, 1993

संख्या १-९२/७२-पी० डब्ल्यू०१०.—भारत के राष्ट्रपति, विभागीय पदोन्नति की सिफारिशों पर श्री वेद भूषण, अनसंधान अधिकारी (सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला) (राजपति वर्ग-II) को बैतनमान रूप से २०००—३५०० में तत्काल नियमित पदोन्नति करने के बारे में सहर्व आदेश देते हैं। नियमित पदोन्नति पर अधिकारी कार्यालय मुख्य

अधिकारी (दक्षिण), हि० प्र० लो० नि० वि०, शिमला-171001, में
ही तैनात रहेंगे।

2. अधिकारी पदोन्नति के प्रथम दो वर्षों में परिवेश पर
रहेंगे।

शिमला-2, 2 फरवरी, 1993

संदेश पी०वी०३० डब्ल्य०-२ वी० (6) 8/91.—भारत के राष्ट्रपति
महोदय, निम्नलिखित अधीक्षण अधियन्ताओं, लोक निर्माण विभाग
हिमाचल प्रदेश को जनहित में तत्काल स्थानान्तरित करने के सहर्ष
आदेश देने हैं:—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम व तैनाती स्थान	स्थानान्तरित स्थान
1.	श्री आर सी० गोयल, अधीक्षण अधियन्ता, हिमाचल प्रदेश कुण्डि विश्वविद्यालय, पालमपुर से प्रत्यावर्तन पर।	अधीक्षण अधियन्ता, छोड़ीय अधियान्तिक महाविद्यालय हमीरपुर में प्रतिनियुक्त पर श्री एस० डी० कौण्डल के स्थान पर।
2.	श्री आई० वी० गोयल, अधीक्षण अधियन्ता (रूपांकन-II), लोक निर्माण मुख्यालय, शिमला-1.	अधीक्षण अधियन्ता, आरवी- टरेशन, सोलन, रिक्त स्थान पर।
3.	श्री एस० डी० कौण्डल, अधीक्षण अधियन्ता, सेक्रेट्री अधियान्तिक महाविद्यालय, हमीरपुर।	अधीक्षण अधियन्ता, अष्टम बूँ लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर, रिक्त स्थान पर।
4.	श्री एस० एस० जुनेजा, अधीक्षण अधियन्ता, हिमाचल प्रदेश ^{प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से प्रत्या- वर्तन पर।}	अधीक्षण अधियन्ता, प्रथम बूँ, मण्डी, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में श्री आर० ए० चौधरी के स्थान पर।
5.	श्री आर० ए० चौधरी, अधीक्षण अधियन्ता, प्रथम बूँ, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मण्डी।	अधीक्षण अधियन्ता (रूपांकन- II), लोक निर्माण मुख्यालय, शिमला में श्री आई० वी० गोयल के स्थान पर।

उक्त अधिकारी अपने-प्रपने स्थानान्तरित स्थान पर तुरन्त प्रस्थान
करेंगे तथा कार्यग्रहण भूमि इस विभाग को भेजेंगे।

शिमला-2, 10 फरवरी, 1993

संदेश पी० वी०३० डब्ल्य०-२ वी० (6) 1/91.—भारत के राष्ट्रपति
महोदय, निम्नलिखित अधिकारी अधियन्ताओं, लोक निर्माण विभाग
को जनहित में तत्काल स्थानान्तरित करने के सहर्ष आदेश देते हैं:—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम व तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित स्थान
1.	श्री एस० एस० कानरा, अधि- कारी अधियन्ता, शिमला विकास प्रशिक्षण।	अधिकारी अधियन्ता (रूपांकन), द्वितीय बूँ, लोक निर्माण विभाग, शिमला में श्री आर० वी० गोयल के स्थान पर।
2.	श्री आर० ए० गुप्ता, अधि- कारी अधियन्ता (रूपांकन), द्वितीय बूँ, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला।	अधिकारी अधियन्ता, शिमला विकास प्रशिक्षण में प्रति- नियुक्ति के आधार पर।
3.	उक्त अधिकारी अपने-प्रपने स्थानान्तरित स्थान पर तरन्त प्रस्थान करेंगे तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भेजेंगे। श्री गुप्ता का प्रतिनियुक्ति को बंदा ज्ञान अख्याल से जारी की जाएंगी।	उक्त अधिकारी का स्थानान्तरित स्थान पर तरन्त प्रस्थान करेंगे तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भेजेंगे।
4.	उक्त अधिकारी का स्थानान्तरित स्थान पर तरन्त प्रस्थान करेंगे तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भेजेंगे।	उक्त अधिकारी का स्थानान्तरित स्थान पर तरन्त प्रस्थान करेंगे तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भेजेंगे।

शिमला-2, 15 फरवरी, 1993

संदेश पी० वी०३० डब्ल्य०-२ वी० (6) 9/90.—भारत के राष्ट्रपति
महोदय, निम्नलिखित अधिकारी अधियन्ताओं, लोक निर्माण विभाग
हिमाचल प्रदेश को जनहित में तत्काल स्थानान्तरित करने के सहर्ष
आदेश देते हैं।

क्र० सं० अधिकारी का नाम व
तैनाती स्थान

स्थानान्तरित स्थान ३

- श्री अरुण महाजन, अधिकारी
अधियन्ता (रूपांकन), लोक
निर्माण, मुख्यालय, शिमला-1.
अधिकारी अधियन्ता (रूपांकन), लोक
निर्माण मण्डल-II, शिमला श्री अमर सिंह
चौहान के स्थान पर।
- श्री अमर सिंह चौहान, अधि-
कारी अधियन्ता (रूपांकन), लोक
निर्माण मण्डल-II, शिमला.
अधिकारी अधियन्ता (रूपांकन),
लोक निर्माण मुख्यालय, शिमला
श्री अरुण महाजन के स्थान पर
तथा आपस में।

2. उपरोक्त अधिकारी तुरन्त अपने-प्रपने स्थानान्तरित स्थान के लिए
प्रस्थान करेंगे तथा कार्यग्रहण सूचना इस विभाग को अविलम्ब भेजेंगे।

शिमला-171002, 17 मार्च, 1993

संदेश पी० वी०३० डब्ल्य०-२ वी० (3)-38/91.—भारत के राष्ट्रपति,
श्री जसवंत लाल छावड़ा, अधीक्षण ग्रेड-I, कार्यालय प्रमुख अधियन्ता,
हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग, शिमला को उनकी अधिविधिता
आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से दिनांक 30-4-1993
(अपराह्न) से सेवा निवृत करने के सहर्ष आदेश देते हैं।

यह: भारत के राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल
प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु
नामतः* भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह
अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न
विवरणों में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त* प्रयोजन के लिए भूमि
का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित
हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की
धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के
राष्ट्रपति इस समय उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारीयों, उनके
कमचारियों और अधिकों को इलाके की किसी भी भूमि
में प्रवेश करने और सरक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित
या अनुमत अन्य सभी कारों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार
देते हैं।

4. कोई भी हितवद्वयक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के
अर्जन पर कोई आपत्ति हो। तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस
(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहिती,
लोक निर्माण विभाग, मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर
कर सकता है।

*गांव लाल, तहसील करसोग, जिला मण्डी में करसोग, परलोग
मुक्त के निर्माण हेतु।

संख्या लो० नि० (ब) 7(1) 63/92.

शिमला, 27 मार्च, 1993.

विवरणी

जिला : मण्डी

तहसील : करसोग

गांव	खराया नं०	क्षेत्र
		धौ० वि० विस्त्रा०
सोल	34/1	0 08 08
422	92/1	0 02 02
	101/1	0 00 09
	103/1	1 15 06
	105/1	0 04 11
	107/1	0 02 13
	107/2	0 01 10
	108/1	0 06 18
	291/1 110/1	0 13 05
	159/1	0 01 16
	172/1	0 00 09
	183/1	0 09 14
	184/1	0 14 08
	205/1	0 12 07
कित्ता ..	14	5 13 16

*गांव करसोग, तहसील करसोग, जिला मण्डी में करसोग-पर्लोग सड़क के निम्नण हेतु।

संख्या लो० नि० (ब) 7(1) 41/92.

शिमला-2, 27 मार्च, 1993.

करसोग/416	397/1	0 00 08
	407/1	0 00 02
	409/1	0 00 15
	410/1	0 00 02
	413/1	0 00 13
कित्ता ..	5	0 02 00

आदेश द्वारा,

एस० एस० सिद्ध,
वित्ताधिकार एवं सचिव।

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Shimla-2, 1st February, 1988

No. Rev. D(A)2-2/82.—In exercise of the powers vested in him under clause (a) of Sub-Section (1) of Section 28 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953 (Act No. 6 of 1954) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to confer upon the following Sub-Divisional Officers, the powers of Collector under the said Act to be exercised by them within the local limits of their jurisdiction as specified against each name below from the date the officers concerned have assumed the charge as such:—

- Shri Dharuv Vashist, Chopal Sub-Division.
Sub-Divisional Officer (C), Chopal.
- Smt. Upma Chaudhary, Shimla (Urban) Sub-Division.
Sub-Divisional Officer (C), Shimla.

By order,
ATTAR SINGH,
Secretary.

PONG DAM CELL
Shimla-2, the 5th February, 1988

No. 5-1/85-Pong Cell.—In partial modification of this Department notification of even number, dated the 24th June, 1985, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to nominate Shri Nand Kumar Chauhan, M. L. A. as a member of the State Level Chamera Project Oustees Rehabilitation Advisory Committee with immediate effect.

2. Other terms and conditions as contained in paras 2-5 of the notification referred to above shall remain unchanged.

By order,

ATTAR SINGH,
Financial Commr-cum-Secretary (Rev.).

Shimla-2, the 19th February, 1988

No. Rev. D (A)2-10/82.—In exercise of the powers vested in him under clause (a) of Sub-Section(1) of Section 28 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953 (Act No. 6 of 1954) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to confer upon the following Assistant Settlement Officers, the powers of Collector under the said Act to be exercised by them within the local limits of their jurisdiction as specified against each name below from the date the officers concerned have assumed the charge as such:—

- Shri Raj Gopal Sharma (Vashist), Kangra and Una Assistant Settlement Officer.
- Shri Manbeer Chand Rana, Una District. Assistant Settlement Officer.

Shimla-2, the 20th February, 1988

No. Rev. D(D) 1-18/85-I.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to hold in abeyance this department Notification No. 12-14/67-Rev. I (II), dated the 21st July, 1980, pending the recommendations of the committee to go into the whole question of the entry in revenue records namely 'Khudro Drakhtan Malkiet Sarkar' constituted *vide* Notification No. Rev. D (D) 1-18/85, dated 22-1-1986.

By order,

ATTAR SINGH,
Secretary.

Shimla-2, the 22nd February, 1988

No. Rev.-A(B) 10-6/87.—The grievances of retired Government servants/employees relating to pensionary matters have been engaging the attention of the Government for some time past. In order to ensure that pensionary claims of Government employees are settled expeditiously, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to set up a Departmental Pension Adalat in the Himachal Pradesh Revenue Department, which shall comprise of the following :—

- (1) The Secretary (Revenue).
- (2) The Commissioners, Kangra, Mandi and Shimla Divisions.
- (3) The Director of Land Records-cum-Director, Consolidation of Holdings, H.P., Shimla-171002.
- (4) The Settlement Officers, Kangra at Dharamshala and Shimla and Kinnaur districts at Sanjauli, Shimla-171006.

2. The Departmental Adalat shall consider the following matters :—

- (1) Cases of the H. P. Revenue Department's retirees to whom pension/gratuity has not been sanctioned.

- (2) Wrong fixation of pension on the initial stage as a result of revision of pension against which a pensioner may have represented to the department.
- (3) Other grievances relating to the pensioner of the department.
- (4) Cases of such pensioners of H.P. Revenue Department, who may have gone to the Court of Law for the redressal of their grievances with a view to have their settlement outside the Court.
- (5) Reviewing of pending pension cases in the H.P. Revenue Department and finding solution to bring down pendency to the minimum and expeditious settlement of pension cases.
- (6) Monitoring for expeditious settlement of pension cases at the level of Departmental Pension Adalat.

3. The retired Government employees will be at liberty either to address their representations to the Finance Department (in the State Pension Adalat) or to the concerned Head of Office/Head of Department who had prepared their pension papers, with copies thereof to be endorsed to the Secretary (Revenue) as well as to the Senior Deputy Accountant General (A & E), Himachal Pradesh. On receipt of representations from the retirees, the concerned Head of Office/Head of Department will prepare detailed background note on each case and thereafter send/place the same before the Departmental Pension Adalat for consideration and decision. In cases, where it is not possible to find out a solution, the same will be referred to the Finance Department (in the State Pension Adalat).

4. The Meeting of the Departmental Pension Adalat will be held once every month.

शिरोमा-171002, 7 दिसंबर, 1991

संघरा रेव-०(बी०) 2-5/90.—वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या फिल (सी०)(बी०) (7) 6/8, दिनांक 4-7-1989 द्वारा सरकार ने प्रत्येक जिनाधीय कार्यालय में कार्यरत अधीक्षक (ग्रेड-II) के एक पद का, पंजाब पद्धति के आधार पर, दिनांक 20-1-1989 में अधीक्षक ग्रेड-I (राजपत्रित श्रेणी-II) वेतनमान 2200—4000 रुपये में, क्रमोन्तर करने का निर्णय दिया है।

2. उपरोक्त निर्णय के फलस्वरूप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश प्रत्येक जिनाधीय कार्यालय में कार्यरत अधीक्षक (ग्रेड-II) के पदाधिकारी को अधीक्षक ग्रेड-I (द्वितीय श्रेणी) वेतनमान रुपये 2200-50-2400-60-2700-75-3000-100-4000 के पद पर तदर्थ आधार पर 6 मास के लिए या ये पद नियमित रूप से भरे जाने नक, जो भी पहले हो, क्रमान्तर करने के तत्काल भव्य आदेश करते हैं :—

1. श्री दीना नाथ, अधीक्षक, उपायुक्त कार्यालय, हरिपुर
 2. श्री निवेद राज शर्मा, अधीक्षक, उपायुक्त कार्यालय, ऊना
 3. श्री नरवा नन्द, अधीक्षक, उपायुक्त कार्यालय, कांगड़ा
 4. श्री मोम दत्त, अधीक्षक, कार्यालय उप-मण्डलाधिकारी (ना०), देहरा, जिला कांगड़ा।
 5. श्री नेक गढ़, अधीक्षक, उपायुक्त कार्यालय, मण्डी
 6. श्री ऊमा जकर, अधीक्षक, उपायुक्त कार्यालय, मिर्जापुर
 7. श्री एम० बी० लाल, अधीक्षक, उपायुक्त कार्यालय, मिर्जापुर
 8. श्री बर्मी शर्मा, अधीक्षक, उपायुक्त कार्यालय, विलासपुर
 9. श्री हेम चन्द, अधीक्षक, उपायुक्त कार्यालय, मण्डी
 10. श्री पीयूष स्वामी, अधीक्षक, उपायुक्त कार्यालय, मण्डी
3. राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उपरोक्त अधिकारियों की नैनाती

निम्न रूप से करने के आदेश भी सहृदय करते हैं :—

क्रम	अधिकारी का नाम	तैनाती का स्थान
1.	श्री दीना नाथ	उपायुक्त कार्यालय, चम्बा
2.	श्री निवेद राज शर्मा	उपायुक्त कार्यालय, ऊना
3.	श्री नरवा नन्द	उपायुक्त कार्यालय, कांगड़ा
4.	श्री मोम दत्त	उपायुक्त कार्यालय, हरिपुर
5.	श्री नेक गढ़	उपायुक्त कार्यालय, निरमौर
6.	श्री ऊमा जकर	उपायुक्त कार्यालय, सोलन
7.	श्री एम० बी० लाल	उपायुक्त कार्यालय, विलासपुर
8.	श्री बर्मी शर्मा	उपायुक्त कार्यालय, शिमोरा
9.	श्री हेम चन्द	उपायुक्त कार्यालय, मण्डी।
10.	श्री पीयूष स्वामी	उपायुक्त कार्यालय, मण्डी।

आदेश द्वारा,
हिमाचल प्रदेश/
वित्ताधिकारी एवं सचिव।

(राजस्व-क)

शिरोमा-171002, 28 दिसंबर, 1992

संघरा रेव-ए(बी) 3-9/91.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, श्री हेम चन्द कपूर, अधीक्षक ग्रेड-II—(राजपत्रित श्रेणी-II), उपायुक्त कार्यालय, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को अधिवेषिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31-1-1993 (प्रपराह) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त होने के आदेश देते हैं।

ओ० पी० यादव,
वित्ताधिकारी एवं सचिव।

शिरोमा-2, 30 दिसंबर, 1992

संघरा रेव-ए(बी) 1-5/85-II.—भारत के राष्ट्रपति, श्री रत्ना राम शर्मा, नायक तहसीनदार, अम्बर, जिला ऊना को तहसीनदार (राजपत्रित श्रेणी-II) वेतनमान रुपये 2100—3700 के पद पर तदर्थ आधार पर 6 मास के लिए या यह पद नियमित रूप से भरे जाने तक जो भी पहले हो, पदोन्तत करने के तत्काल सहृदय आदेश करते हैं।

2. भारत के राष्ट्रपति, श्री रत्ना राम शर्मा को बतौर तहसीनदार, कांगड़ा (जिला लाहौल एवं स्थित), श्री कल्याण चन्द, तहसीनदार के स्थान पर तैनात करने के आदेश भी सहृदय करते हैं।

3. इन पदोन्तति के फलस्वरूप श्री रत्ना राम शर्मा का तहसीनदार पद पर नियुक्त रहने, वरिष्ठता या नियमित पदोन्तति पर अधिकार नहीं होगा।

शिरोमा-2, 8 जनवरी, 1993

संघरा राज० ए(बी) 2-3/76-4.—भारत के राष्ट्रपति, विभागीय पदोन्तति की सिफारिश पर हिमाचल प्रदेश लोक संबंध विभाग के परामर्शनिमाता श्री बखन लाल, अधीक्षक ग्रेड-II को भू-पक्षीकरण अधिकारी के वृद्धि पर श्रेणी-II (राजपत्रित) वेतनमान 2000—3500 रुपये में पदोन्तत करने के भव्य आदेश करते हैं।

राष्ट्रपति पुनः आदेश करते हैं कि श्री बखन लाल, भू-पक्षीकरण अधिकारी के पद पर तैनाती से पूर्व भू-पक्षीकरण अधिकारी, कांगड़ा के अन्तर्गत छ. माह का भू-पक्षीकरण प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

(डी-शाखा)

शिरोमा-2, 14 जनवरी, 1993

संघरा रेव-डी०(ए०) 1-12/91.—भारत के राष्ट्रपति, हिमाचल प्रदेश भू-पक्षीकरण अधिकारी, 1953 (1954 का अधिनियम संख्या 6) की वार्षा 28 की उप-धारा 1 के खण्ड (बी०) में प्रदत्त अधिकारियों तथा इस सम्बन्ध में उपरोक्त अधिकारियों के अन्तर्गत भू-पक्षीकरण अधिकारी का प्रयोग करते हुये श्री मांहन लाल शर्मा, सहायक

ग्रामीण, २२ वर्षों के भवायक समझौता प्रबन्ध थोड़ी का गठितवां महव प्रदान करते हैं, जो कि उनके द्वारा जिता साल । के पर्वाण में उनके लोबाधिकार को स्थानीय सोमाश्रमों के अन्दर अधिकृतवां के जारी होने की तिथि से प्रवाह की जायेगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

शिमला-2, 22 जनवरी, 1993

संभाव रैब-१(बी०) ३-७/७९.—भारत के दादृपति इस विभाग की नमसंदर्भक प्रशिकृतवां, दिनांक ५-१२-१९९२ जिसके अन्तर्गत श्री अग्र बंदु, जिता राजस्व अधिकारी, कुलू का जिता राजस्व अधिकारी, ऊरा के पद पर स्थानान्तरित किया गया था, का जनहित में तत्काल प्रभाव से रद्द करने के सहर्ष आदेश करते हैं।

प्र० ० एम० पिछ०
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

शिमला-171002, 20 मार्च, 1993

मं० देव०-ए (बी०) १-१/९३.—भारत के दादृपति निम्नलिखित तहसीलदारों के स्थानान्तरणों/नियुक्तियों के आदेश जनहित में तत्काल प्रभाव से सहर्ष करते हैं—

१. श्री वी० ए० अत्तरी, नहसीलदार, भू-व्यवस्था, ऊना को स्थानान्तरित करके नहसीलदार, भरताघाट श्री सुभाष चन्द्र पाल के स्थान पर नियुक्त किया जाता है।
२. श्री सुभाष चन्द्र पाल, तहसीलदार, भरताघाट की स्थानान्तरित करके तहसीलदार, कोटखाई, जिला शिमला के रिक्त स्थान पर नियुक्त किया जाता है।
३. श्री जादीश चन्द्र शर्मा, तहसीलदार जिन्हें न.दैन (भू-व्यवस्था) से कुलू स्थानान्तरित किया गया है, को अब तहसीलदार (भू-व्यवस्था), ऊना, श्री वी० ए० अ० अ० री के स्थान पर नियुक्त किया जाता है।
४. श्री भागी रथ हिमालयन, तहसीलदार (भू-व्यवस्था), प्रम्ब, जिला ऊना को स्थानान्तरित करके तहसीलदार, काजा के रिक्त पद पर नियुक्त किया जाता है।
५. श्री सुभाष चन्द्र सकलानी, तहसीलदार, जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी को स्थानान्तरित करके तहसीलदार, संगडाह स्थित रेण्डुका, श्री लायक राम ज्ञामटा के स्थान पर नियुक्त किया जाता है।
६. श्री लायक राम ज्ञामटा, तहसीलदार संगडाह, जिला सिरमोर को स्थानान्तरित करके तहसीलदार, कसीली, जिला सोलन श्री मोती लाल डमालू के स्थान पर नियुक्त किया जाता है।
७. श्री मोती लाल डमालू, तहसीलदार, कसीली, जिला सोलन को स्थानान्तरित करके तहसीलदार, जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, श्री सुभाष चन्द्र सकलानी के स्थान पर नियुक्त किया जाता है।
८. श्री मदन सिंह पुण्डीर, तहसीलदार, कुलू को तहसीलदार, कोटखाई, जिता शिमला के पद पर किया गया स्थानान्तरण रद्द किया जाता है।

आ० पी० यादव,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Shimla-171002, the 2nd January, 1988

No. RD-I-B(2)1/83.—The Governor, Himachal Pradesh on recommendations of the Departmental Promotion

Committee and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to order promotion of Smt. Sheela David to the post of Lady Circle Supervisor (Class-II Gazetted) in the pay scale of Rs. 825-25-850-30-1000/40-1200/50-1400-60-1580 on regular basis with immediate effect and post her as such at Dharamshala (Kangra), Himachal Pradesh.

2. Smt. Sheela David will be on probation for a period of two years from the date of her taking over as Lady Circle Supervisor on regular basis.

Shimla-171002, the 2nd January, 1988

No. RID. I-B (3)27/83.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the promotion of Smt. Usha Chopra, Lady Social Education Organisor as Lady Circle Supervisor in the pay scale of Rs. 825-25-850-30-1000/40-1200/50-1400-60-1580 (Class-II Gazetted) purely as a temporary measure on *ad hoc* basis for a period of six months or till the post is filled up on regular basis in accordance with the Recruitment and Promotion Rules relating to the post of Lady Circle Supervisor whichever is earlier, with immediate effect.

2. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to post Smt. Usha Chopra as Lady Circle Supervisor at Hamirpur (H. P.) against a vacant post.

3. This will not confer any right whatsoever for promotion to the post of L.C.S., Seniority etc. upon Smt. Usha Chopra.

Shimla-2, the 4th January, 1988

No. RDD-II-B(5)-6/86.—Consequent upon the introduction/implementation of Training and Visit System of Agriculture Extension in Himachal Pradesh with the assistance of the World Bank, the following 522 posts of Village Development Co-ordinators (Gram Sewaks) and Panchayat Secretaries are hereby transferred to Agriculture/Horticulture Departments respectively for the smooth implementation of the said project as under:-

No. of posts	Transferred to		Remarks
	I Agri- culture Depart- ment	I Horticul- ture De- partment	
(a)	(b)	(c)	(d)
(i) Filled	257	157	100 From Village Development Co-ordinators. =130
(ii) Vacant	265	165	100 From Panchayat Secretaries. =127
			From Village Development Co-ordinators. =240
Total ..	522	322	200 From Panchayat Secretaries. =25

By order,
Sd./-

Financial Commissioner Dev.-cum-Secretary(R.D.).

ORDERS

Shimla-2, the 22nd February, 1988

No. RDI-B(6) 2/87-5580.—In partial modification of this Department Order No. RD-I-B(6) 2/86, dated

19-10-1987, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to post Shri Padam Singh Block Development Officer (*Ad hoc*) in Rewalsar Block with immediate effect in public interest.

Shimla-2, the 26th February, 1988

No. RD-I-B(6)2/87-6543.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to promote Shri Dev Singh Negi, SE & BPO as Block Development Officer (Class-II Gazetted) in the pay scale of Rs. 825-25-850-30-1000/40-1200/50-1400-60-1580 on *ad hoc* basis. This is a purely temporary promotion and will not confer any right of seniority etc. on him.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to post him as Block Development Officer in Keylong Block, District Lahaul and Spiti in public interest.

V. K. BHATNAGAR,
Director-cum-Joint Secretary.

अधिसूचनां

शिमला-171002, 2 फरवरी, 1993

संख्या ढी० डी० ए०-१०९/८९-याट-१९७.—भारत के राष्ट्रपति, हिमाचल प्रदेश में इस विभाग की अधिसूचना संख्या ढी० डी० ए०-१०६/८९-II, दिनांक ४-७-८९ व संख्या ढी० डी० ए०-१२२/९०-आर० ढी०, दिनांक १०-७-१९९० द्वारा मरुस्थल विकास कार्यक्रम पर गठित राज्य स्तरीय तालमेत्र एवं स्वीकृति समिति को भंग करने के सहृदय आदेश देते हैं।

भारत के राष्ट्रपति, हिमाचल प्रदेश में मरुस्थल विकास कार्यक्रम पर राज्य स्तरीय तालमेत्र एवं स्वीकृति समिति के निम्न प्रकार से निम्नलिखित कार्यक्रम के सहृदय आदेश देते हैं :—

1. मलाहाकार, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष
2. माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला सदस्य
3. मयूरक नवीन (डी० वी० ए० पी०), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मन्त्रालय, ब्लॉक न० ११, मण्डल-६, ढी० डी० ओ० कृष्णलैन, लादी रोड, नई दिल्ली। सदस्य
4. वित्तायुक्त (विकास) एवं सचिव (ग्रा० वि० वि०), हिमाचल प्रदेश सदस्य
5. वित्तायुक्त एवं सचिव (जनजातीय विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-२ सदस्य
6. सचिव (सिचाई एवं जन स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला। सदस्य
7. सचिव (वन). हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला सदस्य
8. उप-कुरुक्षिति, डी० यशवर्ण निह० परमार० उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौगों, मो० न०, हिमाचल प्रदेश। सदस्य
9. उप-कुरुक्षिति, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमुख, हिमाचल प्रदेश। सदस्य
10. मनाहार० (योजना), हिमाचल प्रदेश, शिमला सदस्य
11. मुख्य अधियक्ष (सिचाई एवं जन स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश, शिमला। सदस्य
12. प्रधान, मुख्य अध्यक्षाल (वन), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला। सदस्य
13. मुख्य मन्त्री आरटी, हिमाचल प्रदेश, विलामपुर सदस्य
14. विदेशक, पशुपालन, हिमाचल प्रदेश, शिमला-५ सदस्य

15. निदेशक, कृषि, हिमाचल प्रदेश, शिमला-५	सदस्य
16. निदेशक, उद्यान, हिमाचल प्रदेश, शिमला-२	सदस्य
17. जिलाधीश, लाहौल एवं स्पिति, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश।	सदस्य
18. जिलाधीश, किन्नौरस्थित रिकांग पिंडो, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।	सदस्य
19. अधीक्षण अभियन्ता (सिचाई एवं जन स्वास्थ्य), रिकांग पिंडो, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।	सदस्य
20. परियोजना निदेशक, मरुस्थल विकास परियोजना, काजा, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।	सदस्य
21. परियोजना निदेशक, मरुस्थल विकास परियोजना, पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।	सदस्य
22. अरुणपाल, वन, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।	सदस्य
23. वन मण्डलाधिकारी, काजा, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश।	सदस्य
24. वन मण्डलाधिकारी, पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।	सदस्य
25. अधिकारी अभियन्ता (सिचाई एवं जन स्वास्थ्य), काजा, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।	सदस्य
26. अधिकारी अभियन्ता (सिचाई एवं जन स्वास्थ्य), पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।	सदस्य
27. परियोजना अर्थशास्त्री, मरुस्थल विकास कार्यक्रम राज्य समन्वयक शास्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-२।	सदस्य
28. निदेशक (ग्रा० वि० एवं परियोजना) समन्वयक, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, हिमाचल प्रदेश, शिमला-२।	सदस्य-सचिव
अत्तर सिंह, वित्तायुक्त (विकास) एवं सचिव।	
शिमला-२, 4 मार्च, 1993	
मंगः एस० पृ० ० टी०-४१/८५—इस विभाग की पूर्व अधिसूचना संख्या पृ० ० ए० ०-०४१/८५-आर० ढी० डी० वि०, दिनांक ३ अक्टूबर, 1985 का अधिकरण करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय द्वाईसम संचालन उप-समिति के पुनर्गठन की सहृदय स्वीकृति प्रदान करते हैं :—	
1. मलाहारा (क) माननीय राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश	अध्यक्ष
2. वित्तायुक्त (विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य
3. निदेशक (उद्यान), हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य
4. कार्यकारी अधिकारी खादी एवं ग्रामीणांग बोर्ड, हिमाचल प्रदेश	सदस्य
5. प्रबन्धक निदेशक, लघु उद्योग एवं नियर्यात निगम, हिमाचल प्रदेश	सदस्य
6. प्रबन्धक निदेशक, हस्तकला एवं हथकरशा निगम, हिमाचल प्रदेश	सदस्य
7. मलाहारा (योजना), हिमाचल प्रदेश, शिमला	सदस्य
8. मनस्त परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश	सदस्य
9. लैंडी प्रबन्धक, युको वैक	सदस्य
10. शेत्रीय प्रबन्धक, स्टेट वैक आफ इण्डिया, शिमला	सदस्य
11. शेत्रीय प्रबन्धक, पंजाब नैशनल वैक	सदस्य
12. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, सुन्दरनगर, जिला मण्डी	सदस्य
13. निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश	सदस्य सचिव

उप-समिति के निम्नालिखित मुख्य कार्य होंगे :—

- प्रशिक्षण संस्थानों और मास्टर काप्ट-समेन/दस्तकार जो ग्रामीण युवकों को ट्राईसम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करते हैं के कार्यों को देखना।
- विभिन्न व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता का पता करना तथा उसे प्रशिक्षण संस्थानों के हारा किस तरह सफल प्रशिक्षण का मन्त्रालय हो और उनकी मुद्रूहना के लिए मिकारिंग करना।
- विभिन्न व्यवसायों के लिए उस रहे पाठ्यक्रम की देख-रेख और जहां आवश्यकता हो पाठ्यक्रम में बदलाव लाना।
- जिला ग्रामीण विकास अधिकारियों में प्रशिक्षण संस्थानों को भूमूळे करने हेतु प्राप्त प्रस्तावनाओं का अनुमोदन और अनुमोदित प्रस्तावनाओं का ग्रामीण विकास मन्त्रालय को ग्रामीण कार्यवाही हेतु प्रेषण करना।
- वर्धनित सभूहों के ग्रामीण युवकों में सम्बन्धित कार्यों की उन्नति हेतु कार्य।
- ट्राईसम योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना।
- प्रत्यारोपण योजना को कार्य रूप देना।

अल्प सिंह,
वित्तायुक्त एवं सचिव।

OCIAL AND WOMEN'S WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Shimla-2, the 12th February, 1988

No. Kalyan. A(4)-1/88.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate Shri Rangila Ram Rao, M.L.A. as non-official member in the Gujjar Welfare Board constituted vide this Department notification No. Kalyan-A(4)-8/83, dated 6-12-83 the term of which has further been extended for a period of three years with effect from 6-12-86 vide this department notification No. Kalyan A(4)-15/86, dated 7-7-1987.

2. The above non-official member will be entitled to draw T. A. and D. A. in respect of the journey performed by him in connection with the meetings of the Board as defined in the Annexure circulated vide this department notification No. WLF.A(4)-8/83, dated 12-1983.

AJAY PRASHAD,
Secretary (Welfare).

शिमला-171002, 5 जनवरी, 1993

संख्या कल्याण (बी) 9-4/75.—भारत के राष्ट्रपति, विभागीय पदोन्नति कमेटी को सिफारिश पर, समाज एवं महिला कल्याण विभाग में निम्न जिला कल्याण एवं परिवीक्षा अधिकारियों (श्रेणी-II राजपत्रित) को वेतनमान 2100-50-2400-60-2700-75-3000-100-3700 रुपये में स्थाई करने के आदेश सहृदय तत्काल से करते हैं :—

1. श्री जान सिंह अकुर
2. श्री प्रमर नाथ नर
3. श्री हरि द्वाण कौशल

प्रमिन्दर हीरा,
ग्रामीण एवं सचिव।

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd February, 1988

No. 912/88-Transport.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute a High Powered Committee to go into the entire working of Himachal Road Transport Corporation. The Committee will constitute the following members:—

1. Hon'ble Transport Minister	<i>Chairman.</i>
2. Shri Jagdev Chand, M.L.A.	<i>Member</i>
3. Kanwar Durga Chand, M.L.A.	<i>-do-</i>
4. Shri Hira Singh Pal, M.L.A.	<i>-do-</i>
5. Shri Yogindra Chandra, M.L.A.	<i>-do-</i>
6. Shri Rangila Ram Rao, M.L.A.	<i>-do-</i>
7. Shri Dharam Vir, Vice Chairman, H.R.T.C.	<i>-do-</i>
8. The Secretary (Finance), Govt. of H.P.	<i>-do-</i>
9. The Secretary (Transport), Govt. of H.P.	<i>-do-</i>
10. Commissioner, Transport, H.P.	<i>-do-</i>
11. Shri B. D. Thapar	<i>-do-</i>
12. Managing Director, M.I.D.C. Managing Director, Himachal Road Transport Corporation	<i>Member-Secretary</i>

The terms of reference of the Committee will be as follows:—

1. The Committee would go into the entire working of Himachal Road Transport Corporation including the causes of accidents in the buses of H.R.T.C. and would suggest ways to reduce the accident.
2. The Committee would also suggest the streamlining of the working of H.R.T.C.
3. The Committee would submit its report within the period of 2 months.
4. The non-official members will be entitled to the TA/DA as admissible under the rules.

By order,

S. S. SIDHU,
Commissioner-cum-Secretary.

TOURISM DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th January, 1988

No. 10-8/84-TSM(Sectt).—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute district level "Fossil Park Committee" to devise ways and means for systematic development of Fossil Park, Suketi, District Sirmaur, Himachal Pradesh, as under with immediate effect:—

1. Deputy Commissioner, Sirmaur, Himachal Pradesh.	<i>Chairman</i>
2. Shri Ajay Bahadur Singh, M.L.A., Nahan.	<i>Member</i>
3. Commissioner Tourism, Himachal Pradesh or his representative.	<i>Member</i>
4. Director, Geological Survey of India, Himachal Pradesh Circle, Chandigarh.	<i>Member</i>
5. Executive Engineer (B & R), Nahan	<i>Member</i>
6. Executive Engineer (I&PH), Nahan	<i>Member</i>
7. Himachal Pradesh Tourism Development Corporation officer at Chandigarh.	<i>Member</i>

8. State Geologist, Himachal Pradesh, Shimla.	<i>Member</i>
9. Block Development Officer, Nahan	<i>Member</i>
10. Divisional Forest Officer, Nahan	<i>Member</i>
11. Sub Divisional Magistrate, Nahan.	<i>Member-Secretary</i>

The Committee will hold its meetings from time to time and take necessary steps for the proper development of the Park.

The terms and conditions for TA/DA to the non-official member who is the member of Himachal Pradesh Vidhan Sabha shall be as usual.

**भाग 2—वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मंजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि
उद्योग विभाग (भौमिकीय शाखा)**

नीलामी सूचना

शिमला, 4 अप्रैल, 1993

संख्या उद्योग-भू (वनि-4) लघु-174/92.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला ऊना को लघु बनिं खानों की नीलामी महा-प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊना के कार्यालय में दिनांक 12-5-1993 को प्राप्त: 11.00 बजे की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति ऊनों के पूर्ण विवरण ऊनों तथा खानों से सम्बन्धित अन्य ऊनकारी के लिए महा-प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊना से सम्पर्क स्थापित करें।

भवदीय,
हस्ताक्षरित/
निदेशक, उद्योग।

लोक सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 4 फरवरी, 1993

संख्या 5-128/90-पव-आग-2.—हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 1971 के उप-नियम 1.17 और 1.26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री वीर चन्द्र भैंक, संयुक्त निदेशक, लोक सम्पर्क को निदेशालय लोक सम्पर्क के ग्राहरण एवं विनाश अधिकारी तथा निदेशालय लोक सम्पर्क में कार्यरत तुलीय एवं चूर्णधर्म थेणी जनर्चरियों एवं आवासिक व्याप के कार्यालय अध्यक्ष तथा नियंत्रण अधिकारी की शक्तियों मुख्य शीर्ष 2220—सचना एवं प्रचार के तहत दिनांक 4-2-1993 से श्री ठारेंग डुंगे, उप निदेशक के स्वान पर जो इस मन्त्र अवकाश पर है, प्रदान की जाती है। यह आदेश आकामी मादेशों तक जारी रहेंगे।

देवी प्रसाद जोशी,
निदेशक।

कार्यालय (जिला दण्डाधिकारी, विलासपुर, जिला विलासपुर (हि० प्र०))

अधिसूचना

विलासपुर, 26 मार्च, 1993

मंदस्ता एफ०डी० ए०८०-बी० ए००१० (आपृति) 86-11-1211 से 71.—इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना मंदस्ता एफ०डी० ए०८०-7181 (आपृति) 86-11-445-505, दिनांक 8 फरवरी, 1993 द्वारा आवश्यक वस्तुओं का अधिकतर परचमन विक्रय मूल्य निर्धारण किया गया था कि प्रसंग जारी रखने हुए जो कि हिमाचल प्रदेश ग्रनाइट ग्राजित में दिनांक 20 फरवरी, 1993 को प्रकाशित हो चुकी है तथा हिमाचल प्रदेश जमावारी, मुनाफाकारी निरोधक आदेश, 1977 की वारा 3(1) (ई) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, मैं तथ्य श्रीघर, जिला दण्डाधिकारी, विलासपुर, जिला विलासपुर आदेश जारी करता हूँ कि उपरोक्त अधिसूचना द्वारा निर्वाचित अधिकतर परचमन विक्रेता मूल्य अगले दो माह यानि 20-5-1993 तक लागू रहेगा।

तस्य श्रीघर,
जिला दण्डाधिकारी, विलासपुर, जिला विलासपुर (हि० प्र०)।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

कुल्लू, 3 अप्रैल, 1993

संख्या 3681-3800.—मैं, श्रीवानन्द जीवन, जिला दण्डाधिकारी, कुल्लू आवश्यक वस्तुओं के अधिकतम परचमन मूल्य निर्धारण सम्बन्धी पिछले सभी आदेशों व अधिसूचनाओं का अधीक्षण करते हुए तथा हिमाचल प्रदेश जमावारी, मुनाफाकारी उन्मत्तन आदेश, 1977 जिन्हि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एवं आपृति विभाग की अधिक गतियां संख्या एफ०डी० ए०८० ए०-३ (2)/७७, दिनांक 30-10-80 द्वारा संशोधित हैं कि धारा 3 (1)(ई) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आवश्यक वस्तुओं के सभी कर सहित प्रत्येक के समक्ष दर्शाएं गए अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित करता हूँ:—

क्रमांक	आवश्यक वस्तु का नाम	अधिकतम निर्धारित पूरचून दरें गमी करों सहित
1	2	3
1.	मीट बकरा/मेडा	40.00 रु० प्रति किलोग्राम
2.	भूर्गी डैन्ड	40.00 "
3.	भूर्गी ब्राइनर	45.00 "
4.	मीट सुग्रार	30.00 "
5.	मछली तली हुई	56.00 "
6.	मछली कच्ची	30.00 "
7.	डबल रोटी वजन 400 ग्राम	3.25 थोक भाव तथा 3.50 परचून भाव।

यका हुआ खाना किसी भी होटल/दावे में :

8.	चपाती तम्बरी	1.00 रुपये प्रति
9.	चपाती तबै बाली	0.75 "
10.	परांठा स्टफ़ड	2.50 "
11.	दो परी चना महित	3.50 "
12.	प्रति चुम्बक दाल मञ्जी महित	8.00 "
13.	चावल प्रति ब्लेट	3.00 "
14.	दाल सादी प्रति ब्लेट	2.00 "
15.	दाल फाईड प्रति ब्लेट	5.00 "
16.	मञ्जी सादी प्रति ब्लेट	2.00 "
17.	मञ्जी स्पेशल प्रति ब्लेट	8.00 "
18.	मञ्जी पनीर बाली प्रति ब्लेट	18.00 "
19.	मीट प्रति ब्लेट	16.00 "
20.	मीट रोस्टेड प्रति ब्लेट	18.00 "
21.	आमलेट दो अण्डों का बो	5.00 "
	स्लाईस महित।	
22.	चिकन करी प्रति ब्लेट	18.00 "
23.	दूध कच्चा प्रति किलोग्राम	6.50 "
24.	दूध उबला प्रति किलोग्राम	7.00 "
25.	दूध उबला मीठा महित प्रति	7.50 "
	किलोग्राम।	
26.	दही प्रति किलोग्राम	10.00 "
27.	चाय प्रति कप	1.00 "
28.	धूपका मीट महित प्रति ब्लेट	8.00 "
29.	धूपका मीट महित आधी प्लेट।	5.00 "
30.	मोमो प्रति ब्लेट जिममें पांच	7.00 "
	पीस हो।	

यह भी वादेश देना हूँ कि सभी दुकानदारों को दुकान में महज इतिहास स्थान पर मूल और सूची हिन्दी (देवग्रामी में) प्रदर्शित करना और उस पर दुकानदार/मालिदार/प्रबन्धक के दिनांक सहित हस्ताक्षर हाना अनिवार्य है तथा प्रत्येक दुकानदार ग्राहक को कैशमीरों जारी करना जिसमें दुकानदार का नाम व पता तथा हस्ताक्षर और ग्राहक ने ली गई कीमत का पृष्ठ विवरण हो ।

यह अदिश समूह जिला कुल्लू में हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने से पहले पाह की प्रशंसित कक्ष नाम रहेगा।

जीवानन्द जीवन,
जिला दग्धाधिकारी, कुल्लू ।

कार्यालय गिला दण्डाधिकारी, सानन, जिला शोलान

अंदेशा

सोलन, 24 मार्च, 1993

संघर्ष पेंजी/3-19/87-भारतीय बोर्ड वाहन प्रधिनियम, 1988 (प्रधिनियम नं ०५९ आफ १९८८) की धारा 115 में प्रदत्त शक्तिवां का प्रयोग करते हुए सड़क जो उन्नतायाद्वाश, ग्रीकों के न्यायालय में गुरु होकर पुलिस आना, उप-कोष, तहसील एवं उप-मण्डल कार्यालय ग्रीकों तक जाता है कच्ची 'होने के काणग दुर्घटना होने और सड़क के धर्मसेनों की आशंका से भारी वाहनों के व्रातागमन के लिए प्रतिबंधित घोषित की जाती है।

यह ग्रादेश तुरत लागू होंगे और अगले ग्रादेश तक जारी रहेंगे।

उमा बौद्धी,
मिला दण्डाधिकारी, मोलन ।

INDIRA GANDHI MEDICAL COLLEGE, SHIMLA-1

OFFICE ORDER

Shimla-171001, the 14th December, 1992

No. HFW(MC-A)(A)2-2/79-27155.—In exercise of the powers vested in me under Rule 1.26 of Himachal Pradesh Financial Rules, 1971 (Vol. I), I hereby declare Dr. K. S. Rana, Deputy Medical Superintendent, Indira Gandhi Hospital, Shimla as Drawing and Disbursing Officer under the following heads of accounts in place of Dr. D. S. Puri, Medical Superintendent, Indira Gandhi Hospital, Shimla who is proceeding on winter vacation w.e.f. 15-12-1992 to 28-1-1993:—

- (i) 2210—Medical & Public Health
 - 01—Urban Health Services (Allopathy)
 - 110—Hospital and Dispensaries I. G. Hospital
(N P)
 - (ii) 05—Medical Education, Training and Research
Post Graduate Training of Doctors (NP)
 - (iii) 06—Public Health
Training in Public Health Services
 - (iv) 101—Prevention & Control of diseases Leprosy Eradication Programme (N P)

2. Dr. K. S. Rana Deputy Medical Superintendent will also function as Medical Superintendent, Indira Gandhi Hospital, Shimla during the leave period of Dr. D. S. Puri and shall be Controlling Officer in respect of T. A. claims of Class III and Class IV employees of Indira Gandhi Hospital, Shimla.

Sd/-

*Director of Medical Education
and Research, Indira Gandhi
Medical College, Shimla.*

कायलिय उप-पंजीयक महाकारी समाये (पुर्वोत्तर पण्डित), शिपना-१७१००१

अधिसूचना

शिपला- 1, 5 जनवरी, 1993

मंड्या डी ० ग्रार० ई०-२१-६/८६-कृप०.—जवाहिल इस कार्यनिय
द्वारा जारी अधिसूचना संख्या ३१६४-६६, दिनांक २३-१२-९१ द्वारा
दी सुन्नी तहवील महकारी विपणन नव्या उपभोक्ता मेंव सीमित
के मानीनीत संचालक पाइल की अवधि, दिनांक २२-१२-९२ को
समाप्त हो चकी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को मध्यनक्षत्र रखते हुए मैं, आरा^०
नवं, उप-र्जीषक सहकारी ममायें (पूर्वी मण्डल), शिवपुरा-१
चौचल प्रदेश सहकारी अधिनियम, १९६८ की धारा ३५-ए के
वर्गत प्रदत्त जटिक्यों का प्रयोग करते हुए निलं को दी मूल्नी
तील सहकारी विधान तथा उपभोक्ता संघ सीमित मूल्नी के काय-
लन हैं। मनोनीत संचालक मण्डल के रूप में एक वर्ष की अवधि
प्रबलातान्त्रिक रूप से संचालक मण्डल के गठन तक जो भी पहले
मनोनीत करता है।

1. श्री जीत राम वर्मा, पुत्र श्री मनसा राम, गांव मटेरी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश .. अध्यक्ष ।
 2. श्री नीम कन्द पुत्र श्री टी० आर० वर्मा, गांव धैनो रियोग (झुर्गापुर), तहसील सुन्नी, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश .. संचालक ।
 3. श्री दयम देव पुत्र श्री हेम दत, गांव चबड़ी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला .. "
 4. श्री हुक्क चन्द वर्मा पुत्र श्री जीत राम, गांव दीमान, तहसील सुन्नी, जिला शिमला .. "
 5. श्री बालक राम, गांव गिलडू, डा० खटनोल, तहसील सुन्नी, जिला शिमला .. "
 6. श्री दुर्गा दत शर्मा पुत्र श्री मनी राम, गांव शकरोड़ी, तहसील बुन्नी, जिला शिमला .. "

सरकारी प्रतिनिधि :

1. निरीक्षक सहकारी नमायें, मशोबरा
 2. तहसीनदार, सुन्नी, फ़िला शिमला
 3. विकास खण्ड ग्रंथिकारी, मशोबरा, जिला शिमला

रत्न बन्द गर्भ,
उप-पंजीयक, सहकारी सभायें,
(पुर्वोध मण्डल, शिमना-18)

कायलिंग सहायक पंजीयक, सहकारी सभास, त्रिला मिरमोर, नाहन

कार्यालय आदेश

नाहन, 17 मार्च, 1993

संख्या कोप 3-46/90-1481-34.—जैसा की दि सिरमोर

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति महिला बहुदेशीय सहकारी सभा सिविल, नाहन, नहसील नाहन, जिला सिरमोर सहकारी सभा का कार्य बन्द पड़ा है और सभा लगातार हानियों की ओर बढ़ रही है।

जैसाकि उपरोक्त के सम्बन्ध में सभा के प्रधान को इस कार्यालय के पत्र संखा को 3-46/90-1521, दिनांक 11 मार्च, 1992 द्वारा एक माह के भीतरी स्पष्टीकरण देने हेतु दिया गया था वे जिसका कोई उत्तर कार्यालय में सभा हारा नहीं प्राप्त हुआ।

जैसाकि निरीक्षक नहकारी सभाएं, नाहन ने अपने निरीक्षण पत्र में भी सभा को विघटन में डालने हेतु सिफारिश की है।

ग्रातः मैं, जगतेन्द्र शिंह, यहायक पंजीयक, सहकारी सभाएं जिला सिरमोर, नाहन, हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं, अधिनियम, 1968 (एक्ट नं 03 आफ 1969) की धारा 78 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन सभा को विघटन में डालने के आदेश देता हूं व धारा 79 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरीक्षक महकारी सभाएं, नाहन को विघटक नियुक्त करता हूं तथा मात्र में यह निर्देश देता हूं कि इन सभा को विघटन मध्यस्थी कार्य तीन माह में पूर्ण किया जाव।

जगतेन्द्र शिंह,
यहायक पंजीयक, सहकारी सभाएं,
जिला सिरमोर, नाहन।

INDUSTRIES DEPARTMENT

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER,
DISTRICT INDUSTRIES CENTRE, CHAMBA
HIMACHAL PRADESH

NOTICE UNDER SECTION 24 OF THE ACT

Chamba, the 2nd February, 1991

No. Ind./C/MM/43/861.—Whereas a notice under section 23 of the Himachal Pradesh State Aid to Industries Act, 1971, was served on Shri Tej Singh son of Shri Bhikho Ram Prop. M/s Tej Singh Handloom Industries, Village Parel, P. O. Sultanpur, Tehsil and District Chamba on 6-2-1991, calling upon the said Shri Tej Singh son of Shri Bhikho Ram to pay to me the said sum of Rs. 1998/- (Rupees 1300/- Principal + 698/- interest) upto date on or before 23-10-91 and whereas the said sum has not been paid, I hereby declare that the said sum of Rs. 1140/- (Rs. one thousand one hundred forty only) alongwith interest thereon upto the date of final payment is due and that the property described in the attached schedule is liable for the satisfaction of the said debt.

SCHEDULE

All assets already existed before taking above loan and thereafter raised with the help of above loan by the Proprietor M/s Taj Singh Handloom Industries, V.P.O. Parel, Tehsil and District Chamba (Shri Tej Singh s/o Bhikho Ram and his legal heirs as the case may be).

D. K. SHARMA,
General Manager,
District Industries Centre, Chamba,
District Chamba, Himachal Pradesh.

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER,
DISTRICT INDUSTRIES CENTRE, CHAMBA
HIMACHAL PRADESH

NOTICE UNDER SECTION 24 OF THE ACT

Chamba, the 2nd February, 1993

No. Ind./C/MM/38/862.—Whereas a notice was served on Shri Bhagat Ram s/o Shri Hira Lal of Village and P.O. Masroond, Tehsil and District Chamba on 18-9-1992

under section 23 of the Himachal Pradesh State Aid to Industries Act, 1971, calling upon the said Shri Bhagat Ram to pay to me the said sum of Rs. 2500/- (rupees two thousand five hundred only) and interest thereon upto date on or before 23-10-1992 and whereas the said sum has not been paid, I hereby declare that the said sum of Rs. 2500/- (rupees two thousand five hundred only) alongwith interest thereon upto the date of final payment is due and that the property described in the attached schenule is liable for the satisfaction of the said debt.

SCHEDULE

Immoveable and moveable property exists with Shri Bhagat Ram son of Shri Hira Lal including that raised by way of above loans and such machinery tools etc. installed in the factory premises.

D. K. SHARMA,
General Manager,
District Industries Centre, Chamba,
District Chamba, Himachal Pradesh.

FORM 'L'

(See Rule 52)

CERTIFICATE

Una, the 24th March, 1993

No. Ind/U/Brick Kiln/1848.—In exercise of the powers conferred by rule 52 of the Himachal Pradesh (Concession) Revised Rules, 1971 read with Himachal Pradesh Government Order No. 13-3/70-SI, dated 13th April, 1971.

I, Jai Singh General Manager, District Industries' Centre, Una, hereby certify that a sum of Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand) only is recoverable as arrears of land revenue from M/s Shivalik Gram Udyog Brick workers Tile Industries works Association Village Basdehra, Tehsil and District Una on account of following in respect of royalty for manufacture/sale of pucca bricks w. e. f. 1989-90 to 1992-93.

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Royalty/Deed rent | } 10,000/-upto 1992-93 |
| 2. Surface Rent | |
| 3. Contract Money | |

JAI SINGH

General Manager,
District Industries Centre, Una,
District Una, Himachal Pradesh.

FORM 'L'

(See Rule 52)

CERTIFICATE

Una, the 24th March, 1993

No. Ind/U/Brick.Kiln/1876.—In exercise of the powers conferred by rule 52 of the Himachal Pradesh (Concession) Revised Rules, 1971 read with Himachal Pradesh Government Order No. 13-3/70-SI, dated 13th April, 1971.

I, Jai Singh, General Manager, District Industries Centre, Una, hereby Certify that a sum of Rs. 15,000/- (Rupees fifteen Thousand) only is recoverable as arrears of land revenue from M/s Bishal Brick Kiln Production-cum-sale. Prop. Shri Bodh Raj, Village Raipur Saharon (Una) on account of following in respect of royalty for manufacture/ sale of pucca brick w. e. f. 1987-88 to 1992-93.

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Royalty/Deed rent | } 15000/- up to 1992-93 |
| 2. Surface Rent | |
| 3. Contract Money | |

JAI SINGH

General Manager,
District Industries Centre, Una,
District Una, Himachal Pradesh.

FORM 'L'

(See rule 52)

CERTIFICATE

Una, the 24th March, 1993

No. Ind /U/Brick Kiln/1860.—In exercise of the powers conferred by rule 52 of the Himachal Pradesh (Concession) Revised Rules, 1971 read with Himachal Pradesh Government Order No. 13-3/70 SI, dated 13th April, 1971.

I, Jai Singh, General Manager, District Industries Centre, Una, hereby certify that a sum of Rs. 12500/- (Rupees Twelve Thousand five hundred only) is recoverable as arrears of Lani revenue from M/s Gupta Brick comp. Village Basdehra, Tehsil and District Una on account of following in respect of royalty for manufacture/sale of pucca bricks w.e.f. 1988-89 to 1992-93.

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Royalty/Deed rent. | } 12500/- up to 1992-93 |
| 2. Surface Rent | |
| 3. Contract Money | |

JAI SINGH
General Manager
District Industries Centre Una,
District Una, Himachal Pradesh.

FORM 'L'

(See rule 52)

CERTIFICATE

Una, the 24th March, 1993

No. Ind/U/Brick Kiln/1864.—In exercise of the powers conferred by rule 52 of the Himachal Pradesh (Concession) Revised Rules, 1971 read with Himachal Pradesh Government Order No. 13-3/70-SI, dated 13th April 1971.

I, Jai Singh, General Manager, District Industries Centre, Una, hereby certify that a sum of Rs. 7500/- (Rupees Seven Thousand five hundred) only is recoverable as arrears of land revenue from M/s Shivshakti Brick Gram Udyog Association Village Basdehra, Tehsil and District Una on account of following in respect of royalty for manufacture/sale of pucca bricks w.e.f. 1990-91 to 1992-93.

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Royalty/Deed rent. | } 7500/- up to 1992-93 |
| 2. Surface Rent | |
| 3. Contract Money | |

JAI SINGH,
General Manager,
District Industries Centre, Una,
District Una, Himachal Pradesh.

FORM 'L'

(See rule 52)

CERTIFICATE

Una, the 26th March, 1993

No. Ind/U/Brick Kiln/1844.—In exercise of the power conferred by rule 52 of the Himachal Pradesh (Concession) Revised Rules, 1971 read with Himachal Pradesh Government Order No. 13-3/70-SI, dated 13th April, 1971.

I, Jai Singh, General Manager, District Industries Centre, Una, hereby certify that a sum of Rs. 12500/- (Rupees Twelve Thousand five hundred) only is recoverable as arrears of Land revenue from M/s

Rama Gram Udyog Welfare Village Mobar Bhattali, Tehsil and District Una on account of following in respect of royalty for manufacture/sale of Pucca bricks w.e.f. 1988-89 to 1992-93.

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Royalty/Deed rent | } 12500 - up to 1992-93 |
| 2. Surface Rent | |
| 3. Contract Money | |

JAI SINGH,
General Manager,
District Industries Centre, Una,
District Una, Himachal Pradesh.

FORM 'L'

(See rule 52)

CERTIFICATE

Una, the 24th March, 1993

No. Ind/U/Brick Kiln/1872.—In exercise of the power conferred by rule 52 of the Himachal Pradesh (Concessions Revised Rules, 1971 read with Himachal Pradesh Government Order No. 13-3/70-SI, dated 13th April, 1971.

I, Jai Singh, General Manager, District Industries Centre, Una, hereby certify that a sum of Rs. 7500/- (Rupees seven thousand five hundred) only is recoverable as arrears of land revenue from M/s Satluj Brick Gram Udyog Association Village Basdehra, Tehsil and District Una on account of following in respect of royalty for manufacture/sale of pucca bricks w.e.f. 1990-91 to 1992-93.

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Royalty/ Deed rent | } 7500/- upto 1992-93 |
| 2. Surface Rent | |
| 3. Contract Money | |

JAI SINGH.
General Manager,
District Industries Centre Una,
District Una (H.P.).

FORM 'L'

(See rule 52)

CERTIFICATE

Una, the 24th March, 1993

No. Ind/U/Brick Kiln/1868.—In exercise of the powers conferred by rule 52 of the Himachal Pradesh (Concession) Revised Rules, 1971 read with Himachal Pradesh Government Order No. 13-3/70-SI, dated 13th April, 1971.

I, Jai Singh, General Manager, District Industries Centre, Una, hereby certify that a sum of Rs. 17500/- (Rupees seventeen thousand five hundred) only is recoverable as arrears of land revenue from M/s Shiv Shankar Kuteer Gram Udyog Workers Village P. O. Andora, Tehsil Amb, District Una on account of following in respect of royalty for manufacture/sale of pucca bricks w.e.f. 1986-87 to 1992-93.

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Royalty/Deed rent | } 17500/- upto 1992-93 |
| 2. Surface Rent | |
| 3. Contract Money | |

JAI SINGH,
General Manager,
District Industries Centre Una,
District Una (H.P.).

FORM 'L'

(See rule 52)

CERTIFICATE

Una, the 24th March, 1993

No. Ind/U/Brick Kiln/1856.—In exercise of the powers conferred by rule 52 of the Himachal Pradesh (Concession) Revised Rules, 1971 read with Himachal Pradesh Government Order No. 13-3/70-SI, dated 13th April, 1971.

I, Jai Singh, General Manager, District Industries Centre, Una, hereby certify that a sum of Rs. 12500/- Rupees twelve thousand five hundred) only is recoverable as arrears of land revenue from M/s Himachal Brick Klin Gram Udyog Workers Welfare Association Village Kungrat, Tehsil & District Una, on account of following in respect of royalty for manufacture/sale of pucca bricks w. e. f. 1988-89 to 1992-93.

1. Royalty/Deed rent.
 2. Surface Rent.
 3. Contract Moaey. } 12500/- upto 1992-93

JAI SINGH,
General Manager,
Districts Industries Centre Una,
District Una, (H. P.)

FORM 'L'

(See rule 52)

CERTIFICATE

Una, the 24th March, 1993

No Ind/U/Brick Kiln/1828.—In exercise of the powers conferred by rule 52 of the Himachal Pradesh (Concession) Revised Rules, 1971 read with Himachal Pradesh Government Order No. 13-3/70-SI, dated 13th April, 1971.

I, Jai Singh, General Manager, District Industries Centre, Una, hereby certify that a sum of Rs. 17500/- (Rupees seventeen thousand five hundred) only is recoverable as arrears of land revenue from M/s Bhart Brick Gram Udyog Village Basdehra, Tehsil and District Una, on account of following in respect of royalty for manufacture/sale of pucca bricks w.e.f. 1986-87 to 1992-93 :—

1. Royalty/Deed rent
 2. Surface Rent
 3. Contract Money } 17500/- upto 1992-93

JAI SINGH,
General Manager,
District Industries Centre Una,
District Una, (H.P.).

भाग ३-अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेकन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राजपाल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, कार्डिनेशियल कमिशनर तथा कमिशनर आफ नक्स टैक्स द्वारा अधिसंचित आदेश इत्यादि।

कृषि विभाग

प्रधिसत्त्वनाएँ

गिरजाना-171002, 28 दिसंबर 1992

नम्भा एवं वी (1)-1/75.—भारत के राष्ट्रपति, श्री ओ ० सो० वर्मा, उप निदेशक (कृषि) को संयुक्त निदेशक (कृषि), श्रेणी-१ राजपत्रित पद पर लग्ये ३०००—४५०० के बेतनमान में तदैर आधार पर प्रथम तीन मास की अवधि प्रथमां जब तक संयुक्त निदेशक (कृषि) का पद नियमित स्थ में नहीं नरा जाता, जो भी ५५८ हो, तब ताक पदोन्नति के बहाल भर्त्य आदेश देते हैं।

उक्त पदोन्नति पूर्णतया अस्याई तौर पर की गई है और इस अधिकारी को इमसे इस पद पर निर्वाचित/पदोन्नति/वरीभता का कोई अधिकार प्रदान नहीं होगा।

गान्धीपति महांदय थी ओ० सो० वर्मा का नदर्य पदान्तिति पर उन्हें कुपि निदेशालय ने तैनात करन के महर्पण प्रदेश प्रदान करते हैं।

ਸਿਪਕੀ-171002, 28 ਦਿਸੰਬਰ 1992

सद्या कृषि ० वी-२ (१०) /८७.-विभागीय पदन्त्रिति वर्षिति की मिकारिंग पर भारत के राष्ट्रपति श्री एच० एस० द्वारा, संयुक्त निदेशक (कृषि) का कृषि विभाग में अनिवार्य निदेशक (कृषि) के पद पर अपना एवं प्रभार वार्यक्रम के अन्वर्तन थेंगी-१ राष्ट्रपतिति पद पर ₹ ४५००—६१०० के बीत्रमान में पदन्त्रिति के तंकाल सदर्वादेश देने हैं।

2. श्री एचोएमो दुप्रा, पदोन्नति की दो वर्ष की अवधि तक परिवासी आर्धान रहेंगे।

अदेश द्वारा,
अल्लर मिह

संख्या कृषि० एक० १ (३) /२६-नृज.—इस विभाग की सम-
योगीक अधिकारियता दिनांक १६-११-९२ के क्रम को जारी रखते हुए
रत के तार्ड्युति महोदय “प्रशिक्षण एवं प्रशार कार्यक्रम” के
तर्गत विभिन्न प्रकार के भवन निर्माण कार्य के सचालू व सम्बन्धीय
संचालन हेतु श्री एम० एम० राणा, सहायक भौतिक रक्षण अधिकारी,
दानापुर को कृषि अधिकारियता (बायोगेन), शिमला व कृषि
भियना, भगराहू की प्रहृत मण्डल स्थारोप अधिकारी को तथा
तीव्र व तकनीकी शक्तिया निवेदन करने के सहर्ष आदेश देते

राष्ट्रविनि महोदय उनके कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के भवन निर्माण कार्य को तीन मण्डलों में आवृत्त करने व उनके मण्डल स्वरोग कार्य केव्र भिन्न प्राप्ति से विवरण के मर्ह्या आदेश देते हैं—

मण्डल	प्रभारी	कायंकं व
1	2	3
1. जिम न (मुख्यालय)	कृषि अधिकारी (वायोगम)	ज़िला जिमला, सो नन व बिरामीर।
2. मण्डी (मुख्यालय)	कृषि अधिकारी (भंगरोटू)	ज़िला मण्डी, बिलासपुर, कुल्लु व हमीरपुर।
3. पालमपुर (मुख्यालय पालमपुर)	महायक भ० मंक्षण, अधिकारी, पालमपुर व ऊना।	ज़िला कांडे, चम्बा

आदेश द्वारा/-
हस्ताक्षरित/-

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Shimla-3, the 15th January, 1988

No. 14-27/67-E&T-VI-906.—Whereas it has been reported that the declaration form 'F' (as mentioned below) referred to in sub-section 4 of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act No. 74 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) are declared obsolete/invalid on account of the reasons stated against therein. Now, therefore, pursuant of the provisions of sub-rule 10 of Rule 6 of the Central Sales Tax (Himachal Pradesh) Rules, 1970 the declaration forms bearing number as mentioned below shall be deemed to be obsolete/invalid with effect from the date noted against them :—

Sl. No.	No. of declaration forms 'F' which have been declared invalid/obso- lete	Name and address of the declarer to whom declara- tion form 'F' issued	Name and designation of Assessing Authority who issued form 'F'	Date from which declaration 'F' declared/obsolete invalid
1	2	3	4	5
1.	74051 to 74075	The 'F' forms were found lost in the office of Assessing Authority, Sirmaur at Nahan.	—	17-10-1987

Shimla-3, the 15th January, 1988

No. 14-27/67-E&T-VI-836.—Whereas it has been reported that the declaration form 'C' (as mentioned below) referred to in sub-section 4 of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act No. 74 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) are declared obsolete/invalid on account of the reasons stated against therein. Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-rule 10 of the Rule 6 of the Central Sales Tax (Himachal Pradesh) Rules, 1970 the declaration form bearing number as mentioned below shall be deemed to be obsolete/invalid with effect from the date noted against them :—

Sl. No.	No. of declaration forms 'C' which have been declared invalid obsolete	Name and address of the declarer to whom declara- tion form 'C' issued	Name and designation of Assessing Authority who issued form 'C'	Date from which declaration forms 'C' declared obso- lete/invalid
1	2	3	4	5
1.	Q/3 528115 and Q/3 528116	These forms found in torn condition by the Assessing Authority Solan District Solan.	—	22-12-1987

Shimla-3, the 17th February, 1988

No. 14-27/67-E&T-VI-3450-3540.—Whereas it has been reported that the declaration forms 'C' (as mentioned below) referred to in sub-section (4) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act No. 74 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) are declared obsolete/invalid on account of the reasons stated against therein. Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-rule 10 of Rule 6 of the Central Sales Tax (Himachal Pradesh) Rules, 1970 the declaration forms bearing numbers as mentioned below shall be deemed to be obsolete/invalid with effect from the date noted against them :—

Sl. No.	No. of declaration forms 'C' which have been declared invalid obsolete	Name and address of the declarer to whom declara- tion form 'C' issued	Name and designation of Assessing Authority who issued form 'C'	Date from which declaration forms 'C' declared obsolete/invalid
1	2	3	4	5
1.	Q/3 794526 to Q/3 794550	M/s. New Daily Needs Store, Lakkar Bazar Solan SOL-CST-No. 1144.	Assessing Authority Solan	9-2-1988 (destroyed in fire).

HEM CHAND,
Excise and Taxation Commissioner,
Himachal Pradesh.

मत्स्य पालन विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 6 जनवरी, 1993

संख्या मत्स्य-बा०(६)-१/८८.—भारत के राष्ट्रपति, श्री आर० पी० ० सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य कृषि विकास अधिकारण (एजेंसी), ऊना के प्रतिनियुक्त कार्यकाल को एक वर्ष अर्थात् (दिनांक ११-१०-१९९२ से १०-१०-१९९३ तक) प्रभिन्नत्वकी की मानन्य शर्तों के आधार पर और बड़ाये जाने की मुद्रे स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा,
अत्तर सिंह,
कृषि उत्पादन आयोग, ।

उद्यान विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 10 फरवरी, 1993

सं० उद्यान-ब०(८) १०/४७.—भारत के राष्ट्रपति, श्री यदुवीर मिह, अधीक्षक, घे०-II को अधीक्षक घे०-I वेतनमान रूपये २२००—४०००, उद्यान विभाग में तदर्य आधार पर तकाल प्रभाव से पदोन्नत करने के महर्य आदेश देते हैं।

राष्ट्रपति, श्री यदुवीर मिह को उद्यान निदेशालय में अधीक्षक घे०-I के पद पर तेजानी के भी सहर्य आदेश देते हैं।

हस्ताक्षरित/-
वित्ताधिकर्ता (विकास) ।

DEPARTMENT OF INDUSTRIES
NOTIFICATION
Shimla-2, the 29th January, 1988

No. Udyog (Ka) 3-2/81-II.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to add the following clause under Rule 22(2) of Procedure and Rules for the purchase of Stores by all Departments and Offices of the Government of Himachal Pradesh :—

(c) "if any firm/firms (local unit) manufacturer, some more items at a later stage i.e. after opening of the tenders, such firm(s) may also be considered for the award of parallel rate contract with the prior approval of the Government."

By order,
O. P. YADAV,
Secretary.

भाग ४—स्थानीय स्वायत शासन, म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती रोज़ विभाग

दिनांक १०-५-१९९३ को मुंवह १०.०० बजे हाजिर होकर पेश कर सकता है वरना उपरोक्त अधिकारियों की जन्म तिथि दर्ज करने वारे सम्बन्धित मन्त्रिव, पंचायत को उपरोक्त बनाई गई तिथि दर्ज करने वारे आदेश दे दिये जायेंगे।

अ.ज दिनांक २४-२-१९९३ को मेरे हस्ताक्षर व मोश्र कार्यालय से जारी हुआ।

मोहर ।

बी० आर० जम्बाल,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट,
ऊना, जिला ऊना (घे० प्र०)।

व अदान्त श्री बी० आर० जम्बाल, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री परमेश्वरी दाम गर्भा मुफ्त अनन्द शम शर्मा, निवासी बडेगह, नड्सील बंगाणा, जिला ऊना, (घे० प्र०)।

वनाम

आम जनता

दरबारात जेर धारा १३ (३) जन्म एवम् मृत्यु रजिस्ट्रीकरण एक्ट, १९६९।

दरबारात जेर धारा १३ (३) जन्म एवम् मृत्यु रजिस्ट्रीकरण एक्ट, १९६९।

श्री मुरेश चंद्रवरी मुपुव अमृतमर्था गम, निवासी सामन, तहसील व जिला ऊना ने इस कार्यालय में गुजारिया की है कि उनके पद श्री दिनेश तथा विभाल का जन्म दिनांक २२-५-८८ व १-१०-१९८९ को हुआ है नेत्रिन उनकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वमाध्यारण को इसे इस्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी अधिकारी को कोई उज्जर या एनराज हो तो वह

थ्रम विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 20 मार्च, 1993

संख्या ११-२/९३ (लंब) आई० डी०.—अधिहोस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि श्री दिनेश मैहता मारफत श्री पी० को कुकरेजा, मकान नं० ३३४६, सेक्टर १९-बी, चण्डीगढ़ और प्रबन्ध निदेशक, मै० हिम टैक्नो फोरज प्रा० लि०, गांव व लाकवर वही, जिला सोलन तथा प्रबन्ध निदेशक, मै० हिम फोरज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मकान नं० ३९, सेक्टर २८-ए, चण्डीगढ़ के मध्य नीचे दिए गये विषय पर श्रीयोगिक विवाद है;

और श्रीयोगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा १२(४) क अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत को गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा १२ की उप-धारा (५) के अधीन विचार करने के पश्चात अधिहोस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि यह भालना श्रम व्यायालय को अधिनियम के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या १९-८/८९-अम (लंज), दिनांक ७ सितम्बर, १९९२ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिहोस्ताक्षरी श्रीयोगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १४) की धारा १० की उप-धारा (१) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा ७ के अधीन गठित श्रम व्यायालय, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गये विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है :—

"कि क्या श्री दिनेश मैहता सुपुत्र श्री एम० एल० मैहना, इलैक्ट्रो-शिक्षन का प्रबन्ध निदेशक, मै० हिम टैक्नो फोरज प्रा० लि० एवं मै० हिम फोरज इंडिया प्रा० लि०, वही, जिला सोलन, (हे० प्र०) द्वारा विना नोटिस व बिना जारी कारेवाही के नौकरी से निकालना उचित व न्याय संगत है? यदि नहीं तो श्री दिनेश मैहना, इलैक्ट्रो-शिक्षन किस बेतन, सवा लाभ व राहन का पात्र है।"

हस्ताक्षरित/-
अमानुकृत ।

भाग ५—वैयक्तिक अधिसूचनाए० और विज्ञापन

व अदान्त श्री बी० आर० जम्बाल, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री मुरेश चंद्रवरी सुपुत्र अमृतमर्था गम, निवासी सामन, तहसील व जिला ऊना (घे० प्र०)।

वनाम

आम जनता

दरबारात जेर धारा १३ (३) जन्म एवम् मृत्यु रजिस्ट्रीकरण एक्ट, १९६९।

श्री मुरेश चंद्रवरी मुपुव अमृतमर्था गम, निवासी सामन, तहसील व जिला ऊना ने इस कार्यालय में गुजारिया की है कि उनके पद श्री दिनेश तथा विभाल का जन्म दिनांक २२-५-८८ व १-१०-१९८९ को हुआ है नेत्रिन उनकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वमाध्यारण को इसे इस्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी अधिकारी को कोई उज्जर या एनराज हो तो वह

थ्रम विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 20 मार्च, 1993

संख्या ११-२/९३ (लंब) आई० डी०.—अधिहोस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि श्री दिनेश मैहता मारफत श्री पी० को कुकरेजा, मकान नं० ३३४६, सेक्टर १९-बी, चण्डीगढ़ और प्रबन्ध निदेशक, मै० हिम टैक्नो फोरज प्रा० लि०, गांव व लाकवर वही, जिला सोलन तथा प्रबन्ध निदेशक, मै० हिम फोरज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मकान नं० ३९, सेक्टर २८-ए, चण्डीगढ़ के मध्य नीचे दिए गये विषय पर श्रीयोगिक विवाद है;

और श्रीयोगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा १२(४) क अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत को गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा १२ की उप-धारा (५) के अधीन विचार करने के पश्चात अधिहोस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि यह भालना श्रम व्यायालय को अधिनियम के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या १९-८/८९-अम (लंज), दिनांक ७ सितम्बर, १९९२ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिहोस्ताक्षरी श्रीयोगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १४) की धारा १० की उप-धारा (१) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा ७ के अधीन गठित श्रम व्यायालय, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गये विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है :—

"कि क्या श्री दिनेश मैहता सुपुत्र श्री एम० एल० मैहना, इलैक्ट्रो-शिक्षन का प्रबन्ध निदेशक, मै० हिम टैक्नो फोरज प्रा० लि० एवं मै० हिम फोरज इंडिया प्रा० लि०, वही, जिला सोलन, (हे० प्र०) द्वारा विना नोटिस व बिना जारी कारेवाही के नौकरी से निकालना उचित व न्याय संगत है? यदि नहीं तो श्री दिनेश मैहना, इलैक्ट्रो-शिक्षन किस बेतन, सवा लाभ व राहन का पात्र है।"

हस्ताक्षरित/-
अमानुकृत ।

श्री परमेश्वरी दाम गार्मी सुपुत्र अनन्त राम शर्मा, निवासी बडेशहार, हसीन वनाणा, जिला ऊना ने इम कार्यालय में गुजारिश की है कि उसके त्रिमहें कुमार शर्मा का जन्म दिनांक 7-11-1989 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

अतः मर्वंसाधारण को इस इष्टहार द्वारा सूचित किया जाना है कि इस वारे यदि इसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 10-5-1993 को सबह 10 बजे हाजिर होकर पेश कर मकान है वरना उपरोक्त व्यक्ति की जन्म तिथि दर्ज करने वारे मर्वंसाधारण भवित्व, पंचायत को उपरोक्त बताई गई तिथि दर्ज करने वारे आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 24-2-93 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय से जारी हुआ।

मोहर।

बी० आर० जम्बाल,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट,
ऊना, जिला ऊना (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री बी० आर० जम्बाल, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना
जिला ऊना (हि० प्र०)

श्री जगत राम सुपुत्र सुरत राम, निवासी मैन्सोवाल, मर्व-नहसील हरोली, जिला ऊना (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

दरबास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण ऐक्ट, 1969.

श्री जगत राम सुपुत्र सुरत राम, निवासी मैन्सोवाल, मर्व-नहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसकी पुत्री सीमा देवी का जन्म दिनांक 10-5-1987 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

अतः मर्वंसाधारण को इस इष्टहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस वारे यदि इसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 10-5-1993 को सबह 10 बजे हाजिर होकर पेश कर मकान है वरना उपरोक्त व्यक्ति की जन्म तिथि दर्ज करने वारे मर्वंसाधारण भवित्व, पंचायत को उपरोक्त बताई गई तिथि दर्ज करने वारे आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 24-2-93 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय से जारी हुआ।

मोहर।

बी० आर० जम्बाल,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना;
जिला ऊना (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री बी० आर० जम्बाल, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना,
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

श्री यशवन्त सुपुत्र श्री रघवीर मिह, निवासी भड़ियारां, मर्व-नहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरबास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण ऐक्ट, 1969.

श्री यशवन्त मिह सुपुत्र श्री रघवीर मिह, निवासी भड़ियारां, मर्व-नहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसके मानजे श्री प्रदीप कुमार सुपुत्र श्री रामलाल श्री कुमार सुपुत्र सुभाष चन्द्र व श्रीशंकर कुमार सुपुत्र श्री रामलाल का जन्म दिनांक क्रमशः 6-6-1987, 23-10-1988 तथा 12-3-88 को हुआ है लेकिन उनकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वंसाधारण को इस इष्टहार द्वारा सूचित किया जाना है कि इस वारे यदि इसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो दिन क 10-5-1993 को सुबह 10 बजे हाजिर होकर पेश कर मकान है वरना उपरोक्त व्यक्तियों की जन्म तिथि दर्ज करने वारे मर्वंसाधारण सूचित, पंचायत को उपरोक्त बताई गई तिथियों दर्ज करने वारे आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 24-2-1993 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय से जारी हुआ।

मोहर।

बी० आर० जम्बाल,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना,
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री ध्रुव विश्वास, उप-मण्डलाधिकारी, शिमला (गा०)
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

श्री नरिंद्र कुमार नन्दा पुत्र श्री लेख राज नन्दा, निवासी धूट्ट, गांव मजठाई, तहसील व जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरबास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण ऐक्ट, 1969.

श्री नरिंद्र कुमार नन्दा पुत्र श्री लेख राज नन्दा, निवासी धूट्ट, ग्राम मजठाई, तहसील व जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में उपरोक्त ऐक्ट के अन्तर्गत अपनी व प्रपने बच्चों की जन्म तिथि व मृत्यु दर्ज करवाने वारे प्रारंभन-पत्र गुजारा है। श्री नरिंद्र कुमार नन्दा उपरोक्त के अनुसार उनकी अपनी व पत्नी व बच्चा की जन्म तिथि निम्नलिखित है—

1. श्री नरिंद्र कुमार नन्दा जन्म तिथि 2-5-1945, 2. श्रीमती सुदेश पत्नी। श्री नरिंद्र कुमार की जन्म तिथि 9-8-1946, 3. श्री असीम नन्दा पुत्र मृत्यु की तिथि 31-5-1991, 4. सनील नन्दा पुत्र की मृत्यु तिथि 3-2-1993, 5. कु० नीरू नन्दा पुत्री जन्म तिथि 2-12-1974, 6. कु० मीरू नन्दा पुत्री जन्म तिथि 9-12-1977 है।

अतः मर्वंसाधारण को इस इष्टहार द्वारा सूचित किया जाता है कि जिनको भी उक्त जन्म तिथि व मृत्यु की तारीख दर्ज करवाने वारे किसी भी प्रकार कोई शंक ही नहीं तो वे इस न्यायालय में मिति 18-5-1993 तक अपने प्रारंभन-पत्र देने वाले हैं। यदि कोई भी प्रारोप उक्त तिथि तक इस न्यायालय में प्राप्त न हुआ तो ऐसा माना जाएगा कि श्री नरिंद्र कुमार की अपनी व उनके बच्चों की जन्म तिथि व मृत्यु की तारीख नहीं है और वह तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज की जाएगी।

आज दिनांक 16-4-1993 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

ध्रुव विश्वास,
उप-मण्डलाधिकारी (गा०),
शिमला, जिला शिमला (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री भलोक सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर

मुकदमा नं० 18-92

तारीख पेशी 30-4-93

नाम मुकदमा : विजय सिंह बनाम मर्वंसाधारण

किसी मुकदमा : प्रारंभन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण ऐक्ट, 1969.

श्री विजय सिंह पुत्र राम सिंह, निवासी भवारना, तहसील पालमपुर ने प्रारंभन-पत्र दिया है कि उनकी लड़की कुशल बन्धु का

जन्म 15-1-86 को हुआ है और उसका नाम गाम पंचायत रमेहड़ में दर्ज ही हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को यूनिट फिल्म जाता है कि जिस किसी को इस जन्म पंजीकरण के प्रति आपत्ति हो तो वह भ्रातालतन या बकालतन दिनांक 30-4-93 प्रातः 10 बजे हाजर ब्रातालत आकर पैरवी मुझ्हना करें अन्यथा जन्म पंजीकरण की इजाजत दे दी जाएगी।

आज दिनांक 27-3-93 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर यात्राल से जारी किया गया।

मोहर।

मलोक फ़िल्म,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हिंग्रो)।

भाग 6—भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन

LAW DEPARTMENT

(LEGISLATIVE WING)

NOTIFICATIONS

Shimla-2, the 5th February, 1988

No. LLR-E(9)8/87-Legis.—The Delhi Municipal Corporation (Second Amendment) Ordinance, 1987 (Ordinance No. 9 of 1987) and the Delhi Administration (Amendment) Ordinance, 1987 (Ordinance No. 10 of 1987) recently promulgated by the President of India, which have already been published in the Gazette of India, Extra Ordinary Part-II, Section-I, dated the 24th December, 1987 are hereby republished in the Rajpatha, Himachal Pradesh, for general information of the public.

By order,
Sd/-
Secretary.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

New Delhi, the 24th December, 1987/Pausa 3, 1909 (Saka)

THE DELHI MUNICIPAL CORPORATION (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE, 1987

No. 9 OF 1987

Promulgated by the President in the thirty-eighth Year of the Republic of India.

An ordinance further to amend the Delhi Municipal Corporation Act, 1957.

Whereas Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 123 of the Constitution, the President is pleased to promulgate the following ordinance:—

1. *Short title and commencement.*—(1) This Ordinance may be called the Delhi Municipal Corporation (Second Amendment) Ordinance, 1987.

(2) It shall come into force at once.

2. *Amendment of section 4.*—In the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957) in sub-section (1) of section 4, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, extend for reasons to be specified in the notification, the term of office of all the councillors and aldermen by such period not exceeding one year at a time as it thinks fit, so, however, that the total period so extended shall not exceed three years.”

R. VENKATARAMAN,
President.

C. RAMAN MENON,
Additional Secretary to the Government of India.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

New Delhi, the 24th December, 1987/Pausa 3, 1909 (Saka)

THE DELHI ADMINISTRATION (AMENDMENT) ORDINANCE, 1987

No. 10 OF 1987

Promulgated by the President in the thirty-eighth Year of the Republic of India.

An ordinance further to amend the Delhi Administration Act, 1966.

Whereas Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 123 of the Constitution, the President is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. *Short title and commencement.*—(1) This ordinance may be called the Delhi Administration (Amendment) Ordinance, 1987.

(2) It shall come into force at once.

2. *Amendment of section 10.*—In section 10 of the Delhi Administration Act, 1966 (19 of 1966), for the words “Provided that the said period”, the following shall be substitute, namely:—

“Provided that the Central Government may, by notification, in the Official Gazette, extend the said period for reasons to be specified in the notification by such period not exceeding one year at a time as it thinks fit, so, however, that the total period so extended shall not exceed three years:

Provided further that the said period or extended period.”

R. VENKATARAMAN,
President

C. RAMAN MENON,
Additional Secretary to the Government of India.

Legislation (English) Section

Shimla-171002, 30th June, 1992

No. LLR-E (9)-3/91-Legislation.—The Special Court (Trial of Offences Relating to Transactions in Securities) Ordinance, 1992 (Ordinance No. 10 of 1992) which have been already published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, section I, dated 6th June, 1992 are hereby republished in the Rajpatha, Himachal Pradesh for general information of the public.

By order,
Sd/-
Secretary.

**MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND
COMPANY AFFAIRS
(Legislative Department)**

New Delhi, the 6th June, 1992/Jaistha 16, 1914 (Saka)
**THE SPECIAL COURT (TRIAL OF OFFENCES
RELATING TO TRANSACTIONS IN SECURITIES)
ORDINANCE, 1992**

No. 10 of 1992

Promulgated by the President in the Fourty-third Year
of the Republic of India

An Ordinance to provide for the establishment of a
Special Court for the trial of offences relating to
transactions in securities and for matters connected
therewith or incidental thereto.

WHEREAS Parliament is not in session and the President
is satisfied that circumstances exist which render it
necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred
by clause (1) of article 123 of the Constitution, the
President is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. *Short title and commencement.*—(1) This Ordinance
may be called the Special Court (Trial of Offences Relat-
ing to Transactions in Securities) Ordinance, 1992.

(2) It shall come into force at once.

2. *Definitions.*—In this Ordinance, unless the context
otherwise requires,—

(a) "Code" means the Code of Criminal Procedure,
1973 (2 of 1974);

(b) "Custodian" means the custodian appointed under
sub-section (1) of section 3;

(c) "securities" includes—

(i) shares, scrips, stocks, bonds, debentures, debenture
stock, units of the Unit Trust of India or any
other Mutual Fund or other marketable securities
of a like nature in or of any incorporated company
or other body corporate;

(ii) Government securities; and

(iii) rights or interests in securities;

(d) "Special Court" means the Special Court estab-
lished under sub-section (1) of section 5.

3. *Appointment and functions of custodian.*—(1) The
Central Government may appoint one or more Custo-
dian as it may deem fit for the purposes of this Ordin-
nance.

(2) The Custodian may, on being satisfied on infor-
mation received that any person has been involved in
any offence relating to transactions in securities after
the first day of April, 1991 and on and before the
promulgation of this Ordinance, notify the name of
such person in the Official Gazette.

(3) Notwithstanding anything contained in the Code,
on and from the date of notification under sub-section
(2), any property, moveable or immoveable, or both
belonging to any person notified under that sub-section
shall stand attached simultaneously with the issue of
the notification.

(4) The property attached under sub-section (3) shall
be dealt with by the Custodian in such manner as the
Special Court may direct.

(5) The Custodian may take assistance of any person
for discharging his duties under this section.

4. *Contracts entered into fraudulently may be cancel-
led.*—If the Custodian is satisfied, after such inquiry as
he may think fit, that any contract or agreement entered
into at any time after the first day of April, 1991 and on
and before the proclamation of this Ordinance in relation
to any property of the person notified under sub-
section (2) of section 3 has been entered into fraudulently
or to defeat the provisions of this Ordinance, he
may cancel such contract or agreement and on such
cancellation such property shall stand attached under
this Ordinance:

Provided that no contract or agreement shall be can-
celled except after giving to the parties to the contract or
agreement a reasonable opportunity of being heard.

5. *Establishment of Special Court.*—(1) The Central
Government shall, by notification in the Official Gazette,
establish a court to be called Special Court.

(2) The Special Court shall consist of a sitting Judge
of the High Court nominated by the Chief Justice of the
High Court within the local limits of whose jurisdiction the
Special Court is situated, with the concurrence of the
Chief Justice of India.

6. *Cognizance of cases by Special Court.*—The
Special Court shall take cognizance of or try such
cases as are instituted before it or transferred to it as
hereinafter provided.

7. *Jurisdiction of Special Court.*—Notwithstanding
anything contained in any other law, any prosecution in
respect of any offence referred to in sub-section (2) of
section 3 shall be instituted only in the Special Court and
any prosecution in respect of such offence pending in
any court shall stand transferred to the Special Court.

8. *Jurisdiction of Special Court as to joint trials.*—
The Special Court shall have jurisdiction to try any
person concerned in the offence referred to in sub-
section (2) of section 3 either as a principal, conspirator
or abettor and all other offences and accused persons
as can be jointly tried therewith at one trial in accord-
ance with the Code.

9. *Procedure and powers of Special Court.*—(1) The
Special Court shall, in the trial of such cases, follow the
procedure prescribed by the Code for the trial of warrant
cases before a magistrate.

(2) Save as expressly provided in this Ordinance, the
provisions of the Code shall, in so far as they are not
inconsistent with the provisions of this Ordinance, apply
to the proceedings before the the Special Court, and for
the purposes of the said provisions of the Code, the
Special Court shall be deemed to be a Court of Session
and shall have all the powers of a Court of Session, and
the person conducting a prosecution before the Special
Court shall be deemed to be a Public Prosecutor.

(3) The Special Court may pass upon any person
convicted by it any sentence authorised by law for the
punishment of the offence of which such person is con-
victed.

10. *Appeal.*—(1) Notwithstanding anything in the
Code, an appeal shall lie from any judgment, sentence or
order, not being interlocutory order, of the Special
Court to the Supreme Court both on facts and on law.

(2) Except as aforesaid, no appeal or revision shall
lie to any court from any judgment, sentence or order
of the Special Court.

(3) Every appeal under this section shall be preferred
within a period of thirty days from the date of any
judgment, sentence or order of the Special Court:

Provided that the Supreme Court may entertain an
appeal after the expiry of the said period of thirty
days if it is satisfied that the appellant had sufficient
cause for not preferring the appeal within the period
of thirty days.

11. *Discharge of liabilities.*—(1) Notwithstanding
anything contained in the Code and any other law for the
time being in force, the Special Court may make such
order as it may deem fit directing the Custodian for the
disposal of the property under attachment.

(2) The following liabilities shall be paid or discharged
in full, as far as may be, in the order as under:—

(a) all revenues, taxes, cesses and rates due from the
persons notified by the Custodian under sub-
section (2) of section 3 to the Central Govern-
ment or any State Government or any local
authority;

(b) all amounts due from the person so notified by
the Custodian to any bank or financial institu-
tion;

(c) any other liability as may be specified by the
Special Court from time to time.

12. *Protection of action taken in good faith.*—(1) No
suit, prosecution or other legal proceeding shall lie
against the Central Government or the Custodian for
anything which is in good faith done or intended to be
done under this Ordinance.

(2) No suit or other legal proceeding shall lie against the Central Government or any of its officers or other employees for any damage caused or likely to be caused by any thing which is in good faith done or intended to be done under this Ordinance.

13. *Ordinance to have over-riding effect.*—The provisions of this Ordinance shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law, other than this Ordinance, or in any decree or order of any court, tribunal or other authority.

14. *Powers to make rules.*—(1) The Central Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Ordinance.

(2) Every rule made by the Central Government under this Ordinance shall be laid, as soon as may be

after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

R. VENKATARAMAN,
President.

K. L. MOHANPURIA,
Secretary to the Government of India.

भाग 7— सार्वतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं

शून्य

अनुपूरक

शून्य

भाग 1

**HIMACHAL PRADESH ADMINISTRATIVE
TRIBUNAL AT SHIMLA-171002**

NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th April, 1993

No. HPAT-D (7)-1/90.—It is hereby notified for general information that the 14th April, 1993 shall be observed as Public Holiday in this Tribunal as also in the Sub-Offices of Mandi and Dharamshala on account of Birth anniversary of Dr. B. R. Ambedkar.

By order,
Sd/-
Registrar.

कार्यालय विभाग
अधिसूचना

शिमला-171002, 6 अप्रैल, 1993

संख्या का (नि-1)-बो 0 (2)-2/90-II.—भारत के राष्ट्रपति, विभागीय प्रदेश नियन्त्रित समिति की मिकारिशों पर और हिमाचल प्रदेश सचिवालय के नियन्त्रित स्वाइं अनुभाग अधिकारियों को अवर सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार के पद पर ₹ 3000-100-4000-125-4500 के बतनामात में ₹ 4000/- प्रतिमाह विशेष बतन सहित, प्रदोन्नति/नियुक्ति करने के तत्काल से सहज आदेश करते हैं—

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. श्री बरकत राम मैहता | } ये तीनों अधिकारी पूर्णतया |
| 2. श्री गोपाल सिंह | |
| 3. श्री राजेन्द्र कुमार चौहान | अस्थाई तार पर पहले ही अवर |
| 4. श्री पदम राज गुप्ता | सचिव के पद पर प्रदोन्नति है। |
| 5. श्री बाल मुकन्द | |

उपरोक्त सभी अधिकारी दो वर्ष की परख अवधि पर रहेंगे।
ये पदोन्नतियां नियन्त्रित याचिकाओं पर होने वाले अन्तिम नियंत्रण पर निर्भर होंगी:—

क्रमांक 0 से 0 न्यायालय जहां याचिका याचिका संख्या वाली एवं प्रतिवादी दायर है

1	2	3	4
1. उच्चतम न्यायालय, भारत श्री 04.0 स 02615/ श्री गुरुलाल नेही 87 एवं सी 04.0 एन 0 एवं अन्य विद्व 10114/87.			श्री भगत राम कपरेट एवं अन्य।

आदेश द्वारा,
एस 0 के 0 चौहान,
मुख्य सचिव।